चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 10 जनवरी–16 जनवरी 2011

मूल्य 5 रुपये

और लाल होगी बंगाल की धरती

पेज-3

खर्चा रुपया काम चवन्नी

पेज-4

जन जागरण के नए प्रयोग की दस्तक

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

यह गूजर नहीं किसान आंदोलन है

गूजर आंदोलन कर रहे हैं. क्या यह आंदोलन आकस्मिक है. ये किसान सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं. गूजरों को गांव में रहने वाले राजपूतों का समर्थन क्यों मिल रहा है. गांव में रहने वाले उच्च जाति के लोग भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर क्यों आवाज़ उठाने लगे हैं. क्या वजह है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग शहर के व्यापारी नहीं करते. कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदलने का वक़्त आ गया है. विकास के मायने को नया रूप देने का वक़्त आ गया है.

मनीष कुमार

भारतीय लोकतंत्र का यह अजीब चेहरा है. देश के किसानों को जब भी कोई बात सरकार तक पहुंचानी होती है, उन्हें आंदोलन करना पड़ता है. वहीं देश के बड़े-बड़े उद्योगपति सीधे मंत्रालय जाकर नियम-क़ानून बदल कर करोड़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं. लोकतंत्र से मिलने वाले अवसर और फ़ायदे से भारत की बहुसंख्यक आबादी बहुमत से लगातार दूर होती जा रही है. भारत किसानों का देश है. वह ग़रीब है. सरकार की योजनाओं एवं नीतियों से फ़ायदा मिलना तो दूर, उल्टे नुकसान हो रहा है. किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन तब होता है, जब उसकी संस्थाओं के ज़रिए लोगों के बुनियादी सवालों, उनकी समस्याओं का हल निकलना बंद हो जाता है. जब समस्याओं का हल सरकारी तंत्र न कर सके या फिर सरकारी तंत्र की वजह से समस्याएं पैदा होती हों, तब आंदोलन होता है. किसी भी आंदोलन में जनता का समर्थन तब मिलता है, जब पेट में पीड़ा होती है. वैसे भारत के लोग बड़े ही संतोषी हैं. इतनी महंगाई के बावजूद आंदोलन नहीं करते हैं. फिर अगर गूजर आंदोलन कर रहे हैं तो ज़रूर कोई वजह होगी.

गूजरों का आंदोलन कोई आकस्मिक आंदोलन नहीं है. वे किसी हत्याकांड के विरोध में आंदोलन नहीं कर रहे हैं. गूजर कई सालों से रोज़ी-रोटी के सवाल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. यह आंदोलन दिल्ली से सटे इलाकों और राजस्थान में फैला है. गूजर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग यह है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण. अब सवाल यह है कि गूजर अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर सरकारी नौकरियां करना क्यों चाहते हैं. सरकार को लगता है कि अगर गूजरों की मांग मान ली गई तो देश की दूसरी जातियां भी आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर सकती हैं. यही वजह है कि सरकार इसे राजनीतिक रंग देने में लगी है. गूजरों के आंदोलन को राजनीति के चश्मे से देखना ग़लत है.

गूजर मुख्यत: किसान हैं. उनका जीवन पशुपालन पर निर्भर है. पशुपालन और दूध ही उनकी आय का मुख्य ज़रिया है. सदियों से ये लोग गाय, बकरी और भेड़ पालते रहे, उनका दूध बेचते रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे पशुपालन का भैंसीकरण हो गया. मतलब यह कि भैंस का दूध बाज़ार में छा गया. 1950 से पहले हमारे देश में लोग भैंस नहीं पालते थे. 1950 के बाद से एडीडीपी (एग्रीकल्चर एंड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम) की मदद से मिल्क को-ऑपरेटिव का आंदोलन शुरू हुआ. उसी समय दूध की गुणवत्ता मापने का जो मापदंड बना, उसने पशुपालन और दूध के बाज़ार की पूरी दिशा बदल दी. दूध की गुणवत्ता को फैट परसेंटेज से जोड़ दिया गया. मतलब यह कि जिस दूध में जितना ज्यादा फैट, उतना ही बेहतर दूध. मज़े की बात यह है कि फैट को गुणवत्ता का मापदंड इसलिए बनाया गया, क्योंकि इसे लैक्टोमीटर से आसानी से मापा जा सकता है. हमारे अधिकारियों को दूध की गुणवत्ता मापने का सबसे आसान तरीका यही लगा. पांचवें दशक के बाद से जब यह मिल्क को-ऑपरेटिव आंदोलन चला तो उसी के साथ दूध का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चाय में होने लगा. चाय के अंदर अगर दूध ज़्यादा गहरा हो तो चाय अच्छी मानी जाती है. इन दोनों वजहों से गाय के दूध से ज़्यादा भैंस के दूध की खपत होने लगी. बाज़ार में भैंस के दूध की मांग बढ़ी. देश में पशुपालन के मायने बदल गए. पशुपालन का अर्थ सिर्फ़ भैंस पालना रह गया. इससे बहुत बड़ा बदलाव आया. गाय की तरह भैंस खेतों में नहीं चरती. इससे उसका काम नहीं चलता. गांवों में गाय को ख़रीद कर चारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. इस वजह से दूध के लिए गूजरों को अब खेत से लाए गए चारे और बाज़ार से खरीदे गए चारे की ज़रूरत पड़ने लगी. अब पिछले 25 सालों में भैंसों के खाने के सामानों (चारा और अन्य उत्पाद) पर नज़र डालें तो भैंसों पर किए गए ख़र्च और दूध की कीमत में काफी अंतर था. कुछ सालों तक यह एक और तीन के अनुपात में रहा. मतलब भैंसों के खाने पर अगर कोई एक रुपये ख़र्च करता तो उसे तीन रुपये का दूध मिलता था. गूजरों को फ़ायदा होता था, लेकिन पिछले 10 सालों में तस्वीर बदल गई. भैंस के चारे की कीमत बढ़ गई. इसकी कई वजहें हैं. खेती का तरीका बदला और फ़सलों में भी बदलाव आया. चारे का उत्पादन कम होता गया. साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई. वहीं बाज़ार में फैट की इतनी मांग बढ़ती गई कि किसानों ने भैंसों को फूड कांस्नट्रेट (ऐसा खाना जिससे ज्यादा फैट का निर्माण होता है) खिलाना शुरू कर दिया. फूड कांस्नट्रेट को खली से बनाया जाता है. जब सरसों या किसी बीज से तेल निकाला जाता है तो तेल निकालने के बाद जो बच जाता है, उसे खली कहते हैं. जब तेल महंगे हुए तो खली की कीमत बढ़ गई. इस तरह भैंसों को जो खिलाया जाता था, वह कई गुना महंगा हो गया, लेकिन सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं की वजह से दूध की कीमत नहीं बढ़ने दी. दूसरी परेशानी यह हुई कि बाज़ार में सिंथेटिक (नकली) दूध का अंबार लग गया, जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर दूध की जो कीमत होनी चाहिए, वह हुई नहीं. साथ ही घी का कारोबार भी गूजरों के लिए मुसीबत हो गया. नकली घी का कारोबार असली घी के कारोबार से कई गुना ज़्यादा है. इसने भी दूध की कीमत नहीं बढ़ने दी. यही वजह है कि पिछले दस सालों से गूजरों को नुकसान होने लगा. आमदनी कम होने की वजह से गूजरों की चिंता बढ़ने लगी. उन्हें अब लगने लगा है कि अपने पारंपरिक व्यवसाय की वजह से वे ग़रीब होते चले जा रहे हैं. अब इससे उनका गुज़ारा नहीं होने वाला है.

गूजर आंदोलन को अगर सिर्फ़ जातीय व आरक्षण के चश्मे से देखा गया तो भयंकर भूल हो जाएगी. आज गूजर आंदोलन कर रहे हैं, कल दूसरे किसान आंदोलन करेंगे. आज वे रेल और सड़क जाम कर रहे हैं, कल हथियार भी उठा सकते हैं.

ऐसे मौके पर जब कोई राजनीतिक दल या नेता अच्छे भविष्य के सपने दिखाएगा तो ग़रीबी से जूझ रहे किसानों का समर्थन मिलना लाज़िमी है. अब गूजरों को लग रहा है कि उनके अपने व्यवसाय में फ़ायदा नहीं है और नेता उन्हें नौकरियों में आरक्षण का लालच भी दे रहे हैं. ऐसे में गूजर समुदाय को लग रहा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

वर्तमान चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह को अगस्त में ही रिटायर होना था, लेकिन चूंकि उनका कोई उत्तराधिकारी अब तक नहीं मिल सका है, इसलिए वह अभी भी इस पद पर बने हुए हैं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

भ्रष्ट बाबू और सरकारी निष्क्रियता

केंद्रीय सतर्कता आयोग की 2009 की वार्षिक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि कैसे बहुत सारे भ्रष्ट बाबू ख़ुद पर लगे आर्थिक दंड का भुगतान करने से बच गए और इसकी वजह रही सरकारी निष्क्रियता. रिपोर्ट के मुताबिक़, 2009 में पैनल ने भ्रष्टाचार से संबंधित 5783 शिकायतों की जांच की, लेकिन सिर्फ़ 42 फ़ीसदी दागी बाबुओं को ही दंडित किया जा सका. दिलचस्प रूप से इन दोषियों में वे बाबू भी हैं, जो पी चिदंबरम, ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के मंत्रालयों से जुड़े हैं. सूत्रों के मुताबिक़, वित्त और रेल मंत्रालय भ्रष्ट बाबुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के मामले में सबसे पीछे रहे. वित्त मंत्रालय तो सीवीसी द्वारा 6 महीने पहले की गई अनुशंसा के बाद भी 331 बाबुओं के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सका है. इस तरह के उदाहरण रेल और गृह मंत्रालय में भी देखने को मिले. रिपोर्ट में इस बात का भी ज़िक्र है कि कैसे एक संगठन स्वयं भ्रष्ट बाबुओं के ख़िलाफ़ अनुशंसित कार्रवाई को शिथिल बना देता है.

कुमार के ख़िलाफ़ कार्रवाई

अंततः पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासक शिवराज पाटिल ने चंडीगढ़ के विवादास्पद वित्त सचिव संजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है. कुमार 1987 बैच और पंजाब कैडर के अधिकारी हैं और केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर थे. कुमार पर गैर कानूनी रूप से एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के 621 करोड़ रुपये रोकने का आरोप था. उन पर चंडीगढ़ के एक गोल्फ क्लब का आजीवन सदस्य बनने के लिए कागजातों में फ़र्ज़ीवाड़ा करने का भी आरोप था. विश्लेषकों के मुताबिक़, कुमार के खिलाफ कार्रवाई में देरी की वजह यह थी कि वह चंडीगढ़ में पदस्थापित होने के बावजूद केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे. उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले इस मामले में गृह मंत्रालय को भी शामिल करना ज़रूरी था. जब मंत्रालय ने उनके ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया तो तय समय सीमा के भीतर वह जवाब नहीं दे सके.

एनएचएआई चेयरमैन की खोज

कुछ पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में चेयरमैन का पद संबंधित अधिकारी के लिए भाग्यशाली नहीं होता. यूपीए–1 की सरकार में जब टी आर बालू मंत्री थे, तब इस संगठन ने दो साल के भीतर पांच चेयरमैन देखे. सबसे छोटा कार्यकाल जे एस मैनी का रहा. सिर्फ़ दो महीने. वर्तमान चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह को अगस्त में ही रिटायर होना था, लेकिन चूंकि उनका कोई उत्तराधिकारी अब तक नहीं मिल सका है, इसलिए वह अभी भी इस पद पर बने हुए हैं. जब नए चेयरमैन की खोज शुरू हुई तो पता चला कि उस समय के पथ सचिव ब्रह्मदत्त ने भी इस पद के लिए आवेदन किया था, जो ख़ुद चयन समिति के सदस्य थे. तबसे नए चेयरमैन की वह खोज रुकी हुई है. बहरहाल एनएचएआई को अभी इंतजार करना पड़ेगा.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

गुप्ता बन सकते हैं निदेशक

पी वी गुप्ता जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक का पद संभाल सकते हैं. उन्हें रश्मि चौधरी की जगह पर नियुक्त किया जा सकता है.

नारायण गृह मंत्रालय में

वर्ष 1995 बैच के अधिकारी जय प्रकाश नारायण को गृह मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया जा सकता है. इस पद पर अभी 1996 बैच की आईडीएएस अधिकारी रीना टंडन कार्यरत हैं.

खुल्लर बने जेएस

हरियाणा कैडर और 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार खुल्लर आर्थिक मामलों के विभाग में नए संयुक्त सचिव होंगे. वह गोविंद मोहन की जगह पर नियुक्त किए गए हैं.

सीतारमण नए उप सचिव

एम एस सीतारमण जल्द ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाने वाले हैं. वह वहां उप सचिव के पद पर नियुक्त किए जाएंगे.

परिदा पहुंचे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन

एम के परिदा 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है. यह कमीशन उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत आता है. उन्हें राजीव कुमार अग्रवाल की जगह नियुक्त किया गया है. यह पद संयुक्त सचिव के समकक्ष होता है.

यह गूजर नहीं, किसान आंदोलन है

पृष्ठ एक का शेष

है कि परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल गई तो उनकी समस्या हल हो जाएगी. गूजरों ने जब आरक्षण की मांग शुरू की तो उनके सामने एक उदाहरण था, मीणा जाति का. मीणाओं को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के कारण ही आज सिविल सेवा में उनकी संख्या सबसे अधिक है. गूजर मीणाओं को अपना सबसे बड़ा प्रतियोगी मानते हैं और उन्हें लगता है कि मीणाओं ने सरकारी नौकरियों की वजह से सरकारी संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है. गूजरों को लगता है कि आरक्षण मिलने के बाद उनकी भी सामाजिक हैसियत मीणाओं जैसी हो जाएगी. गूजर आंदोलन को जातीय पहचान की लड़ाई समझना ग़लत होगा, क्योंकि इसकी जड़ में आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं. हां, यह बात ज़रूर है कि विषमताओं के ख़िलाफ़ लड़ने और लोगों को संगठित करने के लिए किसी पहचान की ज़रूरत होती है, जो आंदोलन की धुरी बने. इस आंदोलन में गूजर जातिसूचक न होकर किसानों की समस्याओं और सरकारी नीतियों की विफलताओं के ख़िलाफ़ मुहिम का नाम है. किसानों के प्रति सरकार की जो अनदेखी है, वह कहीं गूजर, कहीं यादव या कहीं कुर्मी के नाम से आंदोलन शुरू कर सकती है.

70 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत ने एक किसान आंदोलन खड़ा किया था. उन्हें किसानों का ज़बरदस्त समर्थन मिला. उस समय भी गन्ना, गेहूं, जौ और चने की खेती करने वाले किसानों की हालत वैसी ही थी, जैसी आज गूजरों की है. गन्ना, गेहूं, जौ और चना पैदा करने की लागत ज़्यादा हो गई और सरकार ने इन फसलों की कीमत नियंत्रित कर रखी थी. किसानों को खेती से नुक़सान हो रहा था. बाद में स्थिति में बदलाव आया तो यह किसान आंदोलन शांत हुआ. महेंद्र सिंह टिकैत और गूजर आंदोलन की वजह एक है, लेकिन फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि गूजर अब अपने व्यवसाय में फ़ायदा–नुकसान को छोड़कर सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं.

1991 के उदारीकरण के बाद से सरकारी नीतियों का ध्यान किसानों और मज़दूरों की समस्याओं से दूर हटकर उद्योगपतियों, व्यापारियों और शहरी लोगों पर टिक गया. विकास का मापदंड बदल गया है. सरकार ने अपने दायित्व को ही नए ढंग से परिभाषित कर दिया है. सरकार मूलभूत ढांचे को बेहतर करती है तो औद्योगिक

विकास एजेंडे पर होता है. विकास की परिभाषा विदेशी निवेश, जीडीपी और सेंसेक्स से तय की जाती है. जब भी सरकार बाज़ार को मुक्त करने की बात करती है या इस संदर्भ में कोई फ़ैसले लेती है तो उसका सारा फ़ायदा बड़े–बड़े उद्योगपति ले जाते हैं. शिक्षा में सुधार की बात होती है तो मामला विदेशी विश्वविद्यालयों को देश के शहरों में जगह देने पर रुक जाता है. गांवों में चलने वाली सरकारी योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है. कृषि हो या उद्योग, विदेशी कंपनियों को सारी सुविधाएं और भारतीय बाज़ार उपलब्ध कराने को सरकार अपनी सफलता बताती है. ओबामा, बेन जियाबाओ या फिर सरकोजी आते हैं तो फैसले देश के बड़े–बड़े उद्योगपतियों के साथ मिल–बैठकर लिए जाते हैं. हद तो यह है कि अब दुनिया के बड़े–बड़े उद्योग घरानों को खुदरा बाज़ार में लाने की तैयारी हो गई है. वैसे भी अंबानी और बिरला पहले से ही खुदरा बाज़ार में स्थापित हो चुके हैं. सरकारी नीतियों से लगातार कृषि और उससे जुड़े उत्पादों पर आश्रित लोगों को नुकसान ही नुकसान हो रहा है.

सरकार की प्राथमिकता साफ़ है. उद्योगपतियों, व्यापारियों और शहर के लोगों का चेहरा देखकर सरकार योजना बनाती है. महंगाई पर हाय–तौबा तब मचती है, जब उन उत्पादों की कीमत बढ़ती है, जिनका रिश्ता शहर में रहने वाले लोगों से है. अख़बार में महंगाई को लेकर ख़बर छपती है तो सरकार भी नीतियां बदल देती है. विपक्ष भी हंगामा करने लगता है. मीडिया भी एक्टिव हो जाता है. अख़बार और टीवी वाले पेट्रोल की कीमत पर हाय–तौबा करते हैं तो यह बात समझ में भी आती है कि अख़बार के पाठक और टीवी दर्शक शहरी होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इतने मूर्ख हैं कि मीडिया के साथ वे भी सुर में सुर मिलाकर हंगामा करने लगते हैं. इन राजनीतिक दलों को यह समझ में ही नहीं आता है कि वे जिनके लिए लड़ रहे हैं, वे तो वोट भी देने नहीं जाते. शहरों में तो वोटिंग 30 फ़ीसदी होती है. लेकिन शहरी उच्च और मध्य वर्ग को खुश करने के लिए राजनीतिक दल अपनी शक्ति झोंक देते हैं. वहीं जब किसानों और ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ती हैं तो न मीडिया, न सरकार और न ही विपक्ष उनकी आवाज़ उठाता है. उन्हें अपनी लड़ाई ख़ुद लड़नी पड़ती है. भारत के ग्रामीण बेसहारा हो चुके हैं. उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है. अब ऐसे में सरकारी नीतियों के सताए हुए किसान कहां जाएं? क्या करें? किससे अपनी गुहार लगाएं? सांसद उनकी आवाज़ नहीं उठाते. अधिकारियों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती. देश की विभिन्न संस्थाओं ने किसानों की परेशानियों को अनसुना करने की कसम खा रखी है. ऐसी सोई हुई व्यवस्था तक अपनी आवाज़ पहुंचाने और उसे जगाने के लिए आंदोलन के अलावा और क्या रास्ता है. यही वजह है कि गूजर आंदोलन कर रहे हैं. यही वजह है, जब किसानों की ज़मीन हड़पी जाती है तो उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है. यह प्रदर्शन कभी–कभी हिंसक रूप भी अख्तियार कर लेता है. जहां–जहां किसानों को नुक़सान होता है, वहां वे आंदोलन करते हैं. देश चलाने वाली सारी संस्थाओं को इन सवालों पर ग़ौर करना होगा, हल निकालना होगा.

गूजर आंदोलन को अगर सिर्फ़ जातीय व आरक्षण के चश्मे से देखा गया तो भयंकर भूल हो जाएगी. आज गूजर आंदोलन कर रहे हैं, कल दूसरे किसान आंदोलन करेंगे. आज वे रेल और सड़क जाम कर रहे हैं, कल हथियार भी उठा सकते हैं. अगर ऐसा हो गया तो सरकारी तंत्र के पास उनसे लड़ने का कोई हथियार नहीं बचेगा. यह देश चलाने लायक नहीं रह पाएगा.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 44
दिल्ली, 10 जनवरी –16 जनवरी 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड एवं उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

पुलिस ने पुष्टि की है कि कभी झारखंड पार्टी का सदस्य रह चुका हेम्ब्रम पीसीपीए के सिद्धू कान्हू गण मिलीशिया का सदस्य था.

और लाल होगी बंगाल की धरती

नए साल का नया सूरज/लाल टहकार
लगा मुझे/सिंदूर की डिबिया सा,
जो दंगे के बाद श्मशान में पड़ा था.
हर तरफ़ बिखरी थीं ओस की बूंदें,
अरे वे तो विधवाओं के आंसू थे.

बिमल राय

कविता-नया साल मैंने कई साल पहले लिखी थी. ये उसी की शुरुआती लाइनें हैं. वह कोई साल होगा, जब नए साल का सूरज हिंसा एवं रक्तपात से गीली हुई धरती के क्षितिज पर उगा होगा. बंगाल के मौजूदा हालात पर यह कविता बिल्कुल फिट बैठती है. वामपंथियों का यह दुर्ग पिछले तीन-चार सालों से धधक रहा है, पर 2010 के आख़िरी महीने में यहां दिखी अराजकता ने संकेत कर दिया है कि 2011 के विधानसभा चुनाव तक क्या होने वाला है? बंगाल की अगली संभावित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव तक चुप नहीं बैठने वाली. इधर वाममोर्चे ने भी पलट कर खड़े होने की रणनीति अपना ली है. पक्ष-विपक्ष दोनों की रणनीतियों के संकेत बहुत डरावने हैं. इनमें नया रंग केंद्र सरकार की वजह से भी आ रहा है, जिसमें एक प्रमुख घटक है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस. 2-जी स्पेक्ट्रम की जेपीसी जांच की विपक्षी मांग के साथ शुरुआती सहानुभूति, हाल में पेट्रोल और प्याज की क़ीमतों में वृद्धि का विरोध और राज्य में कांग्रेस को बिना साथ लिए चुनाव लड़ने की धमकियों के पीछे ममता का एक डर भी है कि कहीं जौ के साथ घुन भी न पिस जाए. घोटालों और महंगाई के चलते आज यूपीए का ग्राफ बुरी तरह गिरा हुआ है. राज्य में वाममोर्चा सघन चुनाव प्रचार में जुट गया है. ये गतिविधियां ममता को बेचैन कर रही हैं और वह जीती हुई बाज़ी पलटने की कोई संभावना पैदा नहीं होने देना चाहतीं. 40 दिनों के प्रचार के बाद 13 फरवरी को कोलकाता में वाममोर्चे की एक बड़ी सभा होने वाली है. तृणमूल और कांग्रेस के नेता भी जनता के बीच जाकर आरोपों की सफ़ाई दे रहे हैं. दोनों पक्ष वहीं जा रहे हैं, जहां हिंसक वारदातें होती हैं. दोनों का अपनी जनता के लिए एक ही अप्रत्यक्ष संदेश है, डटे रहे कॉडरो! हम तुम्हारे साथ हैं.

दिसंबर 2010 में दिखी हिंसक छात्र राजनीति के पीछे भी इसी रणनीति ने काम किया. ममता ने हाल में कहा था कि कॉलेजों के चुनावों में अब तक तृणमूल छात्र यूनियन के उम्मीदवारों को मनोनयन पत्र भरने से भी रोक दिया जाता था. इस बार सभी कॉलेजों में तृणमूल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी और यही तैयारी वामपंथी छात्र यूनियन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की भी थी. हालांकि छात्र हिंसा की पहली घटना में हमला कथित तौर पर तृणमूल की ओर ही हुआ, जब हावड़ा के आंदुल में एक एसएफआई छात्र स्वप्न कोले की पीटकर हत्या कर दी गई. उसके साथ अन्य 10 छात्र भी घायल हुए. स्वप्न की हत्या के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे एसएफआई एवं तृणमूल के छात्रों के बीच कोलकाता में भी संघर्ष हुआ. महानगर के आशुतोष कॉलेज के छात्र सौविक हाजरा की बायीं आंख फोड़ दी गई. उसका इलाज हैदराबाद में चल रहा है. इस घटना में एसएफआई के 9 छात्र घायल हुए. बताया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग सौविक को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वह भीड़ की हिंसा का शिकार हुआ. 20 दिसंबर को उपद्रवियों ने उत्तर 24 परगना ज़िले के बनगांव में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के अध्यक्ष शंभू मालाकार को गोली मारकर घायल कर दिया. 22 दिसंबर को आंदुल के उस कॉलेज में चुनाव कराने के लिए चार थानों की पुलिस लगानी पड़ी. स्वप्न को जब मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य एवं विमान बोस जैसे नेताओं ने श्रद्धांजलि दी तो ममता ने एक दिन पहले लालगढ़ में कथित तौर पर माकपा कॉडरों के हाथों मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता सनातन हेम्ब्रम का शव कोलकाता मंगाकर बाकायदा पांच किलोमीटर तक का शोक जुलूस निकाला. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाशों की राजनीति करने का आरोप भी लगाया. माकपा ने कहा कि ममता माओवादियों की लाशें मंगाकर राज्य में अशांति फैला रही हैं. हेम्ब्रम पुलिस अत्याचार के ख़िलाफ़ बनी पीपुल्स कमेटी (पीसीपीए) का सक्रिय सदस्य था. पुलिस ने भी पुष्टि की है कि कभी झारखंड पार्टी का सदस्य रह चुका हेम्ब्रम पीसीपीए के सिद्धू कान्हू गण मिलीशिया का सदस्य था. माकपा के राज्य सचिव विमान बोस ने हेम्ब्रम को तृणमूल का सदस्य बताने की निंदा की और कहा कि 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद से वामदलों के 337 नेताओं एवं कॉडरों के मारे जाने में माओवादियों और तृणमूल दोनों का हाथ है. गत 21 दिसंबर को गरिया दीनबंधु कॉलेज के छात्र काजल किरण मंडल का शव मिलने से सनसनी और बढ़ी. वह तृणमूल छात्र परिषद का सक्रिय सदस्य था और अपने कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में खड़ा हुआ था. उसे माकपा की छात्र यूनियन एएसएफआई से धमकी मिल रही थी और वह दो दिनों से लापता था. 21 को यादवपुर में रेलवे लाइन पर उसका शव मिला. पहले से ही गरमाई राजनीति तब और गरमा गई, जब तृणमूल वालों ने इस छात्र के शव के साथ कोलकाता में जुलूस निकाला. 23 दिसंबर को बर्दवान में रायना के श्याम सुंदर कॉलेज के तृणमूल छात्रसंघ के सैकत निगेल को भी छुरा मारकर घायल किया गया. उसी दिन दक्षिण 24 परगना के पाथेर प्रतिमा में एएसएफआई और तृणमूल छात्रसंघ के बीच हुई झड़पों में 4 छात्र घायल हुए. हिंसक छात्र राजनीति के इस नए दौर ने 70 के दशक के नक्सल आंदोलन में छात्रों की भागीदारी की याद दिला दी. हालांकि उस समय के छात्र आंदोलन का मक़सद था अपना हक़ हासिल करना, लेकिन आज छात्र सिर्फ़ राजनीतिक दलों का मोहरा बन गए हैं. छात्र राजनीति में बाहरी उपद्रवी तत्वों का भी प्रवेश हो रहा है. एएसएफआई के दबदबे को क़ायम रख माकपा अपनी लोकप्रियता में गिरावट रोकने की कोशिश कर रही है. विधानसभा चुनाव से तीन-चार माह पहले माकपा अपने कॉडरों का मनोबल नहीं गिरने देना चाहती. 21 तारीख़ को ही राज्य के अधिकतर कॉलेजों में छात्र संसद चुनाव के परिणाम आए और माओवादी प्रभावित इलाक़ों-पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया के अलावा दक्षिण बंगाल के उन कॉलेजों में तृणमूल छात्र यूनियन का 20 साल बाद क़ब्ज़ा हुआ. कोलकाता और आसपास के इलाक़ों में वाम छात्र यूनियन का दबदबा क़ायम रहा. फिर भी यह साफ हो गया कि राज्य में बदलाव की लहर अभी थमी नहीं है या एकदम से पलटने वाली नहीं है. दलीय संघर्ष हो या माओवादी हिंसा, कहीं विराम नहीं दिखता और नहीं दिखती उम्मीद की कोई किरण. 15 दिसंबर को 40 माओवादियों ने पुरुलिया ज़िले के बागबादी गांव पर धावा बोला और घरों से निकाल कर 7 फारवर्ड ब्लॉक कॉडरों की हत्या कर दी. इनमें एक महिला प्रधान भी थी. बाद में झालदा इलाक़े में पुलिस को पांच लाशें मिलीं. वहां माओवादियों के पोस्टर भी मिले, जिनमें आरोप लगाया गया कि ये लोग सुरक्षाबलों के लिए ख़ुफ़ियागिरी कर रहे थे.

बलात्कार की शिकार एक महिला

इसके पहले 5 दिसंबर को बर्दवान में कथित तौर पर माकपा कॉडरों ने एक तृणमूल समर्थक की पत्नी से बलात्कार किया और बाद में उसके शरीर में आग लगा दी. वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है. हालांकि माकपा के ज़िला मुख्य सचिव अमल हालदार ने कहा कि घरेलू झगड़े के बाद उस महिला ने आग लगाई और यह बयान उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी दिया. इस वारदात से इस आशंका को बल मिलता है कि बंगाल में इस समय चाहे जिस कारण से ख़ूनख़राबा हो, उसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है. 21 दिसंबर को मुर्शिदाबाद ज़िले के खारग्राम में कथित तौर पर माकपा समर्थक उपद्रवियों ने सिराजुदौला उर्फ बापी नामक एक कांग्रेसी ग्राम प्रधान की हत्या कर दी, हालांकि बम फटने से एक हमलावर भी मारा गया. 22 दिसंबर को हावड़ा के चंद्रपुर में माकपा समर्थक शेख शहांगीर को गोली मार दी गई. इस वारदात के बाद वहां छिटपुट हिंसा भी हुई. 26 दिसंबर को पश्चिम मिदनापुर के गोआलतोड़ में बारीन मंडल नामक तृणमूल समर्थक की हत्या कर दी गई. शक है कि इसमें माकपा का हाथ है. उसी दिन ममता ने कोलकाता के धर्मतल्ला में जंगल महल से सुरक्षाबलों को हटाने की अपनी पुरानी मांग दोहराई. उधर दिल्ली में तृणमूल के सांसदों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर अपना दुखड़ा रोया. कोलकाता में राज्यपाल एम के नारायण ने मुख्यमंत्री को बुलाकर हिंसा रोकने के उपाय करने को कहा. यह सब चल ही रहा था कि ममता के दबाव में गृहमंत्री पी चिदंबरम ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी लिख दी, जिसमें क़ानून व्यवस्था की ख़राब हालत के लिए लताड़ लगाई गई और हर्मादवाहिनी को भंग करने को कहा गया है.

feedback@chauthiduniya.com

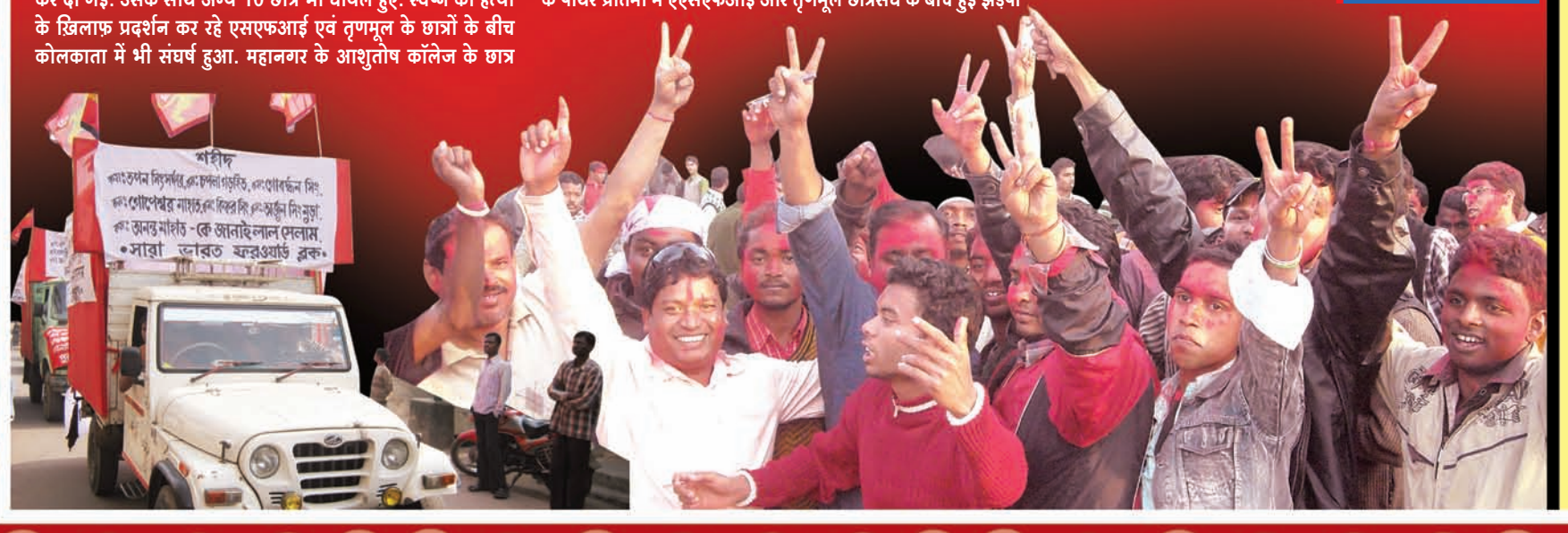

चिदंबरम की चिट्ठी से मचा कोहराम

इसमें कोई शक़ नहीं कि चिदंबरम ने ममता के आगे झुकते हुए सरकार को पत्र लिखा और जंगल महल से माकपा की हर्मादवाहिनी (हथियारबंद माकपा कॉडर) हटाने को कहा. हर्मादवाहिनी बांग्ला का शब्द है और पत्र में इस शब्द के प्रयोग से समझा जा सकता है कि ममता ने इसे लिखने को सीधे डिक्टेट किया होगा. हिंदी ज्ञान के मामले में लिख लोढ़ा, पढ़ पत्थर चिदंबरम ने किसी भाषाविद् या प्रणव मुखर्जी से पूछने की ज़हमत नहीं उठाई कि इसका मतलब क्या है. पहली ग़लती तो यह हुई कि पत्र कोलकाता पहुंचने से पहले ही 24 दिसंबर को मीडिया को लीक कर दिया गया. जब पत्र 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा तो तुरंत बवाल शुरू हो गया. वाममोर्चा के नेताओं ने कहा कि इसका सीधा मतलब तृणमूल को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाना था. तीन दिनों तक उनसे पत्र पर प्रतिक्रिया मांगी जाती रही, पर वे कुछ बोलने में असमर्थ थे. विपक्ष का उत्साह देखिए कि इस मामले पर विधानसभा में मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन की नोटिस लाने की भी तैयारी हो चुकी थी. 27 दिसंबर को चला लेटर बम जैसे ही मुख्यमंत्री तक पहुंचा, वामनेता बिफर उठे. इसमें हर्मादवाहिनी शब्द पर गृहमंत्री की मुहर जो लग गई थी. एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में चिदंबरम से पूछा कि क्या उन्हें ममता और माओवादियों के मेलमिलाप के बारे में पता है? राज्य में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त कहे जाने से भी वाम नेताओं को मिर्ची लगी है. मुख्यमंत्री ने जवाबी पत्र में वही सफ़ाई दी, जिसके बारे में वह पहले से कहते आ रहे हैं. माओवादियों के आतंक से अपना घर-बार छोड़कर भागे वाम कॉडरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें पार्टी कार्यालयों में रखा जा रहा है. संभव है कि सुरक्षा के लिहाज़ से उनके पास कुछ हथियार भी हों. सरकार ने हर्मादवाहिनी जैसे किसी संगठन के सक्रिय होने से साफ़ इंकार किया है. जिस तरह तृणमूल पर माओवादियों से मदद लेने का आरोप लग रहा है, उसी तरह वाम सरकार पर सुरक्षाबलों का दुरुपयोग करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है. ग्रामीण इलाक़ों में माकपा के कॉडर माओवादियों की हरकतों और उनके अड्डों की जानकारी सुरक्षाबलों को दे रहे हैं. पुरुलिया में फारवर्ड ब्लॉक कॉडरों की हत्या इसी शक़ में हुई. तृणमूल को लगता है कि सुरक्षाबलों की वजह से वामदल जंगल महल के तीन ज़िलों में अपना खोया हुआ जनाधार फिर हासिल कर रहे हैं. वामदल भी प्रचारित कर रहे हैं कि ममता माओवादियों के साथ हैं, इसलिए वह सुरक्षाबलों को हटाने की मांग कर रही हैं.

राज्य का राजनीतिक ध्रुवीकरण ऐसा है कि ममता की काट तैयार नहीं हो पा रही है. वाममोर्चे ने सोचा था कि नैनो के जाने के बाद शहरी मध्य वर्ग का ममता से मोहभंग होगा, पर बाद के चुनावों में ऐसा नहीं दिखा. ममता गठबंधन को लेकर जब-तब कांग्रेस को हड़काती रहती हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जंगल महल में सुरक्षाबलों के दुरुपयोग की बात ग़लत साबित होगी तो वह अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं. ज़ाहिर है, अगले पांच महीनों यानी विधानसभा चुनावों तक सुरक्षाबलों को हटाने का फ़ैसला आत्मघाती होगा. वाममोर्चा ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि गृहमंत्री ने तृणमूल का पक्ष लिया और उसी के नज़रिए से हालात का आकलन कर पत्र लिखा. उधर विमान बोस ने कहा है कि अगर तृणमूल अपने मारे गए एवं घायल कॉडरों की सूची पेश करे तो वाममोर्चा भी अपनी सूची सौंपने को तैयार है. गृह मंत्रालय की सूची के मुताबिक़, लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में मारे गए और घायल हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं में क्रमशः तृणमूल के 96 एवं 1237, कांग्रेस के 15 एवं 221 और माकपा के 65 एवं 773 कॉडर हैं.

मुंगेर के थाना तारापुर के लौंगाय गांव के मनोज कुमार उर्फ़ अमित कुमार मधुकर को हत्या के इल्ज़ाम में 4 फरवरी, 1986 को आजीवन कारावास की सज़ा हुई.

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

ख़र्चा रुपया, काम चवन्नी

दो सालों में 54 लाख रुपये मानदेय पर ख़र्च | **दो सालों में यात्रा भत्ता 3 लाख 37 हज़ार रुपये** | **दो सालों में महज़ 27 शिकायतों का निस्तारण**

अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर बना राज्य अल्पसंख्यक आयोग आख़िर किसका कल्याण कर रहा है, जब इस बात की पड़ताल की गई तो पता चला कि लाखों रुपये ख़र्च करने के बावजूद यह अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों का निपटारा समय पर नहीं कर पा रहा है. फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार सफ़ेद हाथी साबित हो रहे इस आयोग में बदलाव के लिए नहीं सोच रही है. आख़िर क्यों? इस सवाल का जवाब जानना उत्तर प्रदेश के करोड़ों अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ज़रूरी है.

अल्पसंख्यक, एक ऐसा शब्द, जिसका इस्तेमाल शायद राजनीति में सबसे ज़्यादा होता है. सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद बस इस शब्द और इस समुदाय का इस्तेमाल ही होता आया है. इसके अलावा जो कुछ भी होता है, वह सिर्फ़ दिखावे के लिए होता है. मसलन, उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग. चौथी दुनिया को मिले दस्तावेज के मुताबिक़, यह आयोग पिछले दो सालों के दौरान लाखों रुपये डकारने के बाद मात्र 27 मामले निस्तारित कर सका. दस्तावेज में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि इन दो सालों में आयोग के पास जितनी भी शिकायतें आईं, उनमें से 139 मामलों में इसने सम्मन जारी किए. पिछले दो सालों में आयोग अपने पास आईं शिकायतों में से महज 27 का ही निस्तारण कर सका. ज़्यादातर मामलों में सुनवाई जारी है.

चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज़ के मुताबिक़, आयोग के अध्यक्ष को प्रति माह 40 हज़ार रुपये, उपाध्यक्ष को 35 हज़ार रुपये और हर सदस्य को 25 हज़ार रुपये मानदेय का भुगतान किया जाता है. इस तरह पिछले दो सालों में इन माननीय सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्ष को क़रीब 54 लाख रुपये मानदेय के तौर पर दिए गए.

दरअसल, आंकड़े सिर्फ़ आंकड़े भर नहीं है, बल्कि वे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की प्रासंगिकता और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सरकार की संजीदगी की कहानी भी बयान करते हैं. इस आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 9 सदस्य हैं. यानी कुल मिलाकर आयोग में 12 लोग हैं. चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज के मुताबिक़, आयोग के अध्यक्ष को प्रति माह 40 हज़ार रुपये, उपाध्यक्ष को 35 हज़ार रुपये और हर सदस्य को 25 हज़ार रुपये मानदेय का भुगतान किया जाता है. इस तरह पिछले दो सालों में इन माननीय सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्ष को करीब 54 लाख रुपये मानदेय के तौर पर दिए गए. इसके अलावा इनके यात्रा भत्ता के रूप में भी आम आदमी की कमाई का एक हिस्सा (3 लाख 37 हज़ार रुपये) ख़र्च हुए. ध्यान देने की बात यह है कि जो पैसा इन लोगों को दिया गया, वह दरअसल जनता का ही पैसा है. वह पैसा, जो आम आदमी टैक्स के रूप में सरकार को देता है. इस लिहाज़ से इस एक-एक रुपये का पूरा-पूरा फ़ायदा आम आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है.

आयोग की कार्यशैली कुछ ऐसी है कि जब कभी इसके पास कोई शिकायत आती है तो आयोग के सदस्य संबंधित व्यक्ति और जगह तक पहुंच कर शिकायत की जांच करते हैं. आयोग के अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक़, आयोग के सदस्य राज्य के सभी जनपदों में भ्रमण कर अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं. ज़ाहिर है, सदस्यों के पास कहीं भी आने-जाने के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है. अक्टूबर 2010 तक के आंकड़ों के मुताबिक़, आयोग 139 मामलों में सम्मन जारी करता है. फिर भी क्या कारण है कि आयोग में शामिल 12 लोग मिलकर दो साल में सिर्फ़ 27 शिकायतों का ही निस्तारण कर पाते हैं. आख़िर आयोग की इस सुस्ती की वजह क्या है?

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी भी ख़ासी बड़ी है. तो क्या उनके पास कोई समस्या या शिकायत नहीं है या फिर वे अपनी समस्या लेकर आयोग के पास नहीं जाते. सवाल यह भी है कि क्या आयोग तभी कार्रवाई करेगा, जब उसके पास कोई शिकायत लेकर पहुंचेगा. पूरे देश में अल्पसंख्यकों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति कैसी है, यह बात किसी से छुपी नहीं है. सच्चर कमेटी से लेकर रंगनाथ आयोग तक इस वर्ग की आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति पर अपनी चिंता ज़ाहिर कर चुका है. ऐसे में क्या आयोग इस बात का इंतजार करेगा कि कोई उसके पास शिकायत लेकर आए. क्या आयोग मीडिया में आई ख़बरों के आधार पर स्वत: कार्रवाई नहीं कर सकता.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

काल कोठरी में ख़त्म होता बचपन

जाता है, इस हिसाब से उसे बाल क़ैदी नहीं माना गया और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, लेकिन 2002 के संशोधन के बाद बाल क़ैदी की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है.

मुंगेर के थाना तारापुर के लौंगाय गांव के मनोज कुमार उर्फ़ अमित कुमार मधुकर को हत्या के इल्ज़ाम में 4 फरवरी, 1986 को आजीवन कारावास की सज़ा हुई. इसके बाद वह पटना हाईकोर्ट तक अपील करते हुए ज़मानत पर रहा, लेकिन 22 फरवरी, 1997 को उसे जेल जाना पड़ा. तेरह सालों से काल कोठरी में सज़ा काट रहे मनोज को तीन साल बाद यानी 2000 में रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कहने को इस अधिनियम को लचीला और कल्याणकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर संशोधन करती रही है, ताकि अधिक से अधिक कारा संसीमित दोषसिद्ध किशोर खुली हवा में सांस ले सकें और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर देशहित में कुछ योगदान दें, लेकिन यह सब कागजों में ही सिमट कर रह जाता है. कई बंदी हैं, जो आज भी रिहाई की आस में हैं. जब एक जागरूक वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश पोद्दार ऐसे मामलों की पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि मनोज जैसे कई किशोर और भी हैं, जो अपना बचपन न जाने कब खो चुके हैं. इस मामले पर पोद्दार ने राज्य गृह विभाग, समाज कल्याण विभाग और राज्य मानवाधिकार आयोग में भी गुहार लगाई है. इस बाबत जब किशोर न्याय परिषद, मुंगेर जेजे वार्ड से जवाब मांगा गया तो उसने भी जवाबदेही से मुंह फेर लिया. राज्य कारा प्रशासन और सलाहकार परिषद को भी इससे कोई वास्ता नहीं है.

हालांकि 10 जून, 2008 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक 16 जुलाई, 2008 को हुई. इसमें प्रस्तुत 9 मामलों में 6 पर विचार करने के बाद 3 लोगों को दोषमुक्त करार देकर रिहा करने का प्रस्ताव पारित हुआ. इन रिहा हुए तीन किशोर बंदियों में पटना के डॉक्टर उत्पलकांत के पुत्र सिद्धार्थ, अरिणित दास केंद्रीय कारा बेउर पटना और जितेंद्र सिंह शामिल हैं. ग़ौरतलब है कि इन तीनों किशोर बंदियों को मुक्त करने का आधार इनकी उम्र का 18 वर्ष से कम होना था. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब इन तीन किशोरों को आज़ाद किया गया, तो फिर मनोज को रिहाई क्यों नहीं मिली?

खानापूर्ति के लिए राज्य सरकार, राज्य सलाहकार बोर्ड, ज़िला सलाहकार बोर्ड, राज्य एवं ज़िला बाल संरक्षण इकाई जैसी कई संस्थाएं गठित की गई हैं, लेकिन सभी अपनी ज़िम्मेदारी को दूसरे के सिर डाल कर पल्ला झाड़ लेती हैं. इन सबका अब तक का यही काम है कि इन्होंने 10 वर्षों में मात्र तीन किशोर बंदी रिहा कराए हैं. इसके अलावा अन्य विचाराधीन किशोर बंदियों को रिहाई कब नसीब होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है.

मामला सिर्फ़ इस तरह के जुर्म में सजायाफ्ता किशोर बंदियों का ही नहीं है, बल्कि उनका भी है, जो अन्य कई मामलों में जेल में बंद हैं. दहेज उत्पीड़न के मामलों (डाउरी एक्ट 498 ए) में परिवार समेत उन दुधमुंहे बच्चों को भी जेल में डाल दिया जाता है, जो 18 साल तो क्या, 18 महीनों के भी नहीं होते. तो क्या तब किशोर न्याय अधिनियम की खुलेआम धज्जियां नहीं उड़तीं? हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक़, भागलपुर के महिला कारा मंडल में महिला क़ैदियों की संख्या 73, सजायाफ्ता क़ैदी 54, विचाराधीन 19 और उनके साथ 8 बच्चे भी शामिल हैं. ग़ौरतलब है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे दहेज उत्पीड़न मामले में ही परिवार के साथ बंदी हैं. अब इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है?

rajesh@chauthiduniya.com

राजेश एस कुमार

कहते हैं, क़ानून अंधा होता है. इसके इस अंधेपन की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियों में अंधेरा छा जाता है, इसका जीता-जागता उदाहरण बिहार के मुंगेर ज़िले का मनोज कुमार सिंह है. यह शख्स पिछले तेरह सालों से मंडल कारा मुंगेर की काल कोठरी में उस सज़ा को भुगत रहा है, जो उसके लिए है ही नहीं. उसकी सज़ा लगभग दस साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही, लालफीताशाही और क़ानूनी दांव-पेचों के चलते जेल में बंद वह आज भी अपनी रिहाई की बाट जोह रहा है.

22 फरवरी, 1997 से जेल में बंद मनोज सज़ा के समय किशोर (16 वर्ष 5 माह) था और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2002 की धारा 15 के तहत किसी भी किशोर, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, को अधिकतम तीन वर्ष की सज़ा होती है. इस हिसाब से मनोज की रिहाई तीन साल में हो जानी चाहिए थी. चूंकि वारदात के समय उसकी उम्र 16 वर्ष 5 माह थी और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 16 साल की उम्र तक के बच्चों को ही बाल कैदी माना

VARUN POWERTECH LIMITED
VARUN
Head Office : C-124, First Floor, Sector-10, Noida-20301, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Phone : +91-120-3910005, +91-120-3910006, Fax : 0120-3910006, Email : vptl2010@gmail.com

Wishing A happy & Prosperous New Year to our Patrons & Customer

OUR MOTO
Excellence Through Commitment

- To achieve excellence in every sphere of our activities through quality in our work procedure and customer focused commitment.
- To timely delivery of high quality, reliable, efficient engineering products and services.
- To provide an optimum solution to our client needs conforming to our organization goals to attain long term goodwill and consistently deliver customer satisfaction.

Factory : A-171, Sector-83, Noida-201305, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Email : vptl2010@gmail.com, Phone : +91-120-4278568, Fax : 0120-4278569

गुरु संगत में बच्चों को सबसे बड़ा देवी-देवता माना गया और संदेश दिया गया कि बच्चों का सम्मान करना सबका कर्तव्य है, उनकेअधिकारों की रक्षा करना पहला धर्म है.

जीने का अधिकार अभियान

जन जागरण के नए प्रयोग की दस्तक

आदियोग

अपने हितों और अधिकारों के लिए आदिवासियों को जगाने और जुटाने का यह अनूठा सामाजिक प्रयोग है. नाम है जीने का अधिकार अभियान, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी एवं मंडला ज़िलों के ढाई दर्जन से अधिक आदिवासी गांवों में अपने पैर जमाने की तैयारी कर रहा है. इसी कड़ी में बीते एक से 10 दिसंबर तक तीनों ज़िलों के कुल 10 गांवों में गुरु संगत का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से भी आदिवासी पहुंचे. यह आयोजन छीतापाल, मुखास (कटनी), उमरझर, खामा, कुबरहट, छपरा (जबलपुर), जंगलिया, झालपानी, मोहपानी और बस्तरी गांव (मंडला) में हुआ. इस दौरान यह नारा लगातार गूंजता रहा कि जागेंगे-जगाएंगे/ख़ुशियां वापस लाएंगे/धरती को स्वर्ग बनाएंगे.

पहले संबंधित गांव की परिक्रमा होती थी. इस दौरान ढोल-मंजीरे की थाप पर यह सामूहिक गान जारी रहता था-किलकारियां कहती हैं जीने दो हमें, जीने दो हमें. गुरु संगत की शुरुआत पांच नन्हें बच्चों को हल्दी-चूना-चावल का तिलक लगाकर उनके पैर छुए जाने से होती थी. हल्दी स्वास्थ्य, चूना स्वच्छता और चावल पोषण के प्रतीक के तौर पर था. समापन पर मीठे भात का वितरण होता था, जिसे हर घर से जुटाए गए एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच चीनी से तैयार किया जाता था. इसे एकता का प्रसाद कहा गया. गुरु संगत में लोगों ने संकल्प लिया कि वे हर रात सोने से पहले पांच मिनट आंख मूंदकर दिन भर के अपने व्यवहार-आचरण का लेखा-जोखा करेंगे. अपनी कमियों, कमज़ोरियों और ग़लतियों को पहचानेंगे और उन्हें दूर करने का हर मुमकिन जतन करने का ख़ुद से वायदा करेंगे. साथ ही हर गुरुवार अपने गांव में गुरु संगत का आयोजन करेंगे, जिसमें घर-परिवार, गांव-समाज एवं ज़िंदगी से जुड़े मसलों और सवालों पर चर्चाएं होंगी. कभी गीत-संगीत की महफ़िल सजेगी तो कभी क़िस्से-कहानियों और लतीफ़ों का दौर चलेगा. गुरु संगत लोगों को जगाने और जोड़ने का काम करेगी.

गुरु संगत यानी गुरु का साथ. तो गुरु कौन? किसी गद्दी पर विराजमान व्यक्ति कतई नहीं, जो केवल भजन-कीर्तन और प्रवचन करता हो. यहां गुरु वही है, जो समाज और लोगों को अंधियारे से उजियारे की ओर ले जाए, जीवन जीने का अर्थ बताए, समता और सम्मान का पाठ पढ़ाए, आत्मनिर्भरता की राह सुझाए, अधिकारों की चाह जगाए, संघर्षों का दिया जलाए. गुरु का मतलब अधिक जानकार होना नहीं, समझदार होना है. गुरु उम्र में छोटा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है. मां पहली गुरु होती है. गुरु जाति, धर्म और लिंग से ऊपर होता है. केवल अच्छा इंसान ही सच्चा गुरु बन सकता है. अच्छा इंसान बनने की कोशिश सच्चा गुरु बनने की शुरुआत है. गुरु संगत ने सच्चे गुरु की पहचान बताई कि वह सबके बीच रहता है, सबके साथ चलता है. मुश्किल राहों पर सबसे आगे होता है, वरना सबसे पीछे रहता है. आदिवासियों से अपील की गई कि वे गुरु बनने और दूसरों को गुरु बनाने की तैयारी करें.

गुरु संगत की बातें

गुरु संगत में बच्चों को सबसे बड़ा देवी-देवता माना गया और संदेश दिया गया कि बच्चों का सम्मान करना सबका कर्तव्य है, उनके अधिकारों की रक्षा करना पहला धर्म है. इससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती कि हर बच्चे के होठों पर मुस्कान हो, वे फूल की तरह खिलें और दूर-दूर तक महकें. सभी बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन यह देखना भी ज़रूरी है कि ख़ुद स्कूल का क्या हालचाल है. ऐसी शिक़ायतें आम हैं कि गुरु जी अक़्सर स्कूल से बाहर रहते हैं या देर से स्कूल आते हैं, ऊंघते रहते हैं, स्कूल में खैनी-गुटखा खाने से परहेज़ नहीं करते या पिटाई करते हैं, मुर्गा बनाते हैं, कान उमेठते हैं, चिकोटी काटते हैं, वगैरह. नतीज़ा यह कि तीसरी-चौथी कक्षा के तमाम बच्चों के पास इस सवाल का जवाब नहीं कि एक मिला एक से तो कितना हुआ. ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा? यह तो ढोंग है. सोचना होगा कि तमाम बच्चे स्कूल जाने के नाम पर बेमन क्यों हो जाते हैं. इसलिए कि बच्चे सबसे पहले प्यार की भाषा समझते हैं, लेकिन स्कूल तो उनके लिए खुली जेल हो गए हैं. आंगनवाड़ी की भूमिका पोषाहार वितरण केंद्र तक सिमट कर रह गई है. यह नई पौध के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

गुरु संगत कटनी ज़िले के मुखास गांव में भी हुई. धीमरखेड़ा ब्लॉक का यह मामूली आदिवासी गांव तब अचानक ग़ैर मामूली हो गया और ख़बरों में छा गया, जब पिछले ढाई साल के दौरान यहां 11 बच्चों की मौत हो गई. इसका कारण पीने का ख़राब पानी और बीमार बच्चों को समय से सही इलाज़ न मिल पाना था. यह सवाल एक स्थानीय संस्था ने उठाया तो उसके कार्यकर्ताओं सहित कुछ गांववालों को क़ानून के हवाले कर दिया गया, लेकिन कुल नतीज़ा आख़िरकार अच्छा निकला. अपनी छीछालेदार से बचने के लिए प्रशासन मेहरबान हुआ. पहली बार किसी कलेक्टर ने मुखास का दौरा किया. इस तरह 11 बच्चों की शहादत के बाद गांववालों को पीने का साफ़ पानी नसीब हुआ. गुरु संगत के कई पड़ावों पर मनरेगा का ज़िक्र छिड़ा और उसका हिसाब भी लगा. माना गया कि एक परिवार में औसतन छह सदस्य होते हैं और साल में सौ दिन के काम की गारंटी है. माना कि सौ दिन काम मिलता है और सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दस हज़ार रुपये की मज़दूरी मिल जाती है. यानी एक माह में लगभग 667 रुपये, प्रतिदिन लगभग 23 रुपये और जिसके छह हिस्सेदार. यह काम के अधिकार की उस क़ानूनी गारंटी का हाल है, जो एक परिवार की ज़िंदगी चलाने के लिए दाल में नमक बराबर भी नहीं है. होना यह चाहिए कि काम की गारंटी परिवार के नाम नहीं, व्यक्ति के नाम हो. दो सौ दिन का काम मिले और मज़दूरी दो सौ रुपये प्रतिदिन हो. गांव-गांव से यह आवाज़ उठनी चाहिए.

महिलाओं की आज़ादी का सवाल भी उठा. इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना गया कि भले ही यह इलाक़ा रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाता हो और उनकी वीरता का गुणगान हो, लेकिन घर की लड़कियों-महिलाओं को तो शुरू से ही कमतर एवं कमज़ोर समझने और उन्हें वैसा ही बनाए रखने का क़ायदा चल निकला है. आदिवासी महिलाओं का चेहरा ढंकता घूंघट इसका नमूना है, जो मूलतः ग़ैर आदिवासी समाज का रोग है. मंडला में घूंघट विरोधी कार्यक्रम भी हो चुके हैं. संगत के सभी पड़ावों पर कई महिलाएं सामने आईं और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी. ज़्यादातर के लिए ऐसे किसी मंच पर खड़े होने का यह पहला मौक़ा था. बस्तरी की रेवती ने कहा कि लड़कियों को बोझ समझा जाता है और बराबरी के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया जाता है तो कुबरहट की यशोदा उलाड़ी ने कहा कि महिलाओं को मर्यादा में रहने की सीख दी जाती है, लेकिन उन्हें इत्मीनान से नहाने की भी आज़ादी हासिल नहीं है. छीतापाल की जीरा बाई एवं कमली बाई, उमरझर की तीतो बाई, छीरपानी की शिवकली मरावी, मोहपानी की सुनीता और सुखी आदि तमाम महिलाओं की ज़ुबानी घरेलू कलह और पंचायतों की उदासीनता भी सतह पर आई. ग़ौरतलब यह भी कि सामाजिक कार्यकर्ता कीर्ति दुबे (कटनी) और सरोज परस्ते (जबलपुर) ने पहली बार किसी कार्यक्रम का संचालन किया.

महिलाओं की आज़ादी का सवाल भी उठा. इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना गया कि भले ही यह इलाक़ा रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाता हो और उनकी वीरता का गुणगान हो, लेकिन घर की लड़कियों-महिलाओं को तो शुरू से ही कमतर एवं कमज़ोर समझने और उन्हें वैसा ही बनाए रखने का क़ायदा चल निकला है. आदिवासी महिलाओं का चेहरा ढंकता घूंघट इसका नमूना है, जो मूलतः ग़ैर आदिवासी समाज का रोग है.

जबलपुर के श्याम सिंह मार्को (कुबरहट) और धनीराम सैंय्याम (छपरा) ने अपने गांव में आयोजित गुरु संगत का संचालन करते हुए इस कला में ख़ुद को मंजा हुआ साबित किया. उमरझर में यह ज़िम्मा लता मंगेश्वरी और ज्योति बैरागी ने संभाला तो बस्तरी में राजेश बैरागी ने. यह तीनों उस नौ सदस्यीय छात्रदल से हैं, जो इस आयोजन का नियमित सहयात्री बना. छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भान साहू की भागीदारी ने आयोजन को ऊर्जा देने का काम किया. जबलपुर के हुब्बीलाल आर्मो (कुसुमडहरी गांव) और पंचम सिंह मार्को (छीरपानी गांव) ने सरकारी लूट के ख़िलाफ़ अपना रचा गीत पेश किया तो 80 साल के केहर सिंह धुर्वे (कुबरहट गांव) ने सामाजिकता के महत्व पर ज्ञान की गंगा बहाई. ख़ुशीलाल ने बताया कि उनके गांव रामेपुरा के लोगों को पानी के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. प्राथमिक स्कूल का भवन 1997 के भूकंप में ढह गया था. भवन दोबारा बनने लगा तो शिक़ायत हुई कि उसमें घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. तबसे भवन अधूरा पड़ा है. आंगनवाड़ी केंद्र भी किराए के घर में है. बलजू कुंजाम ने बताया कि कुल्हार नदी के किनारे बसा उनका गांव रामपारी खुर्द बरसात के मौसम में टापू बन जाता है. मंडला के सामाजिक कार्यकर्ता पन्नालाल सिंगरौरे ने शिक्षकों की भारी कमी को सामने रखा तो ममता साहू ने लड़कियों की शिक्षा और जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता भाग सिंह कुलस्ते ने सरकारी सुविधाओं की दुर्गति को.

संगत में यह आम राय बनी कि विकास तभी विकास है, जब सभी नागरिकों को जीने के अधिकार की गारंटी मिले. यानी हर हाथ को काम, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य का बंदोबस्त, कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक ज़रूरतमंदों की सीधी पहुंच, प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण और सभी तरह के भेदभाव से आज़ादी. लेकिन इस अधिकार की आवाज़ बहुत बिखरी हुई और धीमी है. इसे जोड़ने और मज़बूत किए जाने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि लोग समझदार नहीं, मुश्किल तो यह है कि वे उदासीनता और निराशा के अंधे कोने में दुबके रहते हैं. बेहतरी का सपना देखना भूलने लगे हैं. पंजाबी के शहीद कवि अवतार सिंह पाश के शब्दों में कहें तो सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. जीने को तो कुत्ते-बिल्ली भी जी लेते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमें इंसान की तरह, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीने का सपना देखना और उसे हासिल करने के लिए एकजुट होकर लड़ना सीखना होगा. यह जवाब मांगने के लिए आगे आना होगा कि जो होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ और जो नहीं होना चाहिए था, क्यों और कैसे हो गया? संगत का प्रमुख संदेश था कि बेहतरी के लिए साझा संघर्ष के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं. प्रेम, सहयोग, सौहार्द और विश्वास से बुनी हुई एकता से बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं. अगर यह देवता जाग्रत है तो संघर्ष से बड़ा दूसरा कोई गुरु नहीं.

हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि

इन दिनों एनजीओज़ द्वारा खड़े किए गये सीबीओज़ (समुदाय आधारित संगठन) की जैसे बाढ़ आ गई है. नारा भले हो कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, लेकिन आम तौर पर सीबीओज़ के तौर-तरीक़ों में इस नारे की आत्मा दूर-दूर तक नज़र नहीं आती. इसका मूल कारण एनजीओज़ की नियंत्रणकारी प्रवृत्ति है, जो सीबीओज़ को उनका जेबी संगठन बनाए रखती है. ज़ाहिर है, सीबीओज़ तभी सामने होते हैं, जब उनके विधाता चाहते हैं.

अपवाद कहां नहीं होते. महाराष्ट्र का वाटरशेड आर्गेनाइज़ेशन ट्रस्ट कोई चार साल से मध्य प्रदेश में भी सक्रिय है. जबलपुर, कटनी और मंडला ज़िलों में उसके चार सहयोगी एनजीओज़ हैं. जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, उसका काम वाटरशेड तक सीमित रहा है. मक़सद है, पानी और मिट्टी को बचाना-सहेजना. संस्था ने नए प्रयोगों से जोड़कर परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया. समुदाय को इसका बड़ा फ़ायदा मिला. एक हद तक पानी की किल्लत से छुट्टी मिली, ज़मीन की सेहत सुधरी और किसानी मुनाफ़े का सौदा दिखने लगी. लेकिन साथ ही यह भी दिखा कि समुदाय ने संस्थाओं को सुधार और राहत का फ़रिश्ता मान लिया. सामुदायिक सक्रियता निजी आर्थिक हितों से प्रेरित बनी रही और हमेशा स्थानीय संस्था का मुंह ताकती रही. यह परियोजना को समुदाय तक ले जाने के एकांगी तौर-तरीक़ों का नतीज़ा था, जिसने समुदाय को केवल लाभार्थी की भूमिका तक समेट दिया. दूसरी तरफ़ ज़िंदगी से जुड़े बुनियादी सवाल अनछुए रह गए, क्योंकि परियोजना में उनके लिए कोई जगह नहीं थी. अधिकार आधारित नज़रिया ग़ायब रहा. इसलिए सामुदायिक सक्रियता भी लाभ हासिल करने की दौड़ तक सीमित रही और व्यापक सामाजिक हितों से नहीं जुड़ सकी.

जबलपुर शहर से कोई सौ किलोमीटर दूर बरगी नगर नामक छोटे से क़स्बे में बीते 4 से 14 अगस्त तक 11 दिनों की जीवन की पाठशाला का अनूठा आयोजन हुआ. पाठशाला ने जीने का अधिकार अभियान को जन्म दिया. बाद में अभियान संचालन के लिए गांव-गांव समितियां गठित की गईं और उनके ज़रिए अभियान की गतिविधियां संयोजित की गईं. वाटरशेड आर्गेनाइज़ेशन ट्रस्ट के अलावा तीन स्थानीय संस्थाएं- महामाया शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति (जबलपुर), जयभारती शिक्षा केंद्र (कटनी) और कामयाब युवा संस्कार समिति (मंडला) अभियान की सहयोगी बनीं.

feedback@chauthiduniya.com

पानी पर्यावरण का एक हिस्सा है. इसके सामाजिक पहलू पर ग़ौर करें तो सदियों तक छूत-अछूत जैसे घोर असंवैधानिक और अति अमानवीय शब्द जल निकायों एवं स्रोतों से पारिभाषित किए जाते रहे हैं.

पानी कब बनेगा चुनावी मुद्दा?

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अमरेंद्र किशोर

देश भर में रोज़गार मुहैया कराने वाली अति महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा की सफलता प्रचार माध्यमों द्वारा गाए जाने के बावजूद गांवों से पलायन थमा नहीं है. पेयजल मिशन का यशोगान इस चुनावी माहौल में पवित्र ऋचाओं से कम सात्विक नहीं लगा, मगर इस साल भी गांव–शहर पानी की कमी से आतंकित ज़रूर रहे. जलस्रोतों एवं जल निकायों की गंभीर उपेक्षा, भू–जल के बेतरतीब दोहन और नदी जल के विवेकहीन उपयोग की वजह से यह बात साफ है कि आम आदमी तक पानी पहुंचाने की घोषणाएं निरर्थक हो चुकी हैं. पेयजल से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं में शासन की लापरवाही और अक्षमता साबित हो चुकी है.

जल से जुड़े संदर्भ इंसान के अस्तित्व को तय करते हैं. चाहे किसानी का मसला हो या व्यक्तिगत उपयोग का, पानी की ज़रूरत तो जीव- जंतु–इंसान सभी को होती है. ऐसे में इसकी कमी से अराजकता पैदा होने से इंकार नहीं किया जा सकता. आज़ादी के पहले देश में प्राचीन जल संग्रह पद्धति अस्तित्व में थी, मगर अधिक अन्न उपजाने, शहरीकरण, आबादी के बढ़ते दबाव, अविवेकी विकास नीतियों से कुदरती संसाधनों के परस्पर रिश्तों में दरार देखने को मिली. इनके अनियंत्रित उपयोग से स्थिति बदतर होती चली गई. गांव में दलितों, पहाड़ों में आदिवासियों और शहरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पानी एक गंभीर समस्या बनता चला गया. बांधों के निर्माण, नहरों के संजाल, नलकूप–हैंडपंप जैसे उपायों के बावजूद जल की निरंतरता और उसके वितरण में असमानता लगातार बढ़ती चली गई. नीति नियंताओं को यह बताया गया था कि जल प्रबंधन का लोकतंत्रीकरण हर हाल में ज़रूरी है. मतलब यह कि हर आदमी तक पानी की पहुंच बनाना, उसका समान वितरण सुनिश्चित करना और यह तय करना कि समूची व्यवस्था सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो. जल व्यवस्था के प्रबंधन और नियंत्रण की इन्हीं शर्तों पर योजनाएं बनाने की सहमति हुई थी.

हर गांव–हर घर तक शुद्ध जल की उपलब्धता नेहरू के जमाने से ही सरकार की प्राथमिक प्रतिबद्धता थी. बेहतर आपूर्ति के लिए सुधरी हुई प्रबंध व्यवस्था तय की जानी थी. जलस्रोतों की सुरक्षा और सुधार की ज़रूरत भी बाद में महसूस की गई. विशेषज्ञों ने माना कि परंपरागत जल निकायों को फिर से जीवित किए जाने की ख़ास ज़रूरत है. समान जलापूर्ति सुनिश्चित करना, ख़ास तौर से दलितों एवं आदिवासियों जैसे कमज़ोर तबकों के लिए, एक मुश्किल भरा काम था और सरकार के लिए चुनौती भी. जलस्रोतों के अंदर एवं आसपास साफ पर्यावरण के निर्माण, जल की गुणवत्ता के परीक्षण, कम मात्रा के बेहतर उपयोग, इस्तेमाल हो चुके पानी फिर से उपयोग लायक बनाने और शहरों में कम लागत पर जलापूर्ति के लिए बेहतर प्रबंधन को लेकर अब अनेक कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित हो चुकी हैं.

पानी पर्यावरण का एक हिस्सा है. इसके सामाजिक पहलू पर ग़ौर करें तो सदियों तक छूत–अछूत जैसे घोर असंवैधानिक और अति अमानवीय शब्द जल निकायों एवं स्रोतों से पारिभाषित किए जाते रहे हैं. बाद में संस्कृतिकरण की प्रकिया में ग़ैर ब्राह्मणवादियों 19वीं सदी में न सिर्फ़ जनेऊ पहना, बल्कि जल निकायों पर धावा बोलकर कर्म, धर्म, पाप, माया, संसार और मोक्ष की अवधारणा को नए सिरे से स्थापित किया. आज़ादी के पहले धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों का भी गहरा असर रहा, जिसके चलते जलस्रोतों की शुद्धि और जल से शुद्धिकरण जैसी बातें बेमानी होती चली गईं. जैसे–जैसे लोकतंत्र का प्रचार–प्रसार हुआ, सामाजिक न्याय की अवधारणा गढ़कर उसे सख्ती से लागू किया गया और प्रशासनिक तंत्र को चुस्त–दुरुस्त कर सामाजिक–धार्मिक स्तर पर जारी छुआछूत रोकने का महायज्ञ सरकार ने ज़रूर पूरा किया.

दक्षिण भारत के तटीय इलाक़ों में पश्चिमीकरण का असर पानी की संस्कृति पर पड़ा. बिजली और रेडियो के साथ–साथ लोहे के पाइप से जलापूर्ति को पुजारी वर्ग ने भी स्वीकारा. उल्लेखनीय है कि जल निकायों से ब्राह्मणों के घर तक जाने वाली पाइप लाइन दलितों की बस्ती से भी होकर गुजरती थी. तब लड़की और पानी की कोई जाति नहीं जैसी सुविधापूर्ण अवधारणा सामने आई. इसी प्रक्रिया में जल निकायों के इर्द–गिर्द लगने वाला मजमा ख़त्म होता चला गया. पनघट और घाटों से लोग दूर हो गए और इस दूरी के कारण जन का जल से संवेदनात्मक संबंध बिसरता चला गया. पर्यावरण और नीतिगत असंतुलन से समाज की बेहद पुरानी जल व्यवस्था चरमराती चली गई. जल निकाय पहले लोगों द्वारा संरक्षित होते थे, जो बाद में ठेकेदारी प्रथा की भेंट चढ़ने को मजबूर हुए. किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि पानी किसी भी समाज का बेहद निजी मामला है, सरकार की भूमिका तो सिर्फ़ व्यवस्था संचालक की है. जबकि आज़ादी के बाद तो जल निकायों और आदमी के हलक के बीच के रिश्तों को सरकार ने व्याख्यायित करने का ज़िम्मा ले लिया. नदी–नालों का पानी खेत तक पहुंचाने का काम तो अंग्रेजों ने बहुत पहले ही शुरू किया था. आहर–तालाब के साथ हिकारतपूर्ण व्यवहार से शुरू हुई कहानी नहरों के निर्माण, भू–जल के दोहन से गुजरते हुए बोतलबंद पानी तक जा पहुंची है. उड़ीसा के रायगड़ा जैसे बेहद पिछड़े इलाक़े में पेयजल उपलब्ध करा पाने में सरकार ने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन वहां बोतलबंद पानी का बाज़ार फल–फूल रहा है.

उल्लेखनीय है कि इस ज़िले में हर साल आंत्रशोथ जैसी जलजनित बीमारी से सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं. यह सच है कि एक पर्यावरणीय वस्तु और सार्वजनिक सेवा दोनों रूपों में पानी सार्वजनिक क्षेत्र की चीज है, मगर वैश्विक बाज़ारवादी व्यवस्था में इसके निजीकरण का माहौल बनता चला गया. इससे ग़रीबों के ख़िलाफ़ माहौल बना है. कहते हैं, तीसरा विश्वयुद्ध पानी की कमी के कारण होगा. यह भविष्य की आशंका है, मगर कई देशों में राजनीतिक धरातल पर पानी का मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है. पोलैंड और पनामा जैसे एक–दूसरे से बिल्कुल भिन्न देशों में नगरपालिका से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के चुनावों में पानी का निजीकरण केंद्रीय मुद्दा रहा है. इसी निजीकरण के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में एक शक्तिशाली अभियान चला था, जिसने थैचर को चुनाव हो जाने तक निजीकरण टालने पर मजबूर कर दिया था. पानी को एक बिकाऊ वस्तु मानने से हमारी सोच और सामाजिक व्यवस्था साफ इंकार करती है. जलाधिकार अभियान, जल लोकतंत्र के वास्ते नागरिक मंच, जलकर्मी गठबंधन और पानी मोर्चा के ज़रिए दिल्ली की जल व्यवस्था के निजीकरण को रोकने की सफल कोशिश तो सबको पता है. उधर मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में जल संसद गठित कर जल निकायों को नई ज़िंदगी देने की सफल कोशिश जारी है.

पानी समाज का सांझा संसाधन और बुनियादी मानवाधिकार है, लेकिन मैक्सिको, घाना, ब्राजील एवं कोलंबिया सहित तीन दर्जन से अधिक देशों में पानी के निजीकरण के कारण सामाजिक संघर्ष जारी है. वहां की सरकारें भी अब महसूस कर रही हैं कि नदियां और पानी बिकाऊ नहीं हैं, बल्कि जलापूर्ति और जल निकायों का रखरखाव सामाजिक सहभागिता से संभव हो सकता है. मलेशिया के पेनांग जैसे कई शहरों में सार्वजनिक सेवा के लोकाचार ने जलापूर्ति को सुगम और सर्वसुलभ बनाया है.

जलकर्मियों की सहकारी एवं कुछ ग़ैर सरकारी संस्थाएं अर्जेंटीना और बांग्लादेश के शहरों में जलापूर्ति का काम भी कर रही हैं. घाना के सावेलुगु में तो नदियों के रखरखाव और संरक्षण के लिए जनता को विशेषाधिकार दिए जाने की मांग हो रही है. उल्लेखनीय है कि एनरॉन की सहायक कंपनी आजुरिक्स ने घाना में पानी के निजीकरण के लिए 1995 में एक मंत्री को 50 लाख डॉलर की रिश्वत दी थी, जो बाद में जगज़ाहिर हुई. यही बात 1996 के राष्ट्रीय चुनाव में मुद्दा बनी और सरकार के लिए नुक़सानदेह साबित हुई.

हमारे देश में भी जलसंकट लगातार गहराता जा रहा है. पहाड़ी इलाक़ों से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक कोई आदमी इस संकट से अछूता नहीं है. पानी बेचने का खेल यहां भी जारी है. जल निकायों के निजीकरण की बातें बार–बार उभरती हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां के जल निकायों एवं भू–जलस्रोतों को हड़प रही हैं. इस बारे में जो भी नियम–क़ानून हैं, उनके शब्द मुर्दा हो चुके हैं. एक आम आदमी को पानी चाहिए, यह उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है. न जाने क्यों कोई नागरिक मंच या राजनीतिक दल इसे लोकतांत्रिक मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं. उदाहरण हमारे सामने है, दक्षिण अफ्रीका में पानी तक आम आदमी की पहुंच एक संवैधानिक अधिकार है. हाल में उरुग्वे में एक जनमत संग्रह ने जल के निजीकरण को संविधान के तहत अवैध घोषित किए जाने का समर्थन किया. क्या पंचायतों के ज़रिए हम जल निकायों को जनता के हाथों में सौंपकर जल से जुड़ी अपनी प्राचीन संस्कृति फिर से जीवित नहीं कर सकते? मनरेगा के प्रचारकों से यह सवाल खास तौर से है. जल से जन को दूर करने वालों को जनमत के ज़रिए नसीहत देने का काम कब से शुरू होगा?

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... नीतीश, इंडियन ऑफ द इयर! ...धीर

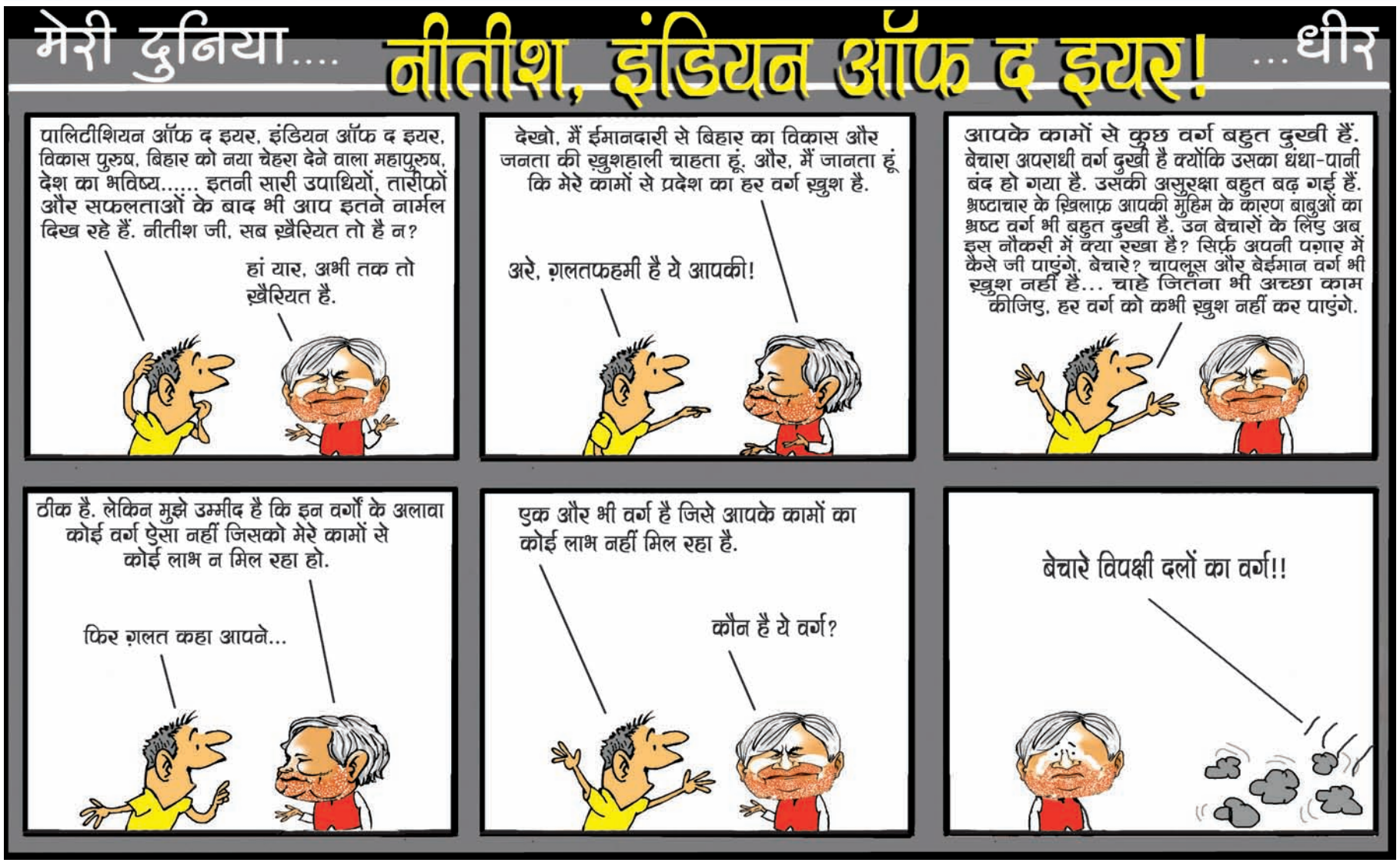

सोड़ा गांव

फिर से सजने लगी चौपाल

गांवों की दशा सुधारने के लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है. ऐसा आंदोलन, जो ग्रामसभा को मज़बूत बनाए और पंचायती व्यवस्था में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित कर सके. ऐसा आंदोलन किसी राजनीतिक दल से नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके अपने निहित स्वार्थ होते हैं. सांसद या विधायक बनकर देश सुधारने का दम भरने वाले आवेशित युवाओं के बल पर भी यह आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता. इसके लिए ज़रूरत है ऐसे लोगों की, जो अपने गांव को राजनीतिक रूप से सुधारने के लिए काम करें. मसलन, छवि राजावत, जो एमबीए की पढ़ाई करने के बाद भी अपने गांव आती हैं और उसके विकास के लिए काम करती हैं.

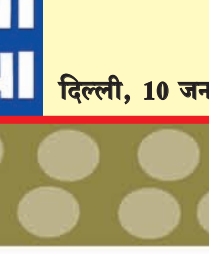

शशि शेखर

भारत में लोकतंत्र का अर्थ लोक नियुक्त तंत्र बना दिया गया है, जबकि इसे लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए था. संविधान द्वारा तंत्र संरक्षक की भूमिका में स्थापित है, जबकि उसे प्रबंधक की भूमिका में होना चाहिए था. ज़ाहिर है, संरक्षक लगातार शक्तिशाली होता चला गया और धीरे-धीरे समाज को गुलाम समझने लगा. तंत्र आदेश देता है और लोक पालन करता है. लोक और तंत्र के बीच दूरी बढ़ती ही जा रही है. इस दूरी को कम करने के लिए ग्रामसभा को मज़बूत करना ही एकमात्र उपाय है. निष्क्रिय ग्रामसभा में जान फूंकने की ज़रूरत है. ख़ुशी की बात यह है कि देश के कुछ हिस्सों में ऐसे प्रयास ज़ोर-शोर से शुरू हो गए हैं और यही प्रयास उम्मीद भी जगाते हैं. राजस्थान के टौंक ज़िले के सोड़ा गांव में एक पेड़ के नीचे चौपाल सजी है. गांव के क़रीब 70-80 लोग बैठकर राशन के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं. किसी ने बैठक में मुद्दा उठाया था कि दुकान खुलने और राशन के आने-बंटने का समय पता ही नहीं चलता. हालांकि इस बारे में सरकारी नियम भी हैं, लेकिन उनकी न तो जानकारी है और शायद न ही ज़रूरत. आरोप लगाने वाले को तो सिर्फ़ इतनी जानकारी चाहिए कि राशन की दुकान में अगले महीने राशन कब मिलेगा. राशन दुकानदार ख़ुद बैठक में नहीं है, लेकिन उसके चाचा उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ग्रामसभा में सबके सामने मुद्दा उठाए जाने से वह ख़फ़ा हो जाते हैं और ज़ोर- ज़ोर से बोलने लगते हैं. लेकिन उनकी दबंगई काम नहीं आती, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग आरोपी के साथ खुलकर नहीं बोल रहे थे, तब भी थे तो उसी के साथ. बहस बढ़ती है तो कई लोग बीच-बचाव करते हैं कि भाई, बंदे ने सिर्फ़ पूछा है, आपका नाम लेकर कोई आरोप थोड़े ही लगाया है. तभी गांव की सरपंच इसका समाधान सुझाती हैं कि राशन दुकान के सामने एक बोर्ड लगा दिया जाए और उस पर दुकान खुलने और राशन मिलने का वास्तविक दिन एवं समय लिख दिया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बोर्ड पर लिखे हुए दिन-समय पर लोग आएं तो उन्हें राशन मिले. सारी सभा एकदम इससे सहमत होती है और हाथ उठाकर इसे मंज़ूर करती है. राशन दुकानदार के चाचा भी इससे सहमत हो जाते हैं. गांव वालों को भरोसा है कि चाचा ने ग्रामसभा में वादा किया है तो अब यह काम ज़रूर हो जाएगा.

ग्रामसभा का एक और फ़ायदा हुआ, अतिक्रमण हटाना. तीन महीने में ही गांव के लोगों ने बातचीत के ज़रिए तालाब की ज़मीन पर बने बाड़े हटवा दिए. एक महिला पंच ने गोचर ज़मीन पर धार्मिक चबूतरा बनाना शुरू किया तो उसे भी इन बैठकों में ही समझा दिया गया और अब उसने अपनी जिद छोड़ दी है. एक पंच सदस्य का कहना है कि पहले जो काम होता था, वह सरपंच की मनमर्जी से हुआ करता था. वह जो-जहां चाहता था, वही होता था.

धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, ग़रीब-अमीर या किसान-मज़दूर का भेदभाव ही दरअसल किसी ग्रामसभा और पंचायत को कमज़ोर बनाता है. भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत व्यवस्था आज के दौर में गांवों के संपूर्ण विकास की पहली शर्त है. वर्तमान समय में ग्रामसभाओं की निष्क्रियता के कारण सरकारी पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार है. जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी मिलकर मनमानी करते हैं और भ्रष्टाचार भी. ग्रामसभा के नाम पर कुछ लोगों के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और खानापूर्ति हो जाती है. वास्तविक ग्रामसभा बैठती ही नही है, लेकिन कुछ नए और ऊर्जावान लोगों की बदौलत यह तस्वीर बदल रही है. सोड़ा गांव में अब ऐसी बैठकें हर महीने हो रही हैं. गांव की नवनिर्वाचित युवा सरपंच छवि राजावत जींस-टीशर्ट पहने इन बैठकों को संचालित करती हैं. एमबीए करने के बाद सरपंच बनी लड़की की कहानी राष्ट्रीय मीडिया में ख़ूब छाई रही थी, लेकिन छवि की उम्र और अनुभव गांव के मुक़ाबले कहीं कम है. गांव की राजनीति में एमबीए की डिग्री लेते वक़्त पढ़ाई गई बातें भी कुछ ख़ास काम नहीं आतीं, लेकिन छवि ने तीन महीने में तीन बैठकें बुलाकर इसका तोड़ निकाल लिया है. गांव के एक नौजवान जसवंत सोनी कहते हैं कि जब यह पढ़ी-लिखी लड़की सरपंच बनी तो हमें लगा कि यह तो ज़्यादातर जयपुर स्थित अपने घर में रहेगी, गांव का क्या विकास करेगी, लेकिन जब गांव के बीच बाज़ार में ग्रामसभा की खुली बैठक बुलाई गई और उसमें लोगों से पूछा गया कि गांव के विकास की शुरुआत कहां से हो, तो हमें लगा कि अब गांव वाकई सुधरेगा.

ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान है. लोग बैठकों के आदी नहीं हैं, छवि बताती हैं, पहली बैठक में लोग आए तो उन्हें लगा कि वे भाषण सुनने आए हैं. मैं चुप रही और मैंने हर आदमी से बोलने के लिए कहा. पहले तो सब हिचके, लेकिन बाद में सब लोग खुलकर बोले. सबने गांव को लेकर अपना-अपना सपना साझा किया. तीन महीने का समय कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन गांव में पंचायत की प्राथमिकताएं तय हो गई हैं. सबसे पहले लक्ष्य रखा गया है कि गांव के 150 बीघे के तालाब के आधे हिस्से की खुदाई कराई जाए. कई वर्षों से इस तालाब की खुदाई नहीं हुई है और यह सूखा मैदान लगता है. अर्से से जमी काली मिट्टी की खुदाई नरेगा के तहत कराना आसान नहीं था. वह भी तब, जब बारिश आने में सिर्फ़ एक महीना बाक़ी हो. इसलिए सबसे राय-मशविरा करके तय किया गया कि जेसीबी मशीनें लगा दी जाएं. इसके लिए क़रीब 70 लाख रुपये की ज़रूरत थी. सरकार की कोई योजना नहीं थी कि इस तरह का काम मशीनों से कराकर गांव के तालाबों को सुधार लिया जाए. अफसरों ने साफ़ हाथ खड़े कर दिए. यहां काम आई सरपंच की एमबीए की पढ़ाई. साथ पढ़े युवक-युवतियों, जो अब बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ने तालाब की खुदाई के लिए चंदा इकट्ठा किया.

ग्रामसभा का एक और फ़ायदा हुआ, अतिक्रमण हटाना. तीन महीने में ही गांव के लोगों ने बातचीत के ज़रिए तालाब की ज़मीन पर बने बाड़े हटवा दिए. एक महिला पंच ने गोचर ज़मीन पर धार्मिक चबूतरा बनाना शुरू किया तो उसे भी इन बैठकों में ही समझा दिया गया और अब उसने अपनी जिद छोड़ दी है. एक पंच सदस्य का कहना है कि पहले जो काम होता था, वह सरपंच की मनमर्जी से हुआ करता था. वह जो-जहां चाहता था, वही होता था. अब जो काम हो रहा है, वह सभी सदस्यों और गांव के बुज़ुर्गों से राय लेकर उनके मन मुताबिक हो रहा है. वह कहते हैं कि 11 पंच पूरे गांव की भावनाओं को थोड़े ही समझ सकते हैं. जब हर व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश होगी, तभी पता चलेगा कि गांव क्या चाहता है. गांव के पंच हों या अन्य प्रभावशाली लोग, सरपंच छवि राजावत के लिए सबकी राजनीति से निपटने का एक ही तरीक़ा है, गांव के लोगों को इकट्ठा करके फ़ैसला लेना. गांव का विकास उनका सपना है, लेकिन वह अपना सपना और ज्ञान लोगों पर थोपना नहीं चाहतीं. पंचायत और उसके कर्मचारी क्या काम करेंगे, यह गांव के लोगों की मौजूदगी में तय होता है.

गांव के पंचों और आम लोगों को समझाना शायद आसान है, लेकिन जब बात पंचायत के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों की आती है तो मामला टेढ़ा हो जाता है. ग्रामसभा की पहली बैठक में ही जब सचिव को बैठक के मिनिट्स बनाने के लिए कहा गया तो पहले उसने बाद में बनाने को कहा, लेकिन सबके सामने कहे जाने का असर हुआ. बैठक के मिनिट्स बने. मिनिट्स के नीचे लोगों ने अपने दस्तखत या अंगूठे भी लगा दिए. सचिव ने जानबूझ कर मिनिट्स और दस्तखतों के बीच एक लाइन खाली छोड़ दी. अगले दिन सरपंच ने अचानक देखा कि इस लाइन में गांव के राशन डीलर के पक्ष में एक फ़ैसला लिख दिया गया, जबकि उस बैठक में राशन के मुद्दे पर चर्चा भी नहीं हुई थी. इस लाइन को हटवा दिया गया, लेकिन सरपंच को अपने इशारों पर चलाते रहे ग्राम सचिव को नई सरपंच का ग्रामसभा की बैठक कराना अच्छा नहीं लग रहा.

शायद यही वह जगह है, जहां हमारे देश का पंचायती राज का सपना अटक गया है. कहने को पंचायत को हम तीसरे स्तर की सरकार कहते हैं, लेकिन अपने एक भी कर्मचारी पर इस सरकार का नियंत्रण नहीं है. सब के सब राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह हैं. पूरा का पूरा पंचायती राज अफसरों के हवाले है. इसे अफसरों के चंगुल से निकाल कर स्वतंत्र करना किसी आंदोलन के बिना संभव नहीं है. ऐसा आंदोलन किसी राजनीतिक दल से नहीं निकल सकता. सांसद या विधायक बनकर देश सुधारने का दम भरने वाले आवेशित युवाओं के बल पर भी यह आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता. इसके लिए ज़रूरत है ऐसे लोगों की, जो अपने गांव को राजनीतिक रूप से सुधारने के लिए काम करें.

shashishekhar@chauthiduniya.com

युवा वर्ग का आज के परिवेश में क्या दायित्व बनता है, इसका इस वर्ग को न तो बोध है और न इसे बोध कराने वाला कोई मार्गदर्शक. बीते वर्ष मानवता को शर्मसार करने वाले ज़ालिमों के नाम रहे.

सोनिया गांधी का यह दावा कि कांग्रेस कभी सांप्रदायिकता से लोहा लेने से पीछे नहीं हटी, भी एक अर्धसत्य है.

मेघनाद देसाई

कांग्रेस को नए विचारों की ज़रूरत है

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने एक बार कहा था कि राजनीति में एक सप्ताह का समय बहुत लंबा होता है. कांग्रेस महाअधिवेशन का आयोजन बड़े आत्मविश्वास के साथ हुआ, लेकिन इसका अर्थ वफादार कांग्रेसियों के लिए थकाऊ और बार-बार दोहराने वाली प्रक्रिया बनकर रह गया. कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया कि कांग्रेस अब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक गंभीर वैधानिक कार्यक्रम की शुरुआत करेगी. सोनिया गांधी ने कुछ उपायों को नोट ज़रूर किया, लेकिन इस संबंध में कोई विधेयक तैयार किया जाएगा, इसका वादा नहीं कर सकीं. इस बात की भी शेख़ी बघारी गई कि जिन मंत्रियों के नाम भी संदेह के घेरे में आए, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया. लेकिन लोगों ने क्या देखा? आम आदमी ने यह देखा कि इस्तीफ़े के बाद उन मंत्रियों का कुछ नहीं हुआ. कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहां तक कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सुरेश कलमाडी के घर पर पड़े छापे और ए राजा से हुई पूछताछ से यही संकेत मिलता है कि कांग्रेस अब हताश होती जा रही है और यह कार्रवाई भी उसी का परिणाम है.

विपक्ष को देने के लिए कांग्रेस के पास दो अन्य जवाब और हैं. एक तो यह कि भाजपा (एनडीए) की सरकार कांग्रेस (यूपीए) की सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट थी. यह एक अच्छे राजनीतिक मतभेद का परिणाम हो सकता है, लेकिन लोगों को पता है कि उनके पास दो बुरे लोगों में से ही किसी एक को चुनने का विकल्प उपलब्ध है. विपक्ष ने सरकार को ठप्प करके सरकार में निराशा के भाव पैदा कर दिए हैं. कांग्रेस महाअधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वह पीएसी (लोक लेखा समिति) के समक्ष उपस्थित होने को तैयार हैं, लेकिन जेपीसी के समक्ष नहीं. हालांकि जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यह कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था. इसके बाद प्रणव मुखर्जी संसद का विशेष सत्र बुलाने का निमंत्रण इस शर्त पर देते नज़र आए कि इसमें जेपीसी पर बहस होगी. इस तरह जेपीसी की मांग को मानने के लिए दूसरा क़दम उठाया जा चुका था. विपक्ष आने वाले बजट सत्र को भी हंगामे की भेंट चढ़ाने की धमकी दे चुका है. मैं समझता हूं कि अंतिम स्थिति यही होगी, जो विपक्ष चाहता है. जेपीसी के मुद्दे पर यदि लोकसभा में वोटिंग होती है तो तृणमूल यूपीए के ख़िलाफ़ ही मतदान करेगी. यदि कांग्रेस डीएमके को संतुष्ट करके उसे मिलाने की कोशिश करती है तो उसके उन भ्रष्टाचार विरोधी दावों की कलई खुल जाएगी, जो उसने अपने अधिवेशन के दौरान किए थे.

बराक ओबामा के भारत से जाने के बाद से भारतीय राजनीति कुछ बड़ी चुनौतियों से दो-चार हो रही है. वेस्टमिंस्टर शैली की राजनीति में बहुमत की सरकार हमेशा फ़ायदे उठाने की स्थिति में रहती है. कांग्रेस 1947 से 1989 के बीच यानी 42 सालों के दौरान बहुमत की सरकार के तौर पर ऐसे ही विशेषाधिकारों का मज़ा लेती रही है. मैं सोचता हूं कि यह अभी भी संसद में ख़ुद को अच्छी स्थिति में बनाए रख सकती है और किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकती है. न्यूक्लियर डील के मामले में हुई वोटिंग पर भी कांग्रेस कुछ इसी तरह से जीती थी, लेकिन इस बार विपक्ष को सुरक्षा कवच में पड़ी दरार का पता लग चुका है. संसद की कार्यवाही ठप्प करके उसने एक ऐसी तकनीक ईजाद कर ली है, जो काफ़ी प्रभावी साबित हुई है.

बराक ओबामा के भारत से जाने के बाद से भारतीय राजनीति कुछ बड़ी चुनौतियों से दो-चार हो रही है. वेस्टमिंस्टर शैली की राजनीति में बहुमत की सरकार हमेशा फ़ायदे उठाने की स्थिति में रहती है.

यही कारण है कि विपक्ष अब कांग्रेस से सौदा करने को इच्छुक नहीं दिख रहा है. 2-जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी, सीडब्ल्यूजी एवं राडिया टेप जैसे घोटाले एक साथ धमाका करने लगे और इन घोटालों ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया. कांग्रेस तहलका की बात करती है, लेकिन यह कल की बात है और आज के घोटालों के सामने यह कुछ भी नहीं था. अब कांग्रेस अपना दूसरा हथियार निकालती है. यह सांप्रदायिक कार्ड था. आरएसएस को हिंदू आतंकी संगठन साबित करना ही कांग्रेस की नई रणनीति है. इसी बीच दिग्विजय सिंह द्वारा छोड़े गए नए शिगूफे, जिसे वह साबित नहीं कर पाए कि हेमंत करकरे ने आरएसएस से अपनी जान को ख़तरा बताया था, पर भी पलीता लग गया. लेकिन कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भी ऐसे आरोपों को दोहराया गया.

हालांकि सांप्रदायिक कार्ड अब उतना प्रभावकारी नहीं रहा, जितना यह कभी हुआ करता था. कांग्रेस तब दिग्भ्रमित थी, जब राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद प्रकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था. उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी सहयोगी भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हुए भी मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में शानदार जीत दर्ज की. आम आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है और न ही वे मुस्लिम या दलित भी, जो कांग्रेस के सबसे विश्वसनीय वोटबैंक रहे हैं. ये देख रहे हैं कि उत्तर भारत में कांग्रेस सो रही है और एक-एक करके दूसरी पार्टियां सरकार बनाती जा रही हैं. कांग्रेस को अब नए विचारों की ज़रूरत है, नए आइडिया की ज़रूरत है. कांग्रेस महाअधिवेशन से यही साबित हुआ है कि 125 साल पुरानी पार्टी की टोकरी बिल्कुल ख़ाली है रणनीति के मामले में, विचारों के मामले में.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आइए नए साल का स्वागत करें

दो हज़ार दस ने हमें रंगों का विद्रूप रूप दिखाया. एक तरफ कॉमनवेल्थ में हुए घोटाले के आरोपी मुस्कराते दिखे, टूजी स्पेक्ट्रम के मुजरिम मुस्कराते सीबीआई के दफ्तर गए और मुस्कराते ही बाहर आए. दूसरी तरफ़ मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले डॉ. विनायक सेन को अदालत ने उम्रक़ैद की सज़ा दे दी. अदालतें सबूत पर चलती हैं और सबूत पुलिस गढ़ती है. ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे पुलिस देशद्रोही मान रही है, उसके पक्ष में देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा विश्व के उन्नीस नोबेल पुरस्कार विजेता खड़े हो जाएं. आपको एक तथ्य बता दें, पंडित जवाहर लाल जी के ख़िलाफ़, डॉ. लोहिया के ख़िलाफ़, लोकनायक जय प्रकाश नारायण के ख़िलाफ़, आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के ख़िलाफ़ तथा विपक्ष के अधिकांश नेताओं के ख़िलाफ़ धारा 120 और धारा 120 बी के अंतर्गत केस दर्ज हुए और इन्हें कुछ नहीं हुआ. ये धाराएं अंग्रेजों ने बनाई थीं. आज तक इनका इस्तेमाल हो रहा है. राजनैतिक आंदोलनों में जो भी लोग जेल जाते हैं, पुलिस शांति भंग के साथ इन धाराओं को भी लगा देती है. ये धाराएं देशद्रोह की धाराएं हैं.

इन धाराओं का जिन पर इस्तेमाल हुआ है, उनमें प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी तथा लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग शामिल हैं. ये धाराएं जैसे लगती हैं, वैसे ही वापस होती हैं. लेकिन विनायक सेन के साथ ऐसा नहीं हुआ. छत्तीसगढ़ में ग़रीबी है, बेकारी है तो इनके ख़िलाफ़ गुस्सा भी है. नक्सलवादी वहां हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है. नक्सलवादियों के नाम पर बहुत से निर्दोषों को भी पुलिस सताती है. निर्दोषों के पक्ष की आवाज़ उठाना आजकल देशद्रोह हो गया है.

किसी भी तरह की आवाज़ क्यों उठे! सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले डराए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं. यहां तक कि मारे भी जा रहे हैं. संसद ने जनता के हाथ में ताक़त दी है, लेकिन जिनकी लूट खसोट पर आंच आ रही है, वे चाहते हैं कि कोई इस क़ानून का इस्तेमाल न करे. सरकारी अधिकारी भी चाहते हैं कि या तो यह क़ानून बदल दिया जाए या इसकी ताक़त ख़त्म कर दी जाए. इसकी वे जी-जान से कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि राजनेता उनका साथ दें. वैसे यह दो हज़ार दस में नहीं हो पाया, दो हज़ार ग्यारह में भी नहीं हो पाएगा, कहा नहीं जा सकता.

दो हज़ार दस ने जनता के विश्वास को ध्वंस कर दिया. भारत के लोगों का विश्वास लोकतंत्र में है और लोकतंत्र के तीनों अंगों का चेहरा पिछले साल धुंधला गया. न्यायपालिका के ऊपर न्यायपालिका ने हमला किया. सुप्रीमकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर न केवल टिप्पणी की, बल्कि उस टिप्पणी को हटाने वाली याचिका भी ख़ारिज कर दी. देश की अदालतों के बारे में लोगों के बीच क्या बातें होती हैं, इसे इनसे रिश्ता रखने वाले सभी जानते हैं. जजों के ऊपर रिटायर होने के बाद आरोप लग रहे हैं तथा सीबीआई अदालतों में जजों के ऊपर चार्जशीट दायर हुई.

संसद अब बुनियादी बहस या नए सपने को उतारने के लिए क़ानून बनाने वाला लोकतंत्र का मंदिर नहीं रहा. संसद सदस्यों के पास न बहस के विषय हैं और न तर्क. अगर मीडिया विषय न दे तो शायद जितना कोरम संसद में रहता है, उतना भी न हो. इतिहास में पहली बार संसद नहीं चली. विपक्ष और सरकार ने ऐसा मान लिया, मानों वे सर्वशक्तिमान हैं. शायद हैं भी, जब तक जनता उन्हें मानती है, तभी तक. कार्यपालिका के साथ मीडिया ने भी दो हज़ार दस में साख खोई. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, यह कहावत एक बार फिर सही साबित हुई. कुछ बड़े पत्रकार नीरा राडिया के साथ मंत्री बनाने के खेल में पकड़े गए. कई पत्रकार बड़े संपर्क अधिकारी जैसा काम करते हैं. और अब कहने वाले कहने लगे हैं कि पत्रकारों को साथ लो, अच्छे दलाल बन सकते हैं.

बीते साल ने अच्छी यादें कम और बुरी यादें ज़्यादा दी हैं. अच्छी बात केवल एक रही, बिहार में जनता का फ़ैसला, जिसने धर्म और जाति के परे जाकर निर्णय दिया और सिर्फ़ बातें करने वालों को नकार दिया. आशा इस बात की करनी चाहिए कि बिहार जैसा फ़ैसला बाकी प्रदेशों की जनता भी लेगी. क्या दो हज़ार ग्यारह में आशा की जाए कि देश को कुछ ऐसी उपलब्धि होगी, जिसका फ़ायदा ग़रीब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक तथा उन सबको होगा, जो देश में लोकतंत्र चाहते हैं.

राहुल गांधी कांग्रेस की आज आशा भी हैं और भविष्य भी. इसलिए कांग्रेस न बिहार को याद रखना चाहती है और न बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए कोई योजना ही बनाना चाहती है. दो हज़ार दस में फुसफुसाहट थी, पर दो हज़ार ग्यारह में खुलकर मांग होगी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए. कांग्रेस का एक वर्ग है, जो दो हज़ार चौदह का इंतजार नहीं करना चाहता. दो हज़ार दस में भाजपा में जहां सार्थक विपक्ष बनने की इच्छा ख़त्म होती लगी, वहीं नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी भाजपा के नए ट्रेंड सेटर बनकर उभरे. भाजपा में अनुशासनहीनता का खुलकर प्रदर्शन हुआ. पूरी भाजपा चाहती थी कि येदुरप्पा इस्तीफ़ा दें, पर उन्होंने पूरे नेतृत्व को नचा दिया. इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व के महत्वपूर्ण लोगों के न चाहने के बाद भी अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने. विपक्षी दल की जगह भाजपा रीति-नीति में कांग्रेस से होड़ लेती दिखाई दी.

बीते साल ने अच्छी यादें कम और बुरी यादें ज़्यादा दी हैं. अच्छी बात केवल एक रही, बिहार में जनता का फ़ैसला, जिसने धर्म और जाति के परे जाकर निर्णय दिया और सिर्फ़ बातें करने वालों को नकार दिया. आशा इस बात की करनी चाहिए कि बिहार जैसा फ़ैसला बाकी प्रदेशों की जनता भी लेगी. जनता के नज़रिए से दो हज़ार दस किसानों की आत्महत्या के लिए भी जाना जाएगा. क्या दो हज़ार ग्यारह में आशा की जाए कि देश को कुछ ऐसी उपलब्धि होगी, जिसका फ़ायदा ग़रीब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक तथा उन सबको होगा, जो देश में लोकतंत्र चाहते हैं. आइए नए साल का इसी आशा के साथ बाहें फैलाकर स्वागत करें.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

ख़ुशियां तो व्यवस्था परिवर्तन से आएंगी

मानव सभ्यता का एक और वर्ष व्यतीत हो गया. पुरानी यादें-कड़वाहटें जेहन में बसाए, नववर्ष आगमन के हर्षोल्लास में मनुष्य आशामयी जीवन जीने की तमन्ना अपने हृदय में संजोए है. एक-दूसरे को नववर्ष मंगलमय हो का संदेश देना भी आज महज़ एक औपचारिकता बनकर रह गया है. पुरानी बातों को भूलने की अद्‌भुत क्षमता वाला मनुष्य सिर्फ़ और सिर्फ़ आशा के सहारे वर्ष 2011 में अपनी तरक्की के सपने देख सकता है. हो सकता है कि 2010 किसी पूंजीपति के लिए, व्यवसायिक घराने के लिए मंगलकारी रहा हो. संभव है कि किसी राजनीतिक दल या राजनेता को तरक्की हासिल हुई हो, विकास का लाभ मिला हो. पर यह ध्रुव सत्य है कि आम नागरिक तो 2010 में भी सिर्फ़ ठगा ही गया. 2010 में जो भी उम्मीद का, तरक्की का ख्वाब आम नागरिक की आंखों में आया, उसे महंगाई और राजनेताओं-नौकरशाहों के ग़ैर ज़िम्मेदाराना रवैये ने चकनाचूर कर दिया.

मध्यम वर्ग इस आशा और विश्वास के सहारे है कि हो सकता है, 2011 में उसके जीवनयापन की दशा सुधरे, उसका आत्मविकास हो. उम्मीद की तरंगों पर सवार होकर उसने 2011 का स्वागत टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले रंगारंग कार्यक्रम देखकर किया. नववर्ष के स्वागत में जगह-जगह जलसे तो बहुत हुए, लेकिन वे किसी दुखियारे, ग़रीब, बेबस, मज़दूर, किसान एवं बेसहारा की झोपड़ी में उम्मीद की एक किरण नहीं जगा पाए. पूंजीवाद का घिनौना तांडव ऐसे मौक़ों पर अक्सर देखने को मिलता है. शराब की नदियां बहा दी जाती हैं, भोग-विलास का शर्मनाक प्रदर्शन लगभग हर होटल में देखने को मिल जाता है. प्रत्येक वर्ष ग़रीबी का मज़ाक उड़ाते हुए लाखों-करोड़ों रुपये नववर्ष के स्वागत के बहाने पानी की तरह सिर्फ़ मौजमस्ती के लिए रातोंरात बहा दिए जाते हैं. एक तरफ़ भूख से बेहाल लोग, दूध को तरसते नौनिहाल हैं और दूसरी तरफ़ नाना प्रकार के व्यंजन एवं जी भरकर पीने को उपलब्ध शराब! यह सामाजिक-आर्थिक असमानता हमें कहां ले जाएगी? पूंजीवाद का वीभत्स-क्रूर प्रदर्शन ग़रीबों-मेहनतकशों का मज़ाक उड़ाते हुए जारी है.

अब नववर्ष के स्वागत में मानवता का भी ध्यान रखना प्रारंभ हो. हम अपने पड़ोसी के साथ संबंध सुधार सकते हैं, भूखे को खाना खिलाकर, ज़रूरतमंदों को वस्त्र देकर भी हम नववर्ष की खुशियां आपस में बांट सकते हैं. हम मेहनतकशों, किसानों के साथ बैठकर उनके दु:ख-दर्द समझने, उन्हें कम करने की एक साझा कोशिश भी कर सकते हैं. आज हमें अपनी तरक्की के रास्ते नि:संदेह पास-पड़ोस एवं देश-समाज की तरक्की से जोड़कर देखने पड़ेंगे. हमें नववर्ष में व्यक्तिगत हितों की बलि समाज-देशहित में चढ़ाने की पुन: शुरुआत करनी चाहिए. मानव सभ्यता की आधी आबादी यानी स्त्री आज कई चुनौतियों से बेजार है. वह बढ़ती पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में असहाय-असहज होती जा रही है. वह नौकरी-व्यवसाय की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ घर-गृहस्थी के दायित्व निर्वहन को विवश है. क़स्बों-ग्रामीण अंचलों में वह सीमित आय में मन मसोस कर परिवार का मान-सम्मान और चूल्हे की आग बरकरार रखने की ज़द्दोजहद में लगी रहती है. स्कूली छात्र-छात्राओं की अपनी अलग कहानी है. समुचित मार्गदर्शन, निगरानी एवं नैतिक मूल्यों के अभाव में युवा वर्ग अक्सर पार्कों, सिनेमाघरों, चौराहों एवं रेस्तरां में मटरगश्ती करता देखा जा सकता है. पैसा कमाने के फेर में फंसा इंसान परिवार को समय नहीं दे पा रहा है. उसे अपने परिवार के विखंडन एवं नैतिक पतन की तरफ़ देखने की फुर्सत नहीं है. इस प्राथमिक इकाई के विखंडन का दंश संपूर्ण समाज को भुगतना पड़ रहा है. नववर्ष में परिवार की तरफ़ ध्यान देना यदि प्रारंभ हो तो अवश्य ही मंगलकारी वातावरण उत्पन्न होगा.

युवा वर्ग का आज के परिवेश में क्या दायित्व बनता है, इसका इस वर्ग को न तो बोध है और न इसे बोध कराने वाला कोई मार्गदर्शक. बीते वर्ष मानवता को शर्मसार करने वाले ज़ालिमों के नाम रहे. वे ज़ालिम आज भी हमारा राशन-पानी खा रहे हैं और हमारे लोग भूखे पेट सो रहे हैं. सरकारों की अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता के चलते देश आतंक का शिकार रहा. राजनीतिक दलों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, मानवाधिकार संगठनों की अनावश्यक चिल्ल-पों के चलते आतंक के पैरोकार मानवता और देश की सुरक्षा पर भारी रहे. याद करिए, स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरशाह जफर को आगे करके पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत से युद्ध किया गया. मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बलभद्र सिंह चहलारी, उदा देवी, अवंतीबाई आदि का बलिदान हमारे लिए ही था. कालांतर में बाल-पाल-लाल की तिगड़ी के साथ महात्मा गांधी, सावरकर एवं चाफेकर बंधुओं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफ़ाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, शचींद्र नाथ सान्याल, रानी गिडालू, प्रीतिलता वादेदार और अरुणा आसफ अली आदि की क्रांतिकारी टुकड़ियों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके गुलामी की बेड़ियां काट डालीं. महात्मा गांधी के विशाल नेतृत्व और क्रांतिकारियों के अदम्य साहस एवं सर्वस्व बलिदान की उच्च परंपरा ने अंग्रेजों को भारत की पवित्र भूमि से भागने पर विवश कर दिया था. फिर आया 1977. आज़ाद भारत में पुन: एक बुज़ुर्ग कराहती जनता का दु:ख हरने, अपने बीमार शरीर की परवाह करे बग़ैर क्रांति की मशाल लेकर घूमने लगा. जय प्रकाश नारायण की अगुवाई में समूचे भारत में तरुणाई ने अंगड़ाई लेकर भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंका. सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के ओजपूर्ण आह्वान ने समूचे जनमानस में उत्साह और सरकारों में भय भर दिया. दुर्भाग्यवश जेपी द्वारा छेड़ी गई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बनकर रह गई. 1977 के आंदोलन से निकले नेताओं ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई छोड़कर सत्ता से चिपके रहना अंगीकार कर लिया. गांधी, लोहिया एवं जेपी की आत्मा अपने इन छद्म अनुयायी नेताओं और इनके कृत्यों को देखकर अवश्य रोती होगी. आज युवाओं को सही नेतृत्व न देने का जो अपराध बुज़ुर्ग नेता कर रहे हैं, उस पर भी काल की नज़र है. इतिहास साक्षी रहेगा कि गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, लोहिया एवं जय प्रकाश के देश में युवा नेतृत्व के अभाव का ज़िम्मेदार कौन है?

आज 45 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी लोगों, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, साहित्यिक मंडली के हैं, मानवाधिकार संगठन के हैं, नौकरशाह हैं, व्यापारी नेता हैं, किसान नेता हैं, पत्रकार हैं और बुद्धिजीवी हैं, को अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन वर्ष 2011 में प्रारंभ करना चाहिए. क्या इन्होंने एक भी नौजवान को देशप्रेम एवं देश की सुरक्षा के सवाल पर समझाया? क्या इन्होंने किसी किशोर को समाजसेवी या देशभक्त के रूप में तैयार किया? यदि हां तो आप वंदनीय हैं, वरना धिक्कार है आपके जीवन पर! अब प्रण करके नववर्ष 2011 में अपने इस दायित्व को पूर्ण करने की दिशा में प्रयास करें. एक सवाल यह भी है कि क्या अब ऐसा वक़्त आ गया है कि युवा वर्ग अपना नेतृत्व स्वयं करे? बुज़ुर्ग नेता तो सिर्फ़ सियासी गोष्ठी करेंगे. युवा वर्ग को तो उन्होंने अपने, भाई-पुत्र-सगे संबंधियों एवं चाटुकारों के जयकारे लगवाने लायक ही समझ रखा है. अच्छा तो यह होगा कि नववर्ष 2011 में हम मानव मात्र की भलाई के बारे में कार्य करना प्रारंभ करें. एक देश-एक प्राण की भावना का स्थान सिर्फ़ स्वयं हित की सोच ने ले लिया है, इस नववर्ष में इसे बदलना चाहिए. अब तो युवाओं को न तो गांधी मिलेंगे और न जय प्रकाश, उन्हें ख़ुद सरदार भगत सिंह और अन्य अमर क्रांतिकारियों की राह पर चलकर अपना नेतृत्व स्वयं करना होगा. जनता, किसान-मज़दूरों के हक़ की लड़ाई तेज़ करनी होगी. व्यवस्था परिवर्तन के बग़ैर किसी भी समस्या का हल संभव नहीं है. आइए, 2011 में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तेज़ की जाए, तभी नववर्ष के मंगलमय होने की संभावना है.

अरविंद विद्रोही
feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस महाअधिवेशन

संतोष भारतीय द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर लिखा गया लेख पठनीय है. विगत 125 वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनेक रंग-रूप और चेहरे-मोहरे बदले. अपनी 125वीं वर्षगांठ ज़ोर-शोर से मनाती हुई कांग्रेस ने क्या संजीदगी के साथ यह चिंतन करने की जहमत उठाई कि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसके अस्तित्व पर विशेषकर उत्तर भारत में संकट के बादल क्यों छा गए हैं. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में वह सत्ता से बाहर है और उसके फिर से ताक़तवर होने के आसार भी अत्यंत कम हैं. दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पश्चात कर्नाटक भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया. भारत की एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी के तौर पर दीर्घ ऐतिहासिक यात्रा अंजाम देने वाली कांग्रेस को अपने स्वर्णिम इतिहास पर दृष्टिपात करना चाहिए और उन महान नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था.

-प्रभात कुमार राय, ईमेल से.

- कांग्रेस वोट के लिए देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है. हिंदुओं की ख़िलाफ़त करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते. जिस दिन कांग्रेस पानी पी-पीकर भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय ईमानदारी से काम करना शुरू कर देगी, उसी दिन वह देश पर राज करने की हक़दार हो सकेगी. एक ईमानदार मुखौटे के पीछे पूरा भ्रष्ट तंत्र है, इससे काम चलने वाला नहीं है. आज तक कांग्रेस ने महात्मा गांधी का सिर्फ़ नाम भर लिया है, अहिंसा को आज़मा कर नहीं देखा. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अनुशासन का नितांत अभाव है. इसे किसी भी कार्यक्रम से लौटते समय स्टेशनों पर महिलाओं से अभद्र आचरण, लूटपाट और हिंसा के रूप में देखा जा सकता है.

-बलवीर सिंह भटनागर, ईमेल से.

- संतोष भारतीय जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं. मुझे भी जहां तक लगता है कि कांग्रेस की जब-जब सरकार बनी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है. इंदिरा जी-राजीव गांधी का दौर रहा हो या वर्तमान दौर, आख़िर कांग्रेस अपने ही नेताओं के हाथों कठपुतली कैसे बन जाती है? कांग्रेस को अगर सत्ता में बने रहना है तो उसे भ्रष्टाचार के घिनौने दलदल से बाहर निकलना होगा, अपना दामन साफ़ करके लोगों का विश्वास जीतना होगा और शिक्षा-चिकित्सा-विकास जैसे बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा. आज की युवा पीढ़ी जाति-धर्म से ऊपर उठ चुकी है, वह सिर्फ़ विकास चाहती है और कांग्रेस को उसकी इसी सोच और विश्वास को जीतना होगा.

-खादीजा सिद्दीकी, ईमेल से.

सुप्रीमकोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीमकोर्ट की टिप्पणी से कम से कम इतना तो स्पष्ट हो गया कि भारत की धरती पर आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है. आपने सब कुछ अच्छा लिखा, पर एक बात जो मेरे हिसाब से आपको नहीं लिखनी चाहिए थी, वह यह है कि भारतीय सेना यदि सुन ले तो यहां भी पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी. आपको ऐसा नकारात्मक संदेश हरगिज नहीं देना चाहिए.

-सुनयना, सहरसा, बिहार.

दलाल पत्रकार

पत्रकार, जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, को भी भ्रष्टाचार की जंग लग चुकी है. नीरा राडिया के बरखा दत्त एवं वीर सांघवी जैसे बड़े पत्रकारों के साथ गठजोड़ के बारे में चौथी दुनिया ने महीनों पहले बता दिया था. ऐसे पत्रकारों को इंडिया गेट पर फांसी दे देनी चाहिए, ताकि चोरी-चुगली-दलाली का ज़हर देश की युवा पीढ़ी में न फैले.

-महेश चंद्र वर्मा, इंदौर, मध्य प्रदेश.

रंगनाथ रिपोर्ट और सरकार

आपने सही लिखा कि मुस्लिम नेता केवल वोट की राजनीति करते हैं. इतने सारे मुस्लिम नेता हैं, लेकिन किसी ने सरकार से मांग नहीं की कि रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू की जाएं.

-तौफीक अहमद खान, ईमेल से.

**आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com**

सांप्रदायिकता विरोधी गर्जना

केवल बातों से काम नहीं चलेगा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांप्रदायिक ताक़तों पर कटु हमला किया. उन्होंने कहा कि वे सभी संगठन, विचारधाराएं एवं व्यक्ति, जो हमारे इतिहास को तोड़ते-मरोड़ते हैं, धार्मिक पूर्वाग्रहों को हवा देते हैं और धर्म के नाम पर आमजनों को हिंसा करने के लिए उकसाते हैं, देश के लिए विनाशकारी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हर प्रकार की सांप्रदायिकता से लोहा लिया है, चाहे उसका स्रोत कोई भी संगठन रहा हो. बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की सांप्रदायिकता में कोई फ़र्क़ नहीं है और देश के लिए दोनों ही बराबर ख़तरनाक हैं. यद्यपि यह वक्तव्य स्वागत योग्य है, परंतु अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक वर्गों की सांप्रदायिकता के बीच कोई विभेद न करने का सोनिया गांधी का दृष्टिकोण उचित नहीं जान पड़ता.

सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष को उनके पति के नाना एवं आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू के विचार याद दिलाना आवश्यक है. पंडित नेहरू ने कहा था कि यद्यपि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, दोनों ही वर्गों की सांप्रदायिकता बुरी है, तथापि बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता देश के लिए कहीं अधिक घातक है, क्योंकि वह राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़े रहती है. अल्पसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता अधिक से अधिक विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती है. वह बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता को भड़काती भी है और उसे वे बहाने देती है, जिनके सहारे उस वर्ग विशेष के सांप्रदायिक तत्व अपनी गतिविधियां बढ़ाते जाते हैं. लेकिन यह मानना अनुचित होगा कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग न भड़काए तो बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिक ताक़तें निष्क्रिय रहेंगी. वे तब भी वही करेंगी, जो भड़काए जाने पर करती हैं.

अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को एक ही पलड़े पर तौलना कांग्रेस की उन धर्मनिरपेक्ष नीतियों के विरुद्ध है, जिनकी नींव पंडित नेहरू ने रखी थी. हमारे देश में सांप्रदायिक राजनीति और सांप्रदायिक हिंसा दोनों के पीछे बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता है. बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का प्रभाव क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, उसने समाज के सोचने के तरीक़े को बदल दिया है, उसने देश का ध्यान आम लोगों की मूल आवश्यकताओं से हटाकर राम मंदिर जैसे अनावश्यक मुद्दों पर केंद्रित कर दिया है. शाहबानो मामले को अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताक़तों ने बहुत उछाला था और इससे निश्चित रूप से देश को हानि हुई थी, परंतु यह हानि राम मंदिर आंदोलन के कारण देश को हुए नुक़सान के सामने कुछ भी नहीं थी. राम मंदिर आंदोलन ने पहले समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित किया, फिर बाबरी मस्जिद को ढहाया और उसके बाद देश भर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ भयावह हिंसा की. अलबत्ता दोनों प्रकार की सांप्रदायिकता में कुछ समानताएं भी हैं. दोनों ही सामंती और मध्यम वर्ग के हितों की पैरोकार हैं. ये वे वर्ग हैं, जो अपने विशेषाधिकार और समाज में अपनी उच्च स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं.

अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को एक ही पलड़े पर तौलना कांग्रेस की उन धर्मनिरपेक्ष नीतियों के विरुद्ध है, जिनकी नींव पंडित नेहरू ने रखी थी. हमारे देश में सांप्रदायिक राजनीति और सांप्रदायिक हिंसा दोनों के पीछे बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता है.

सोनिया गांधी का यह दावा कि कांग्रेस कभी सांप्रदायिकता से लोहा लेने से पीछे नहीं हटी, भी एक अर्धसत्य है. कई मौक़ों पर कांग्रेस ने सांप्रदायिकता का नंगानाच नज़रअंदाज़ किया. चाहे सिख विरोधी दंगे हों या बाबरी ध्वंस, कांग्रेस या तो दूसरी तरफ़ देखती रही या दोपहर की झपकी का मज़ा लेती रही. यही कारण है कि कुछ आलोचक कांग्रेस पर सांप्रदायिक दल होने का आरोप लगाते हैं और कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस मामले में कांग्रेस भाजपा से भी अधिक दोषी है. जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में रही, वे भी सांप्रदायिक दंगों से मुक्त नहीं रहे. यद्यपि यह मान्यता सही नहीं है, तथापि इससे यह अवश्य ध्वनित होता है कि दंगा पीड़ित कितने अधिक कुंठित हो गए हैं और यह भी कि वे मानते हैं कि कांग्रेस अगर चाहती तो वह सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण कर सकती थी. अगर कांग्रेस सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सार्थक हस्तक्षेप नहीं करती रही है तो इसका एक कारण तो यह है कि सत्ता के लोभ में कई सांप्रदायिक तत्वों ने कांग्रेस में घुसपैठ कर ली है. उनकी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में कोई आस्था नहीं है. दूसरे, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सांप्रदायिक तत्वों ने पुलिस, नौकरशाही, सेना एवं न्यायपालिका सहित राज्य के सभी तंत्रों में पैठ बना ली है.

हम सबको यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि धर्मनिरपेक्षता के मोर्चे पर कांग्रेस उतनी चौकस और प्रतिबद्ध नहीं रही, जितना उसे रहना चाहिए था. कांग्रेस ने चुनावों में लाभ पाने के लिए अनेक बार सिद्धांतों को तिलांजलि दी. अयोध्या निर्णय पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि वह अवसरवादी नीतियां अपनाने में सिद्धहस्त है. अयोध्या निर्णय भारतीय संविधान के ख़िलाफ़ है और उन प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के भी, जो गांधी जी और नेहरू के नेतृत्व के दिनों में कांग्रेस के पथप्रदर्शक थे. इसके बावजूद कांग्रेस ने इस निर्णय के बारे में एक शब्द भी कहना उचित नहीं समझा. कांग्रेस अध्यक्ष के वक्तव्य का हम जोरदार स्वागत करते, यदि उनकी कथनी के अनुरूप कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मैदानी स्तर पर प्रदर्शित करती. अगर कांग्रेस सचमुच धर्मनिरपेक्ष है तो उसे अयोध्या निर्णय को धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर कसना चाहिए और अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए हरसंभव प्रयास करने चाहिए. सच्चर समिति एवं रंगनाथ मिश्र आयोग की रपटों को ठंडे बस्ते में डालकर कांग्रेस यह दावा नहीं कर सकती कि वह धर्मनिरपेक्ष है. हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता. क्या कांग्रेस इतिहास के सांप्रदायिकीकरण के विरुद्ध आवाज़ उठाएगी? क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार का मुक़ाबला करेगी? क्या वह ईसाइयों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास करेगी, जिन्होंने हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा ली हैं? क्या कांग्रेस वे सभी क़दम उठाने में सक्षम है, जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक हैं? क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाएगी?

इन दिनों कांग्रेस में ज़ोर-शोर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है. क्या पार्टी यह सुनिश्चित कर रही है कि नए भर्ती हो रहे कांग्रेसी कहीं सांप्रदायिकता के वायरस से ग्रस्त तो नहीं हैं? जो भी पार्टियां धर्मनिरपेक्ष-प्रजातांत्रिक राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन्हें अपने वर्तमान और नए सदस्यों को गहन प्रशिक्षण देना होगा, ताकि वे समाज में फैलाई जा रही सांप्रदायिक घृणा से लड़ सकें. अगर कांग्रेस यह सब नहीं करती है तो पार्टी अध्यक्ष का वक्तव्य केवल एक खोखला नारा बनकर रह जाएगा.

इस सिलसिले में दिग्विजय सिंह का वह बयान भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने राज्य तंत्र में सांप्रदायिक तत्वों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की है. क्या ऐसी कोई रणनीति बनाई जाएगी, जिससे सभी स्तरों के अधिकारी-कर्मचारी धर्मनिरपेक्ष-प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के वाहक न बनें. यह सही है कि सांप्रदायिक ताक़तों ने हर दिमाग़ में घृणा का बीज बो दिया है, परंतु प्रश्न यह है कि कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है? दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि सांप्रदायिक ताक़तें जर्मनी के नाजियों की तरह अल्पसंख्यकों पर निशाना साध रही हैं. बिल्कुल ठीक, परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? यही वह चुनौती है, जिससे कांग्रेस को मुक़ाबला करना है.

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

शादी के बाद पति-पत्नी घर-गृहस्थी में रम गए, लेकिन छह महीने बाद पत्नी को पता चला कि वह जिसे पति परमेश्वर मानती रही, वह तो असल में एक औरत है.

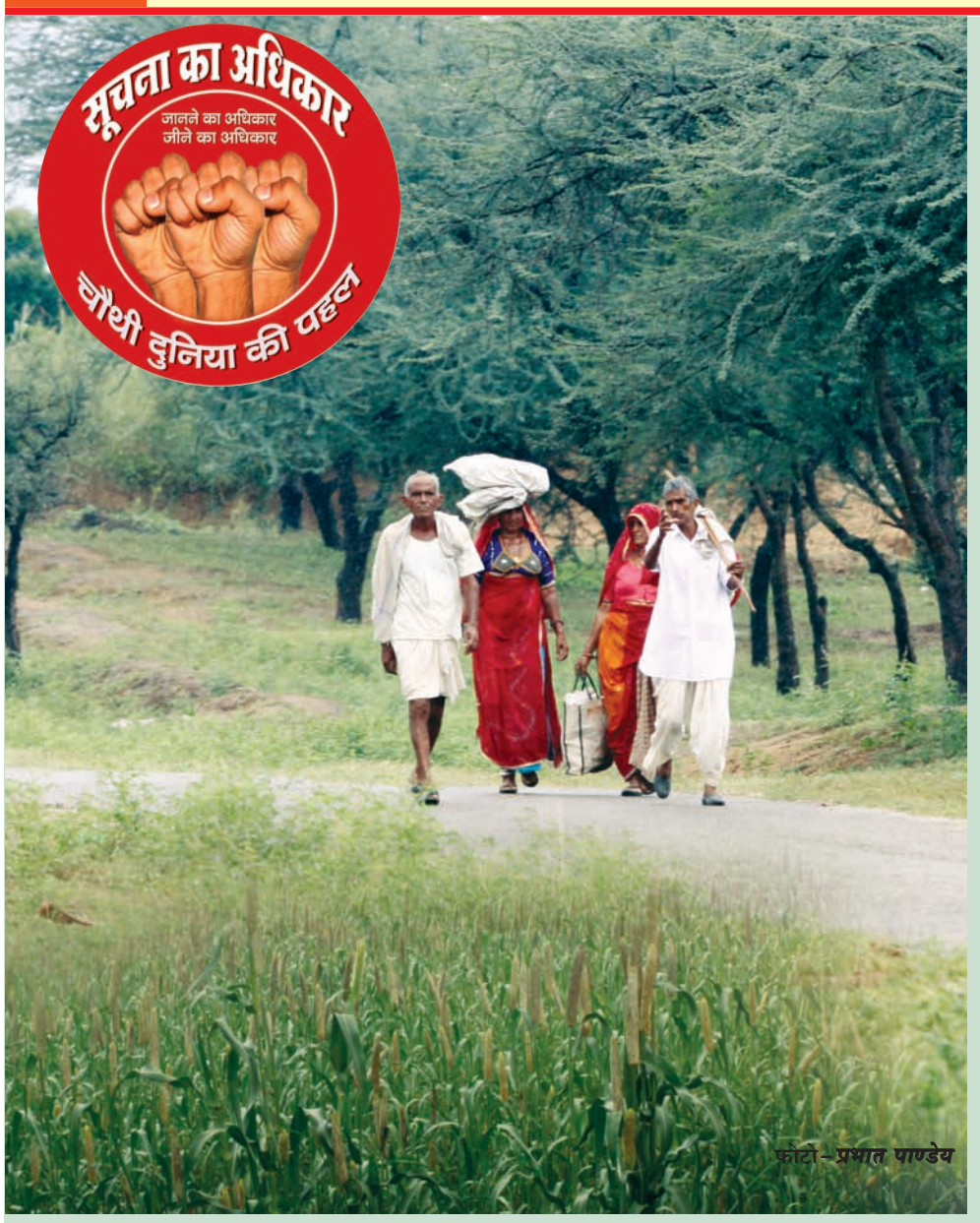

फोटो- प्रभात पाण्डेय

पंचायत की भूमि और पट्टे की जानकारी

ग्रामीण भारत के लिए मुख्य संसाधन भूमि है. ऐसे में ग्राम पंचायत की ज़मीन का काफ़ी महत्व है. ग्राम पंचायत की ज़मीन अक्सर कई कामों के लिए पट्टे पर दी जाती है. जैसे भूमिहीनों को आवास के लिए, कृषि, खनन या वनीकरण के लिए. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि वास्तव में कितनी ज़मीन किसे और कब तक के लिए पट्टे पर दी गई है. वास्तव में पंचायत के पास कितनी ज़मीन है. कहीं उसके वितरण (पट्टे देने) में कोई गड़बड़ी तो नहीं है. इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपके पास सूचना का अधिकार क़ानून है, जिसके तहत आप एक आवेदन देकर उक्त सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. अपने आवेदन में आप यह पूछ सकते हैं कि पंचायत के पास अलग-अलग तरह की कितनी ज़मीन है. मसलन कृषि योग्य ज़मीन, बंजर ज़मीन, चारागाह की ज़मीन, ग्रामसभा की ज़मीन इत्यादि. इसके अलावा आप यह जानकारी भी मांग सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में किन परिवारों को किस कार्य के लिए और कितनी ज़मीन पट्टे पर दी गई. कितनी ज़मीन ऐसी है, जिसका अब तक कोई उपयोग नहीं हो सका. इस अंक में हम एक ऐसा ही आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप उक्त सूचनाएं मांग सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(भूमि और पट्टे से संबंधित जानकारी)

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

.....में भूमि संबंधी निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त ग्राम पंचायत की भूमि के संबंध में निम्न विवरण मानचित्र के साथ उपलब्ध कराएं:
(क) कितनी भूमि कृषि योग्य है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(ख) कितनी भूमि बंजर है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(ग) चारागाह की भूमि कितनी है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(घ) ग्राम समाज की भूमि कितनी है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(च) मरघट की भूमि कितनी है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(छ) तालाब की भूमि कितनी है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित)

2. विगत 25 वर्षों में उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को निम्नलिखित से संबंधित पट्टे दिए गए? विवरण मानचित्र के साथ उपलब्ध कराएं:
(क) कृषि योग्य पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(ख) आवासीय पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(ग) खनन योग्य पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(घ) वनीकरण पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).
(ज) अन्य कोई पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

3. वर्ष.....से.....के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने भूमिहीन परिवारों को पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:
क. पट्टाधारक का नाम.
ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.
ग. पट्टाधारक का पता.
घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

4. वर्ष.....से.....के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को कृषि योग्य भूमि के पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:
क. पट्टाधारक का नाम.
ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.
ग. पट्टाधारक का पता.
घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

5. वर्ष.....से.....के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:
क. पट्टाधारक का नाम.
ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.
ग. पट्टाधारक का पता.
घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

6. वर्ष.....से.....के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को खनन योग्य भूमि के पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:
क. पट्टाधारक का नाम.
ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.
ग. पट्टाधारक का पता.
घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

7. वर्ष.....से..... के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत केकितने परिवारों को वनीकरण पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:
क. पट्टाधारक का नाम.
ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.
ग. पट्टाधारक का पता.
घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

8. वर्तमान में ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की ऐसी कितनी भूमि शेष है, जिसका अभी तक किसी पट्टे के लिए उपयोग नहीं किया गया है? रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित उपलब्ध कराएं.

9. ग्राम पंचायत में भूमिहीन परिवारों को पट्टा देने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पद एवं पता बताएं. इससे संबंधित सभी शासनादेशों एवं निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
यह सप्ताह आपके लिए कुछ विपरीत प्रभाव देने वाला और खिन्नता भरा रहेगा. किसी काम में लगातार असफलता मिलने से मन में उदासी रहेगी. वरिष्ठ और परिवारीजन आपकी ख़िलाफ़त कर सकते हैं.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सुधार की ओर अग्रसर हो रहा है. हो सकता है, इसी वजह से आपको कामकाज में उत्साह बनाए रखने में मदद मिले. यदि आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो निर्धारित लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने में देर नहीं लगेगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
काफ़ी समय से कोई लाभ आपको मिलने में देर लग रही है. इस सप्ताह आपके पास कोई ऐसी ख़बर आ रही है, जो आपके लिए आगे चलकर लंबी दौड़ का घोड़ा साबित हो.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
यह सप्ताह आपके लिए मनोकामना की पूर्ति में सहायक होगा. सप्ताह के आरंभ से ही कुछ अच्छी ख़बरें मिलने लगेंगी. यदि आप इसी तरह अपने कामकाज में तल्लीन रहेंगे तो आगे का समय आपके लिए धन-समृद्धि से भरपूर हो जाएगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह किसी घटना या घोषणा से आपकी सुख-शांति में व्यवधान पड़ सकता है. अचानक ही कुछ विपरीत परिस्थितियां पैदा होने से आपका आत्मविश्वास विचलित हो सकता है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
प्रेमी या जीवनसाथी के व्यवहार से उदासी और अशांति का माहौल रहेगा. बार-बार किसी न किसी कारण आपको अपने परिवारीजनों एवं मित्रों से उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ता है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी. आपको अपने प्रयासों में लगातार सफलता मिलेगी. सामाजिक, राजनीतिक मंच पर भी आपका नाम सम्मान और आदर से लिया जाएगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
फ़िलहाल आपके आगे-पीछे विरोधियों एवं आलोचकों का दबदबा है. इस सप्ताह आप अपने जिस काम को पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, उसमें कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर रही है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
किसी मोटे लाभ के लिए इस सप्ताह आपके मन में काफी चिंता और उत्सुकता रहेगी. हो सकता है, अभी इस काम को पूरा करने में कुछ समय और लग जाए, लेकिन यदि आप कोई नई रणनीति तैयार करेंगे तो आपका कार्य अचानक संपन्न हो सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह के आरंभ में आपके साथ कुछ अद्भुत घटनाएं होंगी. यह सब अशुभ गोचर का प्रभाव है. ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमेशा ऐसी स्थिति रहेगी. आपके जीवन में उतार-चढ़ाव बहुत जल्दी-जल्दी आते हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह आपको अपनी शारीरिक, मानसिक इच्छापूर्ति का सुख और हर्ष मिलेगा. किसी नए व्यक्ति द्वारा सम्मान और दावत दिए जाने की ख़ुशी होगी. कोई अच्छा उपहार आपको मिल सकता है. कोई निकट-दूर की मनोरंजक यात्रा भी संपन्न हो सकती है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
बहुत समय से चल रहा कोई विवाद या मामला अचानक समाप्त होने से मन को शांति मिलेगी. आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी भागीदारी एक नया विकल्प बन सकती है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

पत्नी का पति औरत

दुनिया भी बड़ी अजीबोग़रीब है. न जाने यहां कैसे-कैसे करिश्मे हो जाते हैं. अब एक करिश्मा और सुनिए. अक्सर लोग शादी को लेकर उत्साहित होकर कई उल्टे-सीधे फ़ैसले लेते हैं. कई बार उन्हें धोखे भी मिलते हैं और कई बार तो दुल्हन ही बदल जाती है. इस बार की कहानी थोड़ी अलग है. राउरकेला में एक शादी हुई. शादी के बाद पति-पत्नी घर-गृहस्थी में रम गए, लेकिन छह महीने बाद पत्नी को पता चला कि वह जिसे पति परमेश्वर मानती रही, वह तो असल में एक औरत है. अब बताइए भला, किसी महिला का पति मर्द है या नहीं, यह पता करने में तो सिर्फ़ एक रात ही लगती है. तो फिर यह मैडम छह महीने तक क्या करती रहीं. है न अजीब बात? एक अजीब बात और सुनिए.

एक ओर तो आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि शादी के पहले ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ परंपरागत समाज, ख़ासकर मुस्लिम, ऐसे भी होते हैं, जहां पति चार-पांच बच्चों का बाप बन जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देख पाता. अब यह तो हद हो गई न! आजकल तो मल्लिका, शर्लिन जैसी विषकन्याओं का ज़माना है. और बात सिर्फ़ अपने देश की ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भी वीना मलिक जैसी कन्याएं पाई जाती हैं, जो फिल्मों में नग्न दृश्य करने से परहेज नहीं करतीं. तो फिर भला उसी पाकिस्तान में ऐसे मर्द और औरत की कल्पना कैसे की जा सकती है, जिन्होंने एक-दूसरे का चेहरा ही न देखा हो. बावजूद इसके कि उनके चार-पांच बच्चे आंगन में खेल रहे हों. बात तो अजीब है, लेकिन ऐसे अजीब कारनामे तो होते रहते हैं दुनिया में.

अंगूठे में कंप्यूटर

अब तक लैपटॉप के नोटबुक और पॉकेटबुक वर्जन को कंप्यूटर के एडवांस वर्जन के तौर पर माना जाता रहा है, लेकिन साइंटिस्ट अब ऐसा कंप्यूटर बनाने में जुटे हैं, जो इंसान के हाथ के अंगूठे में फिट हो जाएगा. इससे लोगों को साथ में लैपटॉप लादकर घूमने से आज़ादी मिल जाएगी. किसी ज़माने में लैपटॉप तो दूर, आम आदमी ने कंप्यूटर तक के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज विज्ञान इतना विकास कर गया है कि छोटी डायरी के साइज के लैपटॉप की मदद से हम दूरदराज के इलाक़ों में बैठकर भी दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकते हैं. हालांकि तरक्की का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा. अब कंप्यूटर हमारे अंगूठे में फिट होकर न सिर्फ़ हमें पूरी दुनिया से जोड़ेगा, बल्कि हमारे शरीर की हर गतिविधि की भी ख़बर रखेगा. इसे चार्ज करने के लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह हमारे शरीर की एनर्जी से ही चार्ज हो जाएगा. ज़ाहिर है, ऐसी स्थिति में आजकल के भारी-भरकम कंप्यूटर कचरा हो जाएंगे. बार्क में टेक्निकल फिजिक्स डिवीज़न से जुड़े डॉ. डी के असवाल बताते हैं कि हम विकास की राह पर जिस रफ्तार से जा रहे हैं, वह हमें जल्द ही 22वीं शताब्दी की ओर ले जाएगी. आज हम कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में सिलिकॉन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. फ़िलहाल इनका साइज़ 20 नैनो मीटर से कम होना संभव नहीं है. ऐसे में हम भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे! अत: इसके विकल्प के तौर पर हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर्स के इस्तेमाल की भी परिकल्पना की है, जो साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ेगा. हमारा ब्रेन और इसकी मेमोरी भी मॉलिक्यूलर्स की थ्योरी पर बेस्ड है. साइंटिस्ट जिस मॉलिक्यूलर्स का ईजाद करने की तैयारी में हैं, उसका साइज 0.5 से लेकर 2.5 नैनो मीटर है. उसे हमारे अंगूठे में भी फिट किया जा सकेगा. नाखून में फिट होने के बाद इन नन्हें कंप्यूटरों को चलाने के लिए माइनर पावर की ज़रूरत होगी और ये बॉडी टेंपरेचर से रिचार्ज हो सकेंगे. सिर्फ़ कंप्यूटर ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में कपड़े भी स्मार्ट हो जाएंगे, जो हमारी सेहत के साथ-साथ दिनचर्या अनुसार शरीर की भी देखभाल करेंगे. ये कपड़े भी इन्हीं मॉलिक्यूलर्स पर बेस्ड होंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तान ने भारत और रूस के बीच हुए विभिन्न समझौतों पर अपनी चिंता ज़ाहिर कर दी है. हालांकि भारत की सरज़मीं पर ओबामा एवं जियाबाओ ने भी कोई भारत विरोधी बयान नहीं दिया.

पाकिस्तान की उम्मीदों पर रूस का पानी

सभी फोटो–*सुनील मल्होत्रा*

राजीव रंजन तिवारी

रूस ने पाकिस्तान से 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले की योजना बनाने वालों को सज़ा देने की बात कही. साथ ही उसने आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान एवं अफ़ग़ानिस्तान का आह्वान किया. इसके अलावा रूस ने छह देशों के संगठन शंघाई कोऑपरेशन आर्गनाइजेशन और एशिया पेसिफिक इकॉनामिक कोऑपरेशन फोरम (अपेक) की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया.

भारत और रूस के रिश्तों में पिछले 39 वर्षों के बीच आए तमाम उतार–चढ़ावों को देखते हुए पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि अपनी यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव भारत के प्रति कोई ख़ास दरियादिली नहीं दिखाएंगे, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रूस द्वारा ज़ोरदार ढंग से भारत की वकालत करने और आतंकवाद पर पाकिस्तान–अफ़ग़ानिस्तान को नसीहत देने से पाक की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. इसे भारत की राजनयिक उपलब्धि ही कहेंगे कि चीन की वजह से पाकिस्तान से भी मधुर रिश्ते रखने वाले रूस ने पाकिस्तान के प्रति रूखापन ही ज़ाहिर किया. इससे पाकिस्तान की परेशानी बढ़ी है. समझा जा रहा है कि ताज़ा हालात के मद्देनज़र चीन के माध्यम से पाकिस्तान रूस से निवेदन कर सकता है कि वह (रूस) उसके (पाक) प्रति भी नरमी रखे.

ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों अपनी दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने वर्ष 2015 तक भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के दावे का समर्थन किया और इसके लिए भारत को एक मज़बूत उम्मीदवार एवं हक़दार बताया. मेदवेदेव ने अफ़ग़ानिस्तान में अपने परामर्श केंद्रों के विस्तार पर सहमति दी. रूस ने पांचवी पीढ़ी के अत्याधुनिक और चुपके से मार करने वाले लड़ाकू विमानों की डिज़ाइन तैयार करने एवं उसके उत्पादन की संयुक्त परियोजना को मंजूरी दी है. इस समझौते में लड़ाकू विमान (एफजीएफए) का विकास करना भी शामिल है. बताते हैं कि एक एफजीएफए के निर्माण में कम से कम 10 करोड़ डॉलर की लागत आएगी. जबकि भारतीय वायु सेना की योजना है कि 2017–18 से वह इस तरह के क़रीब 300 विमान अपने बेड़े में शामिल कर ले. यह क़रीब 30 अरब डॉलर का सौदा होगा. साथ ही तमिलनाडु में अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर स्थापित करने एवं अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी. मेदवेदेव ने पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर कह दिया कि कोई भी सभ्य राष्ट्र आतंकियों को बचाने का काम नहीं कर सकता. निश्चित तौर पर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, जो आतंकवादियों को छुपाते हैं, उनके अपराधों पर पर्दा डालते हैं.

रूस ने पाकिस्तान से 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले की योजना बनाने वालों को सज़ा देने की बात कही. साथ ही उसने आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान एवं अफ़ग़ानिस्तान का आह्वान किया. इसके अलावा रूस ने छह देशों के संगठन शंघाई कोऑपरेशन आर्गनाइजेशन और एशिया पेसिफिक इकॉनामिक कोऑपरेशन फोरम (अपेक) की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया. इस दौरान कुल 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. यदि उपरोक्त मुद्दों का अध्ययन गहनतापूर्वक किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के प्रति दरियादिली दिखाने में रूस ने कोई कसर नहीं छोड़ी. मेदवेदेव की भारत यात्रा हाल में आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एवं चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से ज़्यादा प्रभावी एवं हितकारी रही. रूसी राष्ट्रपति का भारत के प्रति सकारात्मक नज़रिया इस्लामाबाद की परेशानी का कारण बन गया है.

पाकिस्तान ने भारत और रूस के बीच हुए विभिन्न समझौतों पर अपनी चिंता जाहिर कर दी है. हालांकि भारत की सरजमीं पर ओबामा एवं जियाबाओ ने भी कोई भारत विरोधी बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी यात्राओं से पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं हुई. वजह, पाकिस्तान को यह पता था कि देर–सबेर अमेरिका और चीन उसके साथ खड़े मिलेंगे. हुआ भी कुछ इसी तरह का. भारत यात्रा के तुरंत बाद जियाबाओ पाकिस्तान गए और वहां उन्होंने उसका जमकर गुणगान किया. अमेरिका द्वारा तो लगातार पाकिस्तान की मदद की जा रही है. अब जब रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने अपनी यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर भारत के प्रति दरियादिली दिखाई तो इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ गई. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल बासित ने इस्लामाबाद में मीडिया से साफ कहा कि भारत एवं रूस के बीच परमाणु और सैनिक समझौतों से इस क्षेत्र में अस्थिरता आएगी और इससे शक्ति संतुलन प्रभावित होगा. पाकिस्तान को इस प्रकार के समझौतों से चिंता है. सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का सवाल भी पाकिस्तान को दर्द देता रहा. प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश करने वाले देशों की वजह से संयुक्त राष्ट्र की सुधार प्रक्रिया में रुकावट पैदा होगी. पाक हमेशा से संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाने का इच्छुक रहा है. पाकिस्तान का इशारा भारत की ओर ही था, क्योंकि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे स्थायी सदस्यता मिल जाए. बहरहाल, रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौतों और उनके द्वारा दिए गए सकारात्मक संदेश से पाकिस्तान को जो परेशानी हुई है, उसका अंदाज़ा उसके उपरोक्त नज़रिए से लगाया जा सकता है.

पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रूस भारत से अपनी यारी निभाएगा, लेकिन इतना नहीं. चूंकि अमेरिका विरोधी नीति की वजह से चीन और रूस के बीच मधुर संबंध हैं, इसलिए पाकिस्तान रूस को भी अपना संरक्षक मानता है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है. बदले हालात में यह समझा जा रहा है कि चीन के माध्यम से पाकिस्तान रूस तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगा कि वह (रूस) उसके (पाक) प्रति अपना नजरिया नरम रखे और सहयोग के लिए आगे आए. वैसे भारत के हितों के विपरीत रूस चीन या पाक की बात सुनेगा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध मूलतः आपसी भौगोलिक–राजनीतिक हितों के आधार पर निर्मित हुए हैं. इतिहास गवाह है कि सोवियत संघ को जब–जब चीन से परेशानी हुई, भारत ने उसकी मदद करके चीन को संतुलित किया. यह अलग बात है कि आज रूस के चीन के साथ मधुर और भारत के साथ असहज रिश्ते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

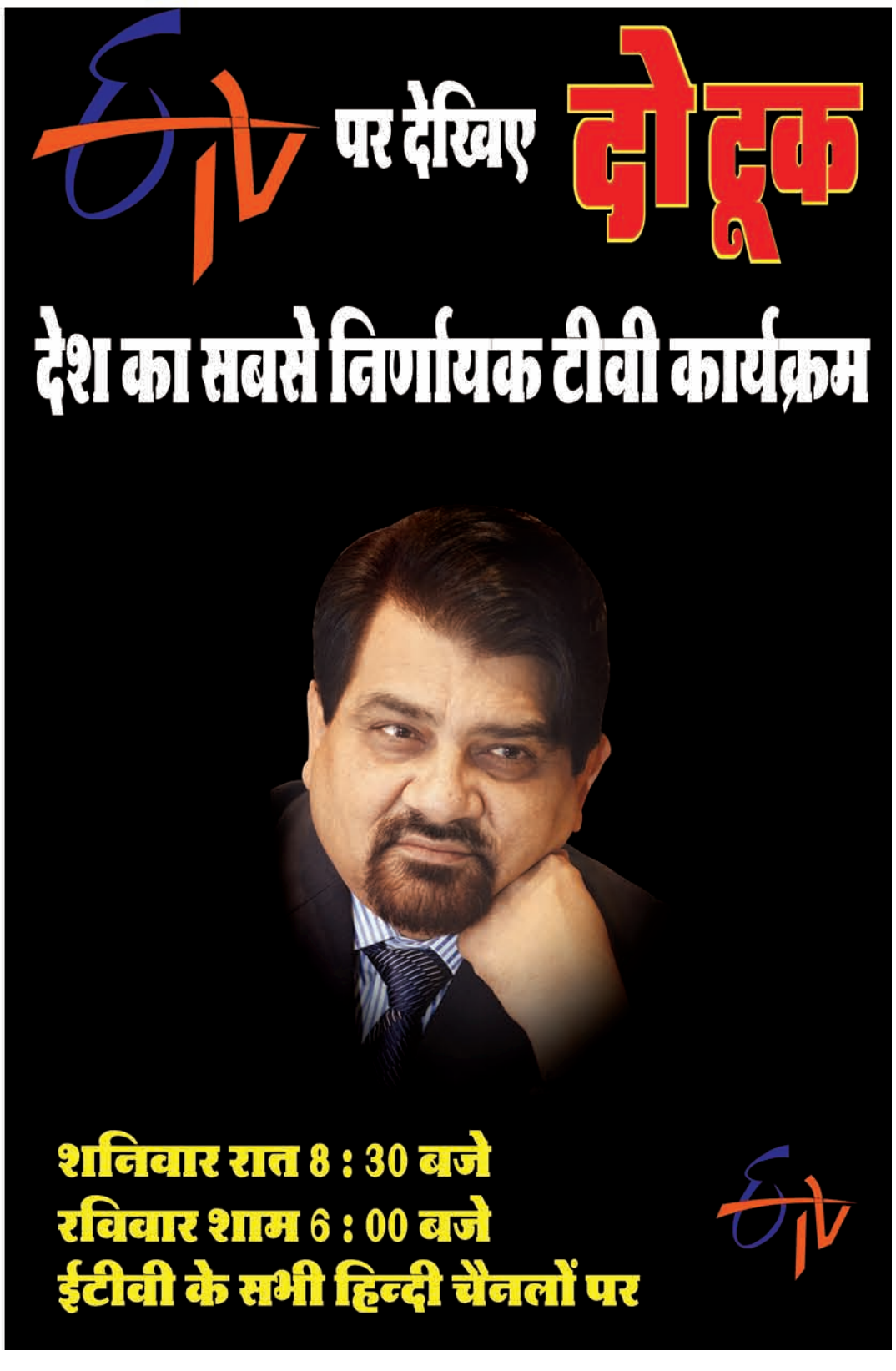

यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह तुरंत ही पांच रुपये दे देता, परंतु उस आदमी की दशा तो बिल्कुल विपरीत थी. उसने न रुपये दिए और न शांत ही बैठा.

मेरे सब व्यवहार नकद हैं और मैं उधार कभी नहीं करता. इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य एवं अन्य पदार्थों की इच्छापूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई बाबा का ब्रह्मज्ञान

श्री साई की लीला पुस्तिका श्री साई सच्चरित्र में एक ही भक्त ऐसा है, जो बाबा से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं कहता. वह बाबा से इस मिथ्या जगत के किसी लोभ को नहीं मांगता, बल्कि वह बाबा से ब्रह्मज्ञान मांगता है. वास्तव में लीला पुरुषोत्तम श्री साई का आशय भी यही था कि इस लीला से सबको मोह त्याग करने की प्रेरणा मिले. आइए सबसे पहले हम इस लीला को श्री हेमाडपंत जी द्वारा स्मरण करते हैं:

एक धनी व्यक्ति (दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया है) अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था. उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास एवं दासियां थीं. जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है? उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है. विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है. तुम्हारी ब्रह्मज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं देता? अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वह आने-जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आया और सीधे मस्जिद पहुंचा. वह साई बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में जा गिरा और प्रार्थना की कि आप यहां आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्मदर्शन करा देते हैं, केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूं. मैं इस यात्रा से थक गया हूं. यदि कहीं मुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना सफल और सार्थक समझूंगा.

बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो. मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा. मेरे सब व्यवहार नकद हैं और मैं उधार कभी नहीं करता. इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य एवं अन्य पदार्थों की इच्छापूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं. ऐसा तो कोई विरला ही आता है, जो ब्रह्मज्ञान का पिपासु हो. भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहां आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है. मैं सोचता हूं कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य एवं शुभ है, जब आप जैसे महानुभाव यहां पधार कर मुझे ब्रह्मज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं. मैं सहर्ष आपको ब्रह्मदर्शन करा दूंगा. यह कहकर बाबा ने उसे ब्रह्मदर्शन कराने हेतु अपने पास बैठा लिया और इधर-उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गया. इसी बीच बाबा ने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहां से पांच रुपये उधार लाने को भेजा. लड़के ने वापस आकर बताया कि नंदू का तो कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है. फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहां भेजा. इस बार भी लड़का रुपये लाने में असफल रहा. इस प्रयोग को दो-तीन बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला.

हमें ज्ञात है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे. यहां प्रश्न हो सकता है कि पांच रुपये जैसी तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी और उस ऋण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों किया गया? उन्हें तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी. वह तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू जी घर पर नहीं हैं. यह नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक के परीक्षार्थ ही रचा था. ब्रह्मजिज्ञासु के पास नोटों की अनेक गड्डियां थीं और यदि वह सचमुच ब्रह्मज्ञान का आकांक्षी होता तो इतने समय तक शांत न बैठता. जब बाबा व्यग्रतापूर्वक पांच रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहां-वहां दौड़ा रहे थे तो वह दर्शक बना बैठा न रहता. वह जानता था कि बाबा अपने वचन पूर्ण करके ऋण अवश्य चुकाएंगे. यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ रहा और पांच रुपये उधार देने तक का साहस नहीं कर सका. पाठक थोड़ा विचार करें कि यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह तुरंत ही पांच रुपये दे देता, परंतु उस आदमी की दशा तो बिल्कुल विपरीत थी. उसने न रुपये दिए और न शांत ही बैठा, बल्कि वापस लौटने की तैयारी करने लगा और अधीर होकर बाबा से बोला, अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्मज्ञान दो. बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्मदर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था. संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए पांच वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है:- (1) पांच प्राण (2) पांच इंद्रियां (3) मन (4) बुद्धि (5) अहंकार. यह हुआ ब्रह्मज्ञान. आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है, जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना. श्री साई की कथा अनंत है, साई नाम अनमोल. जनम सफल हो जाएगा, साई-साई बोल. बाबा की लीलाएं जितनी मनमोहक हैं, उनका रहस्य और तात्पर्य उससे भी अधिक गूढ़ है. वास्तव में बाबा की इस लीला का उद्देश्य भक्तों के मोहग्रस्त मन को माया के पाश से मुक्त कराना और सही मार्ग दिखाना था. अब हम उन सज्जन की बात करते हैं, जो ब्रह्मज्ञान के लिए व्यग्र थे. मेरे अबोध मन में जो जिज्ञासा या विचार हैं, उन्हें मैं यहां आप सभी साई भक्तों के चरणों में अर्पित कर रहा हूं. यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए और यदि सहमत हैं तो आशीर्वाद. वास्तव में बाबा की इन सज्जन पर बहुत कृपा रही होगी, जो बाबा ने अपनी एक विलक्षण लीला में उन्हें सांकेतिक रूप से प्रयोग किया. श्री साई के पास ब्रह्मज्ञान के लिए एक ही व्यक्ति आया और बाबा ने उसे भी ब्रह्मज्ञान देने के स्थान पर उसका उपहास किया, ऐसा सोचना भी मूर्खता जैसी स्थिति है. मेरा साई जो सबके लिए मां और बाप के समान है, वह ब्रह्मज्ञान मांगने वाले का उपहास नहीं कर सकता. श्री साई सच्चरित्र इस कथन को सत्य सिद्ध करता है कि बूटी साहेब, शमा गुरुजी, नाना साहेब चांदोरकर या स्वयं दासगणु महाराज जैसे सतत साई अनुयायियों ने भी बाबा से कभी ब्रह्मज्ञान नहीं मांगा. मेरे विचार में इन सज्जन का नाम ग्रंन्थ में इसलिए नहीं है, क्योंकि इनका नाम लिखने से इनके व्यापार या परिवार से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए ऐसी ही धारणा बन जाती. इसलिए बाबा की अंतःप्रेरणा से मूल ग्रंथ में इनका नाम नहीं है. एक बात यह कि जिस साई के सामने प्रबुद्ध और धनाढ्य व्यक्तियों के विचार और व्यवहार भी शांत हो जाते थे, उनके सामने यह महाशय किस प्रकार अपने धन का प्रदर्शन कर सकते थे?

बाबा स्वयं समर्थ थे और यदि वह इन महाशय से दक्षिणा चाहते तो साधिकार मांग सकते थे. बाबा ने किसी से भी दक्षिणा इसलिए नहीं ली कि उसके पास बहुत धन है. बाबा ने दक्षिणा इसलिए मांगी, क्योंकि वह सब कुछ उनका ही तो है. फिर इन महाशय के स्वयं धन अर्पित करने की प्रतीक्षा क्यों? विचार कीजिए कि यदि आप उन सज्जन के स्थान पर हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा, मुझसे पांच रुपये ले लो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बाबा कहते, तू मुझे धन देगा? तेरे पास है इतना की, तू साई को दे सके? ऐसे में स्थिति और भी ख़राब होती. दूसरी बात यह है कि धनवान व्यक्ति वास्तव में सहज नहीं होते. धन की माया किसी को भी असहज और अनावश्यक रूप से विचारशील बना देती है. इन सज्जन को तो शायद यह लगा ही नहीं होगा कि बाबा उस बालक को इसलिए दौड़ा रहे हैं कि इन्हें शिक्षा मिले. यह तो यही विचार कर रहे होंगे कि बाबा जल्द से जल्द इन्हें ब्रह्मज्ञान दें. इनके लिए ब्रह्मज्ञान पाना किसी अन्य वस्तु को पाने जैसा ही रहा होगा. सांसारिक व्यापार को चलाने वाला आध्यात्मिक व्यवहार को नहीं समझता होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं. आख़िरी बात यह कि शायद यह महाशय ब्रह्मज्ञान और गुरुमंत्र में भेद ही न कर पाए हों. गुरुमंत्र तो गुरु एक साधारण और अत्यंत आत्मीय परिस्थिति में कभी भी दे सकता है. कैसे श्रीमती कानिटकर जो बहुत छोटी उम्र में बाबा के दर्शन करने अपने परिवार के साथ गई थीं. बाबा ने उनके पैरों पर हाथ फेरकर कहा था, जा राममय हो जा. कहते हैं, 80 वर्ष की अवस्था में भी वह अपने पैरों से भलीभांति चल सकती थीं. जिस प्रकार सहजता से श्रीमती रमाबाई कानिटकर को रामनाम जप का गुरुमंत्र मिला था, उसी प्रकार राधाबाई देशमुख को बाबा ने कोई गुरुमंत्र नहीं दिया.

बाबा स्वयं समर्थ थे और यदि वह इन महाशय से दक्षिणा चाहते तो साधिकार मांग सकते थे. बाबा ने किसी से भी दक्षिणा इसलिए नहीं ली कि उनके पास बहुत धन है. बाबा ने दक्षिणा इसलिए मांगी, क्योंकि वह सब कुछ उनका ही तो है. फिर इन महाशय के स्वयं धन अर्पित करने की प्रतीक्षा क्यों?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

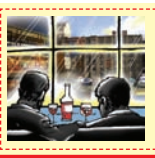

दो दिन से वाइल्ड लाइफ पर बनी कई अद्भुत फिल्में देखने के बाद श्रेष्ठ फिल्म को पांडा अवार्ड (ग्रीन ऑस्कर सेरेमनी) का वक़्त आ गया था. चारों तरफ़ रंग बिरंगी रोशनी से हॉल जगमगा रहा था.

किताब से धुलेगा कलंक!

अनंत विजय

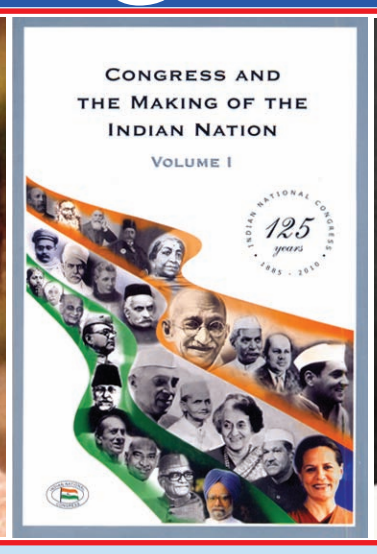

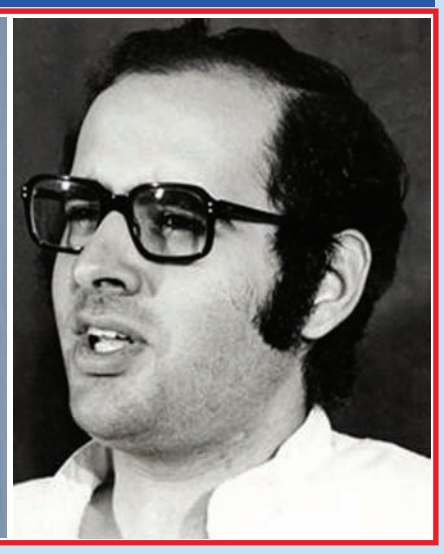

कांग्रेस ने दिल्ली के बुराड़ी में अपना दो दिवसीय 83वां अधिवेशन आयोजित किया. पार्टी के तमाम दिग्गज वहां जुटे और कांग्रेस ने महाअधिवेशन के दौरान ही अपने 125 साल पूरे होने के सालाना जलसे का समापन भी किया. इस मौक़े पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने दो खंडों में प्रकाशित किताब–कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन का विमोचन किया. इस किताब के मुख्य संपादक वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रणब मुखर्जी हैं. एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन वाणिज्य मंत्री एवं दस जनपथ के क़रीबी नेता आनंद शर्मा हैं. संपादक मंडल में प्रख्यात इतिहासकार एवं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की निदेशक मृदुला मुखर्जी, उनके पति एवं दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, जेएनयू के ही इतिहास विभाग में शिक्षिका एवं उनकी बहन सुचेता महाजन हैं. इनके अलावा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में ही कार्यरत भाष्यम कस्तूरी जामिया मिलिया के इतिहास विभाग के शिक्षक रिजवान कैसर जैसे दिग्गज भी शामिल हैं. यहां यह सवाल उठता है कि नेहरू मेमोरियल की निदेशक कैसे एक राजनीतिक दल के प्रकाशन से जुड़ सकती हैं. नेहरू मेमोरियल संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध एक स्वायत्त संस्था है और नियमों के मुताबिक़ इसका निदेशक किसी भी तरीक़े से किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हो सकता है. यह एक अवांतर प्रसंग है, जिस पर अलग से विस्तार से चर्चा की जा सकती है.

इस वक़्त जो चर्चा में है, वह है कांग्रेस की इस किताब में संजय गांधी के बारे में पार्टी की राय. पार्टी ने इस किताब के बहाने ख़ुद को संजय गांधी से अलग करने और इमरजेंसी के दौरान हुई ज़्यादतियों के लिए संजय को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की है. कांग्रेस ने इस किताब में बेहद बेबाक़ी से अपने अतीत पर प्रकाश डाला है. ख़ास तौर पर इमरजेंसी को लेकर, जो जून 1975 में लगाई गई और तक़रीबन पौने दो साल बाद जनवरी 1977 तक कायम रही. कांग्रेस ने माना है कि इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में बेहिसाब ताक़त आ गई थी. इस किताब के पहले खंड के पृष्ठ संख्या 116–17 पर इमरजेंसी और संजय गांधी के बारे में लिखा गया है इमरजेंसी लगने के शुरुआती दिनों में आम जनता ने इसका स्वागत किया, क्योंकि उस दौरान प्रशासन में काफ़ी सुधार आ गया था. लेकिन जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की. दुर्भाग्य से कई सरकारी कार्यक्रमों जैसे–अनिवार्य नसबंदी और झुग्गी– झोपड़ी हटाओ अभियान में अति उत्साह की वजह से ज़्यादतियां हुईं. संजय गांधी इमरजेंसी के दौरान बेहद अहम नेता के तौर पर उभरे. यह उनके ही समर्थन का नतीजा था कि सरकार ने अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम को बेहद ज़ोरदार तरीक़े से लागू करना शुरू किया. संजय गांधी ने स्लम से आज़ादी के अलावा दहेज के दानव को ख़त्म करने और साक्षरता बढ़ाने पर ख़ासा ज़ोर दिया, लेकिन इन योजनाओं को लागू कराने के लिए उन्होंने एकतरफा और अधिकारपूर्वक ढंग से फ़ैसला लिया, जिसकी वजह से जनता बुरी तरह चिढ़ गई.

पार्टी के महाअधिवेशन के दौरान इस किताब का मनमोहन सिंह एवं सोनिया गांधी द्वारा विमोचन करने और प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता के संपादन में जिस तरह इमरजेंसी के दौरान हुईं ज़्यादतियों के लिए संजय गांधी को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, उससे यह साफ़ है कि कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि इमरजेंसी के लिए पार्टी नहीं, व्यक्ति ज़िम्मेदार थे. लेकिन कांग्रेस के कर्ता–धर्ता यह भूल गए हैं कि संजय गांधी को खुली छूट किसने दी. किसने उस दौरान संजय को सत्ता के असंवैधानिक केंद्र के तौर पर उभारा या फिर उभरने की छूट दी. किसने संजय को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी सरकारी योजना पर एकतरफ़ा और अधिकारपूर्वक फ़ैसला करा सकें. संजय गांधी उस वक़्त किसी सरकारी पद पर नहीं थे. हां, इतना अवश्य था कि उनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, जो अपने बेटे की ज़्यादतियों को जानते हुए भी नहीं रोक पा रही थीं. तो क्या यह मान लें कि इमरजेंसी के दौरान हुईं ज़्यादतियों के लिए इंदिरा गांधी ज़िम्मेदार नहीं थीं. कांग्रेस इस किताब के माध्यम से यही कहना भी चाहती है. कांग्रेस के इतिहासकारों ने बेहद चालाकी से इंदिरा गांधी को ज़्यादतियों की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया है.

पार्टी यह बात ज़ोर देकर कह रही है कि इमरजेंसी की ज़्यादतियों के लिए संजय गांधी ज़िम्मेदार थे और उनके दबाव की वजह से ही ज़बरन नसबंदी का बदनाम कार्यक्रम चला. किताब में लिखी इन बातों से देश की राजनीति में झटके महसूस किए जाने लगे हैं. संजय गांधी की पत्नी मेनका और बेटा वरुण गांधी अभी भाजपा में हैं और दोनों ही सांसद हैं. यह कांग्रेस की एक सोची–समझी रणनीति हो सकती है कि संजय को इमरजेंसी के लिए ज़िम्मेदार ठहरा दो, ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेता गाहे–बगाहे कांग्रेस को इसके लिए ज़िम्मेदार न ठहरा सकें. लेकिन क्या देश की जनता इमरजेंसी के दौरान हुईं ज़्यादतियों के लिए कांग्रेस को माफ कर देगी? क्या तुर्कमान गेट पर अपने आशियाने पर चले बुलडोजर का दर्द भुलाना आसान है? कतई नहीं, इमरजेंसी देश के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है और जब भी देश के लोकतांत्रिक इतिहास में उस काले अध्याय को याद किया जाएगा तो संजय गांधी से ज़्यादा इंदिरा गांधी को ज़िम्मेदार माना जाएगा.

किताब में इमरजेंसी और उसके ख़िलाफ़ संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकने वाले लोकनायक जय प्रकाश नारायण के बारे में लिखा है कि उनकी ईमानदारी और जनता की निस्वार्थ सेवा पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, वह बेहद अस्पष्ट थी. किताब के मुताबिक़, जय प्रकाश नारायण ने 1950 में संसदीय लोकतंत्र की आलोचना करते हुए पार्टी विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था. इमरजेंसी के ख़िलाफ़ जय प्रकाश नारायण के देशव्यापी आंदोलन को संविधानेत्तर और अलोकतांत्रिक बताया गया है, जिसका एकमात्र मक़सद लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गई सरकार को गिराना था. लेकिन लेखकों को यहां यह बताना चाहिए कि किस तरह लोकनायक जय प्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आह्वान असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक था. उन्हें अपने निष्कर्ष के समर्थन में कम से कम कोई तो तर्क रखना चाहिए था. किताब में कहा गया है कि 1974 के अंत में जय प्रकाश नारायण का आंदोलन शिथिल हो गया था. हो सकता है कि आंदोलन में कुछ वक़्त के लिए ढिलाई आ गई हो, लेकिन जय प्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा ही ऐसा था, जिसने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को हिला दिया और जिसके दमन के लिए ही उन्होंने पूरे देश को इमरजेंसी के नर्क में धकेल दिया.

इस किताब में राजीव गांधी को स्वप्न दृष्टा के तौर पर पेश किया गया है. जय–जयकार तो राहुल गांधी की भी है. राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान किए गए काम को उल्लेखनीय मानते हुए उसकी सराहना की गई है, लेकिन एडिटोरियल बोर्ड के तमाम दिग्गज बिहार चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका पर ख़ामोश हैं. बिहार में राहुल बाबा के सपनों पर नीतीश कुमार के विकास कार्यों ने ग्रहण लगा दिया. राहुल गांधी ने बिहार को लेकर तमाम रणनीति बनाई, पूरी यूथ ब्रिगेड को चुनाव में झोंक दिया, बावजूद इसके सीट संख्या दस से घटकर महज चार रह गई. सवाल यह उठता है कि इस किताब के माध्यम से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है. क्या यह संभव है कि इस किताब में पार्टी की स्वीकारोक्तियों के बाद इमरजेंसी का कलंक कांग्रेस के माथे से हट जाएगा. मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कभी संभव हो पाएगा. उस दौर के जुल्म के लिए कोई भी माफी नाकाफ़ी है. इतने भारी–भरकम संपादक मंडल के बावजूद किताब बेहद हल्की है और बग़ैर पर्याप्त विस्तार के चलते–चलते विषयों को छूने की कोशिश की गई है. मुझे नहीं मालूम, सोनिया गांधी का एप्रूवल था या नहीं या फिर वह प्रणब मुखर्जी पर आंख मूंदकर भरोसा कर बैठीं. चाहे जो भी हो, मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन पर जारी विवाद पर बहस की गुंजाइश है. होनी भी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी ने अपना स्टैंड बदला है और अब उसके बदले स्टैंड पर सभी को अपना रुख़ तय करना होगा.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती को मुन्नी हमेशा प्रीति की कोई न कोई बात बताती रहती थी. प्रीति तीसरे नंबर की बेटी थी उसकी. मुन्नी प्रीति को जासूस कहती थी. बताती थी कि घर में उसके पीछे क्या–क्या होता है, वह सब कुछ उसे चुपचाप बता देती थी. काम से लौटने पर वही परात में पानी भरकर उसके पैर धोती थी. खाना परोस कर वही लाती थी. बड़ी बेटी नंदिनी अपने काम से काम रखने वाली है और बीच वाली रेखा सबसे तेज. इसके बाद तीन बेटे छोटे. रेखा का मुन्नी से छत्तीस का आंकड़ा हमेशा रहता है. कई–कई दिन दोनों में बातचीत नहीं होती. इस सबके बावजूद वह पढ़ने में तेज है. प्रीति के जाने के बाद मुन्नी टूट गई होगी, ऐसा आनंद भारती सोच रहे थे. रात काफ़ी हो गई थी. उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन प्रीति की मौत की ख़बर सुनकर वह अशांत हो गए थे. नींद नहीं आ रही थी. किसी तरह रात कटी. सुबह हो चुकी थी. तैयार हो समान पैक कर वह रिसेप्शन पर पहुंच गए. हमेशा की तरह तीसा केलगर मुस्कराते हुए खड़ी थी. बाक़ी साथी भी एक–एक कर आ गए और सब कार में बैठकर पेडिंगटन रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए. लंदन से ब्रिस्टल का सफर क़रीब डेढ़ घंटे का था. उसके बाद होटल ब्रिस्टो पहुंचने में पचास मिनट लगने वाले थे. आनंद भारती और टीम के अन्य सदस्य लंदन के अपनी घुमक्कड़ी के किस्से एक–दूसरे को सुनाते हुए ब्रिस्टल के पार्क–वे स्टेशन पहुंच गए. वहां से फिर होटल.

होटल में चेक इन करने के बाद वाइल्ड स्क्रीन फेस्टिवल के वेन्यू पहुंच कर सबने रजिस्ट्रेशन कराया. वहां टीम की भेंट वाइल्ड स्क्रीन की सीईओ हैरिट निम्मो से वाटरशेड में हुई. वाटरशेड में कई स्क्रीन थे. वाटरशेड एक नहर के किनारे पर था. नहर में स्पीड बोट टूरिस्टों को इधर से उधर ले जाते दिख रहे थे. पूरे विस्तार से निम्मो ने फेस्टिवल के बारे में बताया. यह भी बताया कि फेस्टिवल के पच्चीस साल पूरे हो चुके हैं. पूरी दुनिया से वाइल्ड लाइफ पर बनने वाली बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित की जाने वाली हैं. कई थियेटरों पर फिल्में थीं. आनंद भारती ने फिल्मों की सूची देखी. उन्होंने सबसे पहले एक चीनी फिल्म देखने का फ़ैसला किया. फिल्म बिग कैट्स के शिकार और उनको मारकर उनकी हड्डी से बनने वाली दवाओं के बारे में थी. फिल्म को वहां के युवाओं ने बनाया था. चाइना डायलॉग नामक संस्था के माध्यम से वे पूरी दुनिया में बिग कैट्स के शिकार के ख़िलाफ़ अभियान चला रहे हैं. फिल्म देखते हुए आनंद भारती के रोंगटे खड़े हो गए. बिग कैट्स की हड्डियों से बनने वाली दवाओं की फैक्ट्री की शूटिंग निश्चित रूप से ख़तरनाक रही होगी.

फिल्म ख़त्म होने के बाद फिल्म की युवा निर्मात्री जिंग मिंग से आनंद भारती ने इस बारे में पूछा. उसका सीधा जवाब था, निश्चित तौर पर फैक्ट्री की शूटिंग हमारे लिए बड़ी चुनौती थी. हमने वहां काम करने वालों की मदद से इस काम को अंजाम दिया. चीन में सेक्स बढ़ाने के नाम पर इन दवाओं का काफ़ी प्रचलन है. माना जाता है कि इनके सेवन से सेक्स की ताक़त बढ़ती है. यही सोच अब लंदन में भी आ रही है. चीनी दवाओं का अकेले लंदन में कई पाउंड का व्यापार है. इन दवाओं की मांग के बारे में लंदन मेट्रोपालिटन पोलिस के वाइल्ड लाइफ क्राइम यूनिट के हेड एंडी फिशर ने भी आनंद भारती को विस्तार से बताया था, पर क़ानून के लचर होने के कारण वह इनकी बिक्री पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया था कि अगर इसी रफ्तार से बिग कैट की हड्डियों से बनी दवाओं की मांग बढ़ती रही तो दुनिया से बिग कैट जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी.

दो दिन से वाइल्ड लाइफ पर बनी कई अद्भुत फिल्में देखने के बाद श्रेष्ठ फिल्म को पांडा अवार्ड (ग्रीन ऑस्कर सेरेमनी) का वक्त आ गया था. चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी से हॉल जगमगा रहा था. आनंद भारती और उनके अन्य पत्रकार साथी इंडिया टेबिल पर बैठे थे. एक के बाद एक अवार्ड दिए जा रहे थे. इंडिया के फिल्म मेकर भी समारोह में भाग ले रहे थे. इंडिया टीम के साथ दिल्ली से ब्रिटिश हाई कमीशन से जुड़ी अधिकारी डेबरा पिटरसन भी इंडिया टेबिल पर बैठी थीं. जैसे ही पांडा अवार्ड के लिए बेदी फिल्म्स की फिल्म चेरब ऑफ दि मिस्ट का नाम पुकारा गया तो इंडिया टेबिल पर हलचल होने लगी. सभी देर तक तालियां बजाते रहे. एवार्ड सेरेमनी ख़त्म हो चुकी थी. आनंद भारती और अनंत कृष्णन ने होटल जाने से पहले पब में जाने का फ़ैसला किया. देर रात तक पब में दोनों बीयर पीते रहे. इसके बाद सड़क नापने का सिलसिला शुरू हुआ. ब्रिस्टल एवोन नदी के दोनों किनारों पर बसा है. शहर के बीचोबीच नदी में स्पीड बोट और दूसरी छोटी नौकाएं चलती हैं. लोग जल्दी पहुंचने के लिए भीड़ भरे रास्तों में टैक्सी से जाने के बजाय वाटर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं. नदी के दोनों किनारों पर कुछ पुरानी इमारतें हैं और कुछ नई. रात के समय नौकाएं नहीं चलती हैं तो पानी शांत दिखता है. स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नदी दर्पण में तब्दील हो जाती है. इमारतों की परछाई ऐसे दिखती है, जैसे किसी ने जीवंत पेंटिंग ज़मीन पर बना दी हो. दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिस्टल को भारी नुक़सान हुआ था. पुराने जमाने में दासों के व्यापार के लिए भी यह शहर मशहूर रहा है. बारहवीं शताब्दी में ही एवोन नदी के मुहाने पर हारबर बन गया था. समुद्र मार्ग से वेस्टइंडीज और ब्रिस्टल से काफ़ी बड़ा व्यापार होता था. लगभग उसी समय से ये दोनों देश ब्रिटिश कॉलोनी बन गए थे. ब्रिस्टल की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान भी है. दुनिया में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी का भी बड़ा नाम है. नदी पर जगह–जगह ब्रिज बने हुए हैं. ब्रिस्टल में एक इंडियन रेस्त्रां भी है. इसे गुजरात से छठे दशक में यहां आकर पन्ना भाई रमेश भाई चलाते हैं. समोसा–जलेबी से लेकर ढोकला और गंठिये तक सब यहां मिलते हैं. इसी रेस्त्रां में सरदार जोगिंदर सिंह से आनंद भारती की मुलाकात भी काफी दिलचस्प रही. जोगिंदर सिंह बीते पंद्रह साल से ब्रिस्टल में रह रहे हैं. कोई काम–धाम नहीं करते. बस उन्हें इंतजार इस बात का है कि कोई कार–ट्राली उन पर चढ़ जाए. एक्सीडेंट से उनका हाथ या फिर पैर टूट जाए तो वह इंश्योरेंस से मिलने वाली बड़ी रक़म लेकर भारत लौट जाएं. लेकिन पंद्रह साल गुजर गए, ऐसा हो नहीं रहा है. वाहेगुरु से रोज प्रार्थना करते हैं वह, लेकिन उनके दरबार में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है.

काम–धाम नहीं करते तो खाना–पीना कैसे चलता है? परिचय होने के बाद आनंद भारती ने उनसे पूछते हैं.

इंग्लैंड में खाने–पीने की कोई कमी नहीं है. चारों तरफ खाना ही खाना है, जोगिंदर सिंह बेतकल्लुफी के साथ जवाब देते हैं.

मतलब नहीं समझा, आनंद भारती आश्चर्य के साथ पूछते हैं.

इंग्लैंड में एक्सपायरी का चक्कर ज़बरदस्त है. हर स्टोर से हर दिन एक्सपायर हुई खाने–पीने की चीजें फेंकी जाती हैं, यही हमारा भोजन बनती हैं. एक्सपायर हुआ खाना अंग्रेजों के लिए खराब होता होगा, पर हमारा डाइजेशन सिस्टम इसके लिए पूरी तरह ठीक है. इंडिया में भी तो हम एक्सपायरी चीजें ही खा रहे हैं. वहां हमें कौन खेत से तोड़कर देता है. बाकी कोई परेशानी हुई तो अपना पन्ना भाई है न. खाने पर छोटा सा भाषण देने के बाद जोगिंदर सिंह चाय की चुस्की लेने लग जाते हैं. आनंद भारती जोगिंदर सिंह की बात पर अचंभित रह जाते हैं. उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है. वह पूछते हैं, रहते कहां हैं?

वैसे तो पूरा जहां हमारा है, पर फ़िलहाल कई सालों से गुरुद्वारे में रहता हूं, जोगिंदर सिंह का लहजा वही था.

अगले अंक में जारी...

डॉ. वैद्यनाथ शर्मा

पर्दे के पीछे हैं नंगे, बाहर रूप सजाते हैं

संघर्ष संकुल जीवन के गलियारे से गुज़र कर लक्ष्य के विराट प्रांगण तक एक आम आदमी किस तरह पहुंचता है, यही साबित किया डॉ. वैद्यनाथ शर्मा ने. बहुआयामी रचनाधर्मिता और उदात्त व्यक्तित्व के धनी डॉ. शर्मा उच्च कोटि के शिक्षाविद्, स्वस्थ राजनीतिक चेतना संपन्न बुद्धिजीवी, दूरदर्शी संगठनकर्ता, संवेदनशील कवि, सजग साहित्य समीक्षक, समालोचक, यथार्थवादी कहानीकार, भाव प्रवण विचारक, व्याकरणाचार्य, कुशल शोध प्रज्ञ एवं सक्षम शोध निदेशक हैं. उनके रचनात्मक व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य ने साहित्य सर्जकों, पाठकों एवं प्रशंसकों को काफ़ी अभिभूत किया है. 13 अगस्त, 1936 को पटना के मोकामा क़स्बे के सकरवार टोले में जन्मे डॉ. शर्मा के पिता पंडित केशव प्रसाद शर्मा सच्चे गांधीवादी एवं खांटी स्वतंत्रता सेनानी थे. त्यागी, ईमानदार और सामाजिक सरोकार के धनी राजनेता के रूप में वह पूरे प्रदेश में विख्यात थे. उनके दो अग्रजों रामेश्वर शर्मा एवं विश्वनाथ शर्मा जब अंग्रेजों द्वारा गिरफ़्तार किए जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी अल्पायु के बावजूद स्तब्ध भीड़ के बीच भारत माता का जयकारा लगाकर अपनी निर्भीक राष्ट्रवादिता को अभिव्यक्त किया था. राजनीति उनकी विरासत थी, किंतु सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया. दरअसल बच्चा बाबू की राजनीति संवेदना पर आधारित थी. मोकामा नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्य आज भी मील का पत्थर बने हुए हैं.

आर्थिक तंगी और अंग्रेजी सत्ता के पीड़ाजनक प्रहार के बीच एक युवा किस प्रकार लक्ष्य पथ की ओर अग्रसर होता है, डॉ. वैद्यनाथ शर्मा इसका उदाहरण हैं. वह अभाव में भी सद्भाव की राह नहीं छोड़ते. प्राइमरी स्कूल में शिक्षक, बैंक लिपिक, रेलवे गार्ड, महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष और तत्पश्चात प्राध्यापक–प्रोफेसर के पड़ाव को पार करते हुए वह मगध विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए. इस क्रम में एक साहित्य साधक के रूप में डॉ. शर्मा ने विभिन्न विधाओं में कई पुस्तकों का सृजन किया, जैसे शापित सपने (कथा संग्रह), गंगाजल (मगही कथा संग्रह) धूल और फूल (काव्य संग्रह), फणीश्वर नाथ रेणु–कितने चौराहे, प्रसाद और चंद्रगुप्त, प्रसाद एवं ध्रुव स्वामिनी, दिनकर और बापू, दिनकर और रश्मिरथी. कवि के रूप में डॉ. शर्मा ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विडंबनाओं–विद्रूपताओं के विरुद्ध

और नवीन मूल्यों के प्रति हमेशा प्रेरक की भूमिका का निर्वहन किया. युग परिचय शीर्षक कविता में डॉ. शर्मा ने बड़ी बेबाकी से सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है :

हम नाटक के नवमंचों पर
अभिनय नित नया दिखाते हैं,
पर्दे के पीछे हैं नंगे
पर बाहर रूप सजाते हैं.

धूल और फूल नामक काव्य संग्रह बहुआयामी जीवन का यथार्थ एलबम है. यत्र–तत्र आए प्राकृतिक चित्रण और प्रेम से जुड़ी रचनाएं रह–रहकर शीतलता का एहसास कराती हैं. डॉ. शर्मा अमृत लाल नागर सम्मान, बिहार सरकार द्वारा साहित्य सेवा सम्मान और विद्यार्थी हिंदी पुस्तकालय मोकामा द्वारा मोकामा गौरव सम्मान से नवाजे जा चुके हैं. संपादक के रूप में डॉ. शर्मा अपनी स्वतंत्र, तटस्थ, सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय देते हैं. वीथिका, मगधी, तुलसीदल एवं प्रहरी आदि का संपादन करते हुए उन्होंने अपनी रचनात्मक एवं आलोचनात्मक क्षमता का परिचय देकर नए प्रतिमानों की स्थापना की. मगही लोक गीतों में प्रेम की अभिव्यंजना विषय पर उन्होंने शोधार्थी के रूप में ज़बरदस्त ख्याति हासिल की. उनके निर्देशन में हिंदी के अतिरिक्त मगही, मैथिली, भोजपुरी एवं अवधी में कई शोधकार्य संपन्न हुए.

डॉ. शर्मा का व्यक्तित्व जीवन के कई क्षेत्रों में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराता है. साहित्य में वह यथार्थवाद के उद्घोषक, राजनीति में मानवीय मूल्यों के पोषक और सामाजिक जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों के ध्वजवाहक हैं. एक बानगी देखिए:

आडंबर के पर्दों के भीतर न जाने
कैद रही कितनी सांसें,
तड़प–तड़प मरती ही रहीं
कितने सपनों की कितनी लाशें.
तब रो–रोकर हमने यही कहा था
कि फूलों का एक स्पर्श हमें दे दो,
बदले में सारा चमन ले लो.
कलियों की मुस्कान हमें देकर,
बदले में सारा उपवन ले लो.

डॉ. धीरज कुमार
feedback@chauthiduniya.com

यह सिर दर्द को भी ठीक करता है. नीलगिरी सूजन, खिंची हुई मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए जाना जाता है.

जेन का नया एंड्रॉयड पैड

एंड्रॉयड पैड सीरीज में जगह बनाने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल्स निर्माता कंपनी जेन ने नया प्रोडक्ट लांच करने का ऐलान किया है. जेन ने एंड्रॉयड पैड सीरीज में नया जेन पैड भारतीय बाज़ारों में उतारने की घोषणा की है. प्रतिदिन डिजिटल होती लाइफ स्टाइल को और भी स्टाइलिश एवं ग्रैंड बनाने के लिए जेन ने यह नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है. सात इंच का टच हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन रेग्युलर इंटरनेट यूजर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है. टीएम तकनीक के साथ जेन पैड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस करने, फोटो, वीडियो, फिल्में एवं म्यूज़िक देखने-सुनने और ई-बुक्स पढ़ने के लिए काफी अच्छा गैजेट है. यह 2.1 एंड्रॉयड ओ एस वर्जन पर ऑपरेट करता है. दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग, चैट एप्लिकेशंस और इनबिल्ट यूट्यूब एप्लीकेशन होने की वजह से जेनपैड इन्हें बेहतरीन तरीक़े से सपोर्ट करता है. जेन पैड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की चीजों, जैसे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन और ईमेल को हर वक़्त, कहीं भी आते-जाते हुए एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है. इसका एचडीएमआई केबल और आउटपुट इसे एलसीडी टीवी में लगाकर इसके कंटेंट को देखने का विकल्प प्रदान करता है. सिल्वर फ्रंट और ब्लैक बैक के कॉम्बिनेशन में यह सिर्फ़ एक कलर में उपलब्ध है.

सेनहाइज़र का नॉयज कैंसलिंग हेडफोन

आसपास का शोर ख़त्म करके बिल्कुल साफ आवाज़ सुनने की इच्छा सभी म्यूज़िक लिसनर्स को होती है. सेनहाइज़र ने ऐसा ही नॉयज कैंसलिंग हेडफोन बाज़ार में उतारा है. यह एक ऐसा हेडफोन है, जिसमें आसपास की अवांछित आवाज़ें फिल्टर हो जाती हैं और सिर्फ़ कंटेंट सुनाई देता है. सेनहाइज़र पीएक्ससी-250 एक्टिव नॉयज कैंसिलेशन की तकनीक पर आधारित इस हेडफोन से म्यूज़िक और दूसरे ऑडियो कंटेट सुनना काफी सुविधाजनक है. यह खासकर प्लेन, ट्रेन या किसी भी सफर में ऑडियो कंटेंट सुनने के लिए एक अच्छा विकल्प है. कंप्यूटर के साथ लगाने पर यह हेडफोन कंप्यूटर के साउंड को भी कैंसिल कर देता है. इस हेडफोन का बास साउंड काफी क्लीयर है और सुनने में बढ़िया लगता है.

हल्का और कैरी करने में आसान इस हेडफोन को कंपनी ने सुरक्षा के लिहाज़ से एक सुलभ कैरीकेस के साथ तैयार किया है. इसका साइज सभी उम्र या फिजिकल फिटनेस वाले लोगों के लिए सही है. इसमें लगा कुशन काफी कंफर्टेबल है. इस हेडफोन में रिकॉर्डिंग के लिए छोटे से माइक्रोफोन भी दिए गए हैं. इसका एडवांस सर्किट वातावरण में व्याप्त शोर ख़त्म कर सिर्फ़ अपेक्षित आवाज़ ही रिकॉर्ड करता है. अक्सर घर से बाहर रहने वाले लोगों के लिए यह हेडफोन और भी ख़ास है. यह स्टीरियो हेडफोन मिनी प्लग एडॉप्टर से जुड़कर लंबे वक़्त तक काम कर सकता है. सिर पर ठीक तरीक़े से पकड़ बनाए रखने के लिए इसमें पैडेड ड्यूरेबल स्टील टेप लगा है.

यह ख़ासकर प्लेन, ट्रेन या किसी भी सफ़र में ऑडियो कंटेंट सुनने के लिए एक अच्छा विकल्प है. कंप्यूटर के साथ लगाने पर यह हेडफोन कंप्यूटर के साउंड को भी कैंसिल कर देता है. इस हेडफोन का बास साउंड काफी क्लीयर है और सुनने में बढ़िया लगता है.

टी-शर्ट पर ग्राफिक्स की धूम

कैप्सुको एक ऐसी कंपनी है, जहां कुछ कर दिखाने वाले आर्टिस्ट अपना हुनर आजमा सकते हैं. वे कंपनी की वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाकर टी-शर्ट के लिए अपने डिज़ाइन बेचकर कमीशन के तौर पर पैसे कमा सकते हैं. कंपनी किसी भी बैकग्राउंड से जुड़े लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है. टी-शर्ट पर प्रिंटिंग के लिए कंपनी हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ इंक का इस्तेमाल करती है. वह सौ प्रतिशत कॉटन कपड़े पर प्रिंट कर टी-शर्ट बनवाती है. टी-शर्ट पर बने ग्राफिक्स को टिकाऊ बनाने के लिए उस पर कोटिंग भी की जाती है. कंपनी यंग डिजाइनरों के जुड़ाव से अस्तित्व में आई है. लगभग 150 डिज़ाइनों वाली टी-शर्ट्स के स्टॉक के साथ कंपनी दूसरे डिजाइनरों को भी ख़ुद से जुड़ने का मौक़ा देती है. उक्त टी-शर्ट्स बेहद कम क़ीमत पर उपलब्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट से भी ख़रीदी जा सकती हैं. कंपनी ने विभिन्न कलाकारों को जोड़कर एक बिजनेस ग्रुप तैयार किया और दुनिया के सामने मिसाल क़ायम की.

स्विंगर मिटाएगा दर्द

सर्दियों में अक्सर बदन दर्द, जकड़न की शिक़ायत बढ़ जाती है. इससे परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इप्सा लैब्स ने स्विंगर नामक दर्द निवारक मलहम बाज़ार में पेश किया है. यह जोड़ों के दर्द, सूजन, सिर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन की अकड़न, मोच, तनाव, मायोसिटिस, फाइब्रोसिटिस एवं सायटिका जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है. यह आयुर्वेदिक दर्द निवारक कई प्रकार की जड़ी-बूटियों जैसे पुदीने, नीलगिरी, पाइन, गुलथेरिया, लौंग एवं महुए आदि के तेलों का प्रभावकारी मिश्रण है. पुदीने का तेल तंत्रिकाओं एवं मांसपेशियों को आराम और ठंडक पहुंचाता है. इसमें फंगस एवं विषाणुरोधक गुण हैं. यह सिर दर्द को भी ठीक करता है. नीलगिरी सूजन, खिंची हुई मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए जाना जाता है. पाइन तेल जोड़ों का दर्द कम करता है. यह जख्म के जल्दी भरने में मदद करता है. गुलथेरिया का तेल रोगाणुरोधक एवं शक्तिवर्द्धक की तरह कार्य करता है. लौंग का तेल प्रभावकारी दर्दनाशक है. यह सिर दर्द एवं त्वचा की कई बीमारियों के इलाज में अत्यंत कारगर है. महुए का तेल मांसपेशियों की थकान, तनाव एवं जोड़ों के दर्द को दूर करता है. स्विंगर का 25 ग्राम का पैक 42 रुपये में सभी प्रमुख मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स में उपलब्ध है.

लॉजिटेक कीबोर्ड का मजा लीजिए

लॉजिटेक ने कंप्यूटर यूजर्स के लिए एक खास की-बोर्ड लांच किया है. यह वायरलेस इल्यूमिनेटेड की-बोर्ड मॉडल के-800 रिचार्जेबल है यानी बैट्री बदलने की कोई ज़रूरत नहीं. इसमें लगे माइक्रो यूएसबी केबल को प्लग में लगाकर आप टाइपिंग के साथ ही रीचार्ज कर सकते हैं. दिन हो रात, की ठीक से नज़र आए, इसके लिए इसमें बेहतरीन लाइट्स फिट हैं. इसमें एम्बिएंट लाइट्स और मोशन सेंसर के खास फीचर्स हैं, जिससे यूजर्स को सही मात्रा में बैकलाइट मिल सके. इसका बैकलाइटिंग सिस्टम मौसम के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है.

बैकलाइटिंग सिस्टम मौसम के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है. इसका खास फीचर मोशन सेंसर उंगलियों की पहुंच का आभास करके बैकलाइट ऑन कर देता है और उंगलियां हट जाने पर बैकलाइट ऑफ कर देता है.

इसका खास फीचर मोशन सेंसर उंगलियों की पहुंच का आभास करके बैकलाइट ऑन कर देता है और उंगलियां हट जाने पर बैकलाइट ऑफ कर देता है. इस की-बोर्ड में की-बटंस की डिज़ाइनिंग भी अलग तरीक़े से की गई है. इनमें लगे की-राउंड कोनो के साथ कॉनकेव डिज़ाइन के हैं. इसका परफेक्ट स्ट्रोक फीचर की से काम लेना आसान बनाता है, लंबे वक़्त तक इस की-बोर्ड पर काम करना आसान होता है. यही नहीं, इसके की जल्दी ख़राब भी नहीं होते और जल्दी निकलते भी नहीं. भारतीय बाज़ार में 2.4 गीगाहर्ट्ज की वायरलेस कनेक्टिविटी वाले इस की-बोर्ड की क़ीमत 6995 रुपये है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

विश्वकप से पहले भारतीय टीम ने जीत का ज़बरदस्त आगाज़ किया है. भारत ने जनवरी 2000 से अब तक विदेशी ज़मीन पर 23 टेस्ट मैच जीते हैं.

विश्व कप

कितनी तैयार है टीम इंडिया

कुमार सुशांत

सेंचुरियन में हुए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पारी और 25 रनों से मात दी थी. उसके बाद से ही भारत की रैंकिंग को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे, लेकिन डरबन में हुए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को उसी की धरती पर 87 रनों से हराकर साबित कर दिया कि रैंकिंग का असली हक़दार अब भी वही है. बल्लेबाज़ों के लिए कब्रगाह कही जाने वाली स्विंग और उछाल भरी पिच वाले किंग्समीड स्टेडियम पर अपनी शानदार पारी खेलकर भारतीय बल्लेबाज़ों ने बता दिया कि वे ऐसी पिच पर भी विपक्षी खिलाड़ियों को धूल चटा सकते हैं. डरबन में भारत की ऐतिहासिक जीत से इसलिए खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि 19 फरवरी से शुरू होने वाले विश्वकप से ठीक पहले साल 2010 में भारत ने ऐसे-ऐसे विपक्षी धुरंधरों को हराया है, जो विश्वकप में टीम के सामने रोड़ा साबित होते रहे हैं. कहा जाए तो विश्वकप से पहले यह शुरुआती ट्रायल है, लेकिन टीम इंडिया के लिए असली परीक्षा की घड़ी विश्वकप है. हालांकि उसके लिए फिटनेस का मामला चिंता का विषय रहा है. ऐसे में ज़रूरी है कि टीम अति उत्साहित न होती रहे और अपनी जीत का सिलसिला कायम रखे. डरबन में मिली जीत के साथ ही जहां भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ, वहीं कई भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन से पहली बार टेस्ट क्रिकेट के टॉप टेन में अपनी जगह बना ली. वीवीएस लक्ष्मण ने दूसरे टेस्ट में ज़हीर ख़ान के साथ 70 रनों की अहम साझीदारी की. लक्ष्मण ने इस मैच में 96 रन बनाए, जिसके साथ ही उन्हें पहली बार टेस्ट रैंकिंग के टॉप टेन में जगह मिली है. लक्ष्मण 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं दूसरे टेस्ट मैच में 93 रन देकर 6 विकेट गिराने वाले ज़हीर खान पहली बार चौथे पायदान पर पहुंचे हैं.

टीम इंडिया का असली मिशन है विश्वकप 2011, लेकिन विश्वकप में जीत के लिए टीम इंडिया की राह भी आसान नहीं है. एक तरफ़ भारतीय टीम का कीर्तिमान है तो दूसरी तरफ़ टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस का सवाल.

टीम इंडिया का असली मिशन है विश्वकप 2011, लेकिन विश्वकप में जीत के लिए टीम इंडिया की राह भी आसान नहीं है. एक तरफ भारतीय टीम का कीर्तिमान है तो दूसरी तरफ टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस का सवाल. टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनकी फिटनेस पर संदेह किया जाता रहा है. वीरेंद्र सहवाग कंधे की चोट से फिर परेशान हैं. सहवाग की इसी परेशानी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ 12 जनवरी से शुरू हो रही वन डे सीरीज में उनका खेलना संदिग्ध है. उनकी जगह रोहित शर्मा को मौक़ा मिल सकता है. सहवाग कंधे की परेशानी की वजह से इससे पहले भी टी-20 विश्वकप के दो मैचों में नहीं खेल सके थे. टीम में खिलाड़ियों का फिट-अनफिट होना चलता रहता है, लेकिन भारतीय टीम इससे कुछ ज़्यादा ही परेशान है. इसी साल भारतीय कोच गैरी कर्स्टन ने युवराज सिंह, ज़हीर ख़ान और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाए थे. इसके अलावा आशीष नेहरा और रविंद्र जडेजा की फिटनेस पर भी सवाल उठे थे. कर्स्टन ने कहा था कि 42 साल की उम्र में भी वह कई भारतीय खिलाड़ियों से ज़्यादा फिट हैं.

विश्वकप से पहले भारतीय टीम ने जीत का ज़बरदस्त आगाज़ किया है. भारत ने जनवरी 2000 से अब तक विदेशी ज़मीन पर 23 टेस्ट मैच जीते हैं. वहीं साल 2000 से पहले टीम इंडिया विदेशी धरती पर केवल 13 टेस्ट मैच जीत पाने में सफल रही थी. 1990 के दशक की बात करें तो भारत ने विदेशी धरती पर 39 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें उसने एक में ही जीत हासिल की. 15 मैच हारे थे और 23 ड्रॉ रहे. भारत ने 2000 से जिस तरह विदेशी धरती पर जीत हासिल की है, वे आंकड़े बताते हैं कि भारतीय बल्लेबाज़ पहले के मुकाबले अब स्विंग और उछाल भरी पिचों पर बेहतर खेल सकते हैं. इसके अलावा विश्वकप से पहले साल 2010 से जिस तरह जीत का सिलसिला बना है, उससे साफ है कि विश्वकप में इस बार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ नया होने वाला है. लेकिन टीम इंडिया को उस पर खरा उतरने के लिए अपनी सबसे बड़ी समस्या फिटनेस पर ध्यान देना होगा, तभी विश्पकप में चमत्कारी जीत मिल सकती है.

kumarsushant@chauthiduniya.com

डरबन में हासिल उपलब्धि

- भारत ने डरबन टेस्ट में जीत हासिल कर दक्षिण अफ्रीका को उसकी धरती पर दूसरी बार हराने में सफलता पाई. इससे पहले 2006 में जोहानिसबर्ग में भारत को 123 रनों से जीत मिली थी.
- भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक हुए कुल 26 टेस्ट मैचों में भारत की यह सातवीं जीत है. भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 12 टेस्ट मैचों में हार मिल चुकी है. बाकी मैच ड्रॉ रहे.
- साल 2010 में भारत की यह आठवीं जीत है.
- महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट मैच में टीम इंडिया का जीत का प्रतिशत 60 तक पहुंचाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने.
- वीवीएस लक्ष्मण ने डरबन टेस्ट मैच में 96 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को दूसरी बार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. लक्ष्मण पहली बार टेस्ट रैंकिंग में टॉप टेन में शामिल हुए. इससे पहले साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में लक्ष्मण ने 281 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.
- श्रीसंत ने 2010 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन डरबन टेस्ट मैच में दिखाया. उन्होंने 45 रन देकर तीन विकेट हासिल किए.

विश्वकप से पहले भारत का विजय अभियान

- न्यूज़ीलैंड के साथ हुई टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 से जीत हासिल की. वन डे मैचों में उसने न्यूज़ीलैंड को 5-0 से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया.
- ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई टेस्ट सीरीज में भारत ने 2-0 से जीत हासिल की. वहीं वन डे मैचों में उसने 1-0 से सीरीज जीती. दो मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहे.
- एशिया कप 2010 में भारत ने श्रीलंका को हराकर कप पर क़ब्ज़ा किया. भारत ने 15 साल बाद एशिया कप में जीत हासिल की.

नए कीर्तिमान

- 2010 में टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट मैचों में कुल 23 शतक. वहीं वन डे मैचों में 12 शतक टीम इंडिया के नाम हैं. 2010 में वन डे और टेस्ट मैचों में भारतीय बल्लेबाज़ों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया.
- 2010 में हुए कुल 14 टेस्ट मैचों में से भारत ने 8 में जीत हासिल की, 3 मैच हारे, जबकि 3 ड्रॉ रहे.
- 2010 में खेले गए कुल 27 मैचों में से 17 में भारत ने जीत हासिल की, वहीं 10 हारे.
- वन डे और टेस्ट मैचों में भारत की जीत का प्रतिशत दुनिया की क्रिकेट टीमों से काफ़ी आगे है.

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

यशराज बैनर की धूम, रवि चोपड़ा की बागवान, साजिद नाडियाडवाला की दीवाने हुए पागल रिमी सेन के छोटे से फिल्मी करियर की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं.

मेघना की नसीहत

कलियों का चमन गाने से विख्यात हुईं मेघना नायडू को डांस करने और गाने के अलावा घूमने का भी बहुत शौक है. उन्हें जब भी मौका मिलता है, वह अकेले या परिवार के साथ घूमने निकल जाती हैं. वैसे लंबी छुट्टियां वह विदेश में बिताना पसंद करती हैं. उनकी पसंदीदा जगह मियामी, न्यूयॉर्क और दुबई है, लेकिन भारत में उन्हें गोवा सबसे ज्यादा पसंद है. जब उन्हें ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलतीं तो वह गोवा जाना पसंद करती हूं. वह कहती हैं कि गोवा बहुत पास है और खूबसूरत भी. इसकेअलावा उन्हें नैनीताल, शिमला और केरल भी बहुत पसंद है.

वह कहती हैं कि यूं तो हर ट्रिप यादगार होती है, लेकिन पिछली फैमिली ट्रिप उन्हें हमेशा याद रहेगी, जिस पर वह कुछ दिनों पहले गई थीं. वह बताती हैं कि अर्से बाद उनका परिवार कुल्लू-मनाली घूमने गया था. इस दौरान उनके फैमिली फ्रेंड्स भी साथ थे. बहुत समय के बाद वह इस ट्रिप के बहाने अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता पाईं. घूमने-फिरने के नाम पर वह हमेशा तैयार रहती हैं और अगर मन करे तो अकेले भी घूमने निकल जाती हैं, लेकिन परिवार के साथ घूमने का मजा ही कुछ और है. दरअसल, तब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और जमकर मनोरंजन भी कर सकते हैं. आम लड़कियों को ट्रेवल टिप्स देते हुए वह कहती हैं, लड़कियां हमेशा अपने साथ ढेर सारा सामान ले जाती हैं, लेकिन यह सही नहीं है. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहां आप जा रहे हैं, वहां जरूरत का सामान आपको मिल ही जाएगा और एक्स्ट्रा सामान ले जाने की जरूरत ही क्या है! हां, कैमरा ले जाना न भूलें. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड और थोड़ा कैश भी साथ रखें. इनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है.

शबरी में ईशा

रामगोपाल वर्मा से ईशा कोप्पिकर लंबे समय से चिढ़ी हुई हैं और अब वह खुलकर उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर करने लगी हैं. बात यह है कि वर्षों पहले ईशा ने रामू की एक फिल्म शबरी में काम किया था. फिल्म को पूरे हुए चार साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वह सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई. ईशा का मानना है कि रामू की फिल्म के अन्य निर्माताओं से लड़ाई चल रही है और इस वजह से वह फिल्म को रिलीज करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. ईशा को यह बात इसलिए भी दुःख पहुंचा रही है, क्योंकि उनका मानना है कि शबरी उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है. इसमें उन्होंने महिला गैंगस्टर की भूमिका निभाई है. उनका शानदार अभिनय दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहा है. वह पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनकी यह फिल्म जल्दी प्रदर्शित हो. ईशा ने पिछले साल व्यवसायी टिम्मी नारंग से शादी की थी. कहा जाता है कि शादी के बाद हिंदी फिल्मों की हीरोइनों का करियर ही नहीं, उनका निजी जीवन भी पति और परिवार के दायरे में सिमट कर रह जाता है. लेकिन ईशा का मानना है कि शादी के बाद वह ज्यादा बिंदास हो गई हैं. वह कहती हैं, शादी बंधन नहीं, आजादी है. इसकी वजह है ईशा को पति टिम्मी नारंग से मिल रहा सहयोग. ईशा को आने वाले समय से बेहद आशाएं हैं और वह इस दिशा में पूरा प्रयत्न कर रही हैं. ईशा एक अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि बॉलीवुड में सफल शख्स को ही अच्छा कलाकार माना जाता है. ईशा बॉलीवुड में खल्लास गर्ल के नाम से जानी जाती हैं और उन चंद नायिकाओं में से एक हैं, जो बोल्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के किरदारों से दर्शकों को प्रभावित कर चुकी हैं.

आयशा का कॉफी शॉप

आयशा टाकिया आजकल बॉलीवुड के फिल्मकारों के प्रति अपनी नाराज़गी जता रही हैं. यह नाराजगी शादीशुदा अभिनेत्रियों के प्रति फिल्मकारों के उदासीन रवैये को लेकर है. उनका मानना है कि शादी के बाद लड़कियां और भी ज्यादा फ्री हो जाती हैं. यह समाज का बहुत ही संकीर्ण नजरिया है कि लड़कियां शादी के बाद घर की शो पीस बनकर रह जाती हैं, जबकि शादी के बाद तो लड़कियां ज्यादा फ्री हो सकती हैं, क्योंकि उनके साथ कोई देखभाल करने वाला भी होता है. शादी के बाद आयशा ने फिल्मों और फैशन डिजाइनिंग के अलावा कॉफी शॉप्स की चेन खोलने की बात कही है. वह देश के विभिन्न शहरों में कॉफी शॉप खोलेंगी और इसके लिए उन्होंने दौरा भी शुरू कर दिया है. अपने इस नए वेंचर को लेकर आयशा बेहद उत्साहित हैं और इसके लिए जी-जान से मेहनत कर रही हैं. वह कहती हैं कि फिल्में उनका कोर पैशन है, लेकिन फिलहाल वह अपने बिजनेस पर ही ध्यान दे रही हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मां के साथ ऐशा

अभिनेत्री ऐशा देओल ने अपनी मां एवं प्रख्यात अदाकारा हेमामालिनी के निर्देशन में बनी फिल्म टेल मी ओ खुदा में मुख्य भूमिका निभाई है. वह इस फिल्म की सहायक निर्देशक एवं संपादक भी हैं. उन्होंने इसमें तकनीकी सलाहकार की भूमिका भी निभाई. ऐशा कहती हैं, टेल मी ओ खुदा के दौरान मैंने फिल्म निर्माण के तकनीकी पहलुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन मेरे लिए अभी अपना कार्यक्षेत्र एकदम से बदलना जल्दबाजी होगा. हेमा ने ऐशा द्वारा फिल्म संपादन की पुष्टि की है. ऐशा कहती हैं, मैंने मां की मदद की, संपादन भी किया. मैं टेल मी ओ खुदा में उनकी सहायक रही हूं. मैंने कैमरे के पीछे की बहुत सी बातें सीखीं, अब संपादन सीख रही हूं. यह फिल्म मेरे लिए बेहतर रही. ऐशा ने 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने आठ साल के करियर में 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र और हेमामालिनी जैसे विख्यात कलाकारों की संतान ऐशा देओल को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली है. बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐशा को बचपन से ही फुटबॉल के प्रति काफी लगाव रहा है. निर्माता बोनी कपूर ने आफताब शिवदासानी के अपोजिट फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे में ऐशा को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद तो उनकी फ्लॉप फिल्मों की लाइन सी लग गई, लेकिन यशराज बैनर की फिल्म धूम की सफलता उनके लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. सच तो यह है कि धूम के बाद ऐशा की गिनती बॉलीवुड की सेक्सी हीरोइनों में होने लगी. बिंदास ऐशा को गुस्सा आ जाए तो वह किसी को थप्पड़ मारने में वक्त नहीं लगातीं. सुना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में किसी से उनका गहरा रिश्ता है. अब सच क्या है, यह तो ऐशा ही जानें!

फैंस के बीच रिमी सेन

अभिनेत्री रिमी सेन ने पिछले दिनों इंदौर जैसे छोटे शहर में प्रशंसकों के बीच अपना कुछ वक्त गुजारा. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म हंगामा से फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने वाली बंगाली बाला रिमी सेन ने थोड़े से समय में ही अपना नाम सफल अभिनेत्रियों में शुमार करा लिया है. आंखों में अभिनेत्री बनने का सपना लिए रिमी ने कोलकाता से मुंबई का रुख किया. शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें मॉडलिंग जगत से जुड़ने का मौका मिला. एक टेलीविजन विज्ञापन की शूटिंग के दौरान रिमी की मुलाकात प्रियदर्शन से हुई और उन्होंने रिमी को हंगामा केलिए साइन कर लिया. उसके बाद तो रिमी के पास बड़े बैनरों की फिल्मों की झड़ी सी लग गई. यशराज बैनर की धूम, रवि चोपड़ा की बागवान, साजिद नाडियाडवाला की दीवाने हुए पागल रिमी सेन के छोटे से फिल्मी करियर की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं. वह कई प्रतिष्ठित निर्माता-निर्देशकों की पसंद बन चुकी हैं. एक्शन दृश्यों से भरपूर फिल्म धूम में रिमी ने जहां अपनी हल्की-फुल्की भूमिका से दर्शकों को हंसने पर मजबूर किया, वहीं पिछले वर्ष प्रदर्शित जॉनी गद्दार में साजिशों की शिकार एक आम लड़की की भूमिका को भी उन्होंने काफी संजीदगी के साथ निभाया. रिमी की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे तो गाड़े, पर वह इसके श्रेय से हमेशा वंचित रहीं. लगातार बड़े बैनरों की फिल्में कर रहीं रिमी आज भी दूसरी श्रेणी की अभिनेत्रियों में ही शुमार होती हैं.

प्रीव्यू

टर्निंग 30

फिल्म टर्निंग 30 रिलीज से पहले ही विवादों में उलझ गई, लेकिन प्रकाश झा प्रोडक्शंस की इस फिल्म की रिलीज रोकी नहीं जा सकी. यह अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित और प्रकाश झा द्वारा निर्मित है. फिल्म की कहानी नैना नामक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपने 30वें जन्मदिन पर नौकरी छूटने और प्रेमी से रिश्ता टूटने की पीड़ा सहन करनी पड़ती है. यह फिल्म शादी से पहले सेक्स पर आधारित है. युवा निर्देशक अलंकृता का कहना है कि शादी से पहले सेक्स आजकल खराब नहीं माना जाता. भले ही लोग इस बात से मुंह फेरें, लेकिन सच्चाई यही है कि आजकल यह एक फैशन बन गया है. तीस वर्षीय अलंकृता श्रीवास्तव ने दावा किया कि वह समाज की इसी सच्चाई को पर्दे पर रीयल ढंग से पेश करने वाली हैं और इसके लिए उन्होंने गुल पनाग को चुना है, जो नौकरी की वजह से शादी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें शादी से पहले सेक्स करने से परहेज नहीं है.

अलंकृता कहती हैं कि इन दिनों महिलाएं फिल्म निर्माण केलगभग हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब भी पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म में 31 वर्षीय अभिनेत्री गुल पनाग के साथ पूरब कोहली ने अभिनय किया है. अलंकृता कहती हैं कि टर्निंग 30 खुद उन्हीं की जिंदगी का एक टुकड़ा है. एक महिला निर्देशक होना अद्भुत है, लेकिन यह भी सच है कि महिला निर्देशक धीरे-धीरे टूटकर दूर होने लगती हैं. बावजूद इसके वह यहां हैं. बकौल अलंकृता, मैं फिल्मोद्योग में 22 साल की उम्र से काम कर रही हूं, इसलिए सेट पर हमेशा सहज रहती हूं. मेरे लिए यह कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन आप कुछ बातें महसूस करते हैं. अलंकृता फिल्म गंगाजल और राजनीति में बतौर सहायक निर्देशक काम कर चुकी हैं, जबकि फिल्म दिल, दोस्ती, एटसेट्रा और खोया-खोया चांद में वह कार्यकारी निर्माता थीं. वह फिल्म अपहरण और लोकनायक की मुख्य सहायक निर्देशक थीं.

वह कहती हैं, फिल्म की शूटिंग के बाद की निर्माण प्रक्रिया के दौरान मैंने अक्सर महसूस किया कि स्टूडियो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है. लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते. आपको खुद को साबित करना पड़ता है. आपको कई बार ऐसा करना पड़ता है, ताकि वे आपको गंभीरता से लें. आखिरकार यह एक पितृसत्तात्मक उद्योग है. मैं किसी खास घटना या उदाहरण की ओर इशारा नहीं करूंगी, लेकिन सच यह है कि यहां वास्तव में ऐसा है. मेरे निर्देशन में बनी पहली फिल्म आगामी 14 जनवरी को प्रदर्शित होगी. अलंकृता का मानना है कि 30 साल की उम्र के बाद जिंदगी बहुत अनिश्चित हो जाती है. धीर-गंभीर किरदारों में नजर आने वाली पूर्व मिस इंडिया एवं अभिनेत्री गुल पनाग अब जल्द ही हंसाने केलिए तैयार हैं. गुल की चर्चित कॉमेडी फिल्म टर्निंग 30 नए साल में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 10 जनवरी-16 जनवरी 2011

www.chauthiduniya.com

वोट के बदले चोट

महादलितों के उत्थान में सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे यह तक नहीं मालूम कि कितने महादलितों को योजना का लाभ मिला है और कितनों को देना है. यही वजह है कि महादलितों को लग रहा है कि चुनावी चौसर पर उनका सियासी इस्तेमाल करके उन्हें नैपकीन की तरह कूड़ेदान में डाला जा सकता है.

सरोज सिंह

नीतीश कुमार को बिहार में जो प्रचंड जनादेश मिला है, उसमें महादलित समुदाय की भूमिका काफ़ी अहम मानी गई. महादलितों ने चुनाव में जिस तरह एनडीए के लिए दिल खोला, ठीक उसी तरह वे चाहते हैं कि सरकार उनकी भलाई के लिए खजाना खोले. मगर हाकिमों की सुस्ती के कारण उनके दिलों को चोट पहुंच रही है. उन्हें लग रहा है कि चुनावी चौसर पर उनका सियासी इस्तेमाल हुआ है. महादलितों को तीन डिसमिल ज़मीन या बीस हज़ार रुपये देने की योजना के मौजूदा हाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं. महादलितों के उत्थान के लिए सरकार कितना सोचती है, इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार को असल में अपनी योजना का ही पता नहीं है. हालांकि मंत्री रमई राम दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और यह सरकार महादलितों के लिए इतना काम करेगी कि दुनिया में एक मिसाल कायम होगी.

भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रमई राम के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष से ही महादलितों को भूमि आवंटित की जा रही है. लेकिन कितने महादलित लाभांवित हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा उनके विभाग के पास नहीं है. विभागीय अधिकारी इस पर टालमटोल करते हुए कहते हैं कि फरवरी माह में यह आंकड़ा उपलब्ध हो पाएगा. दिलचस्प है कि अभी तक रमई राम के पास यह संख्या भी नहीं है कि कितने महादलितों को इस योजना के तहत भूमि दी जानी है. इस संबंध में उन्होंने ज़िला समाहर्ताओं को प्रस्ताव देने को कहा है. जबकि उनका कहना है कि विगत वर्ष ही ज़मीन का वितरण भी शुरू हो चुका है. यह काफ़ी विरोधाभासी प्रतीत होता है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी को तो दाल में काला नज़र आता है. वह कहते हैं, बहुत घालमेल है. महादलितों का बढ़ता दायरा ही सरकार के गले की फांस बन गया है. पहले चार जातियों को महादलितों के कोटे से बाहर रखा गया था. राजनीतिक कुचक्र में अब पासवान के अलावा सभी अनुसूचित जातियां इसमें शामिल हो गईं. लिहाजा अनुसूचित जातियों की तकरीबन 80 से 90 फ़ीसदी आबादी को महादलित करार दिया जा चुका है, जिन्हें तीन डिसमिल ज़मीन देना सरकार के लिए भारी पड़ रहा है. इसलिए इसे ठंडे बस्ते में डालने की साजिश चल रही है.

नीतीश सरकार में महादलितों के प्रति नीतिगत मामलों में तुगलकी तौर-तरीके ही आजमाए गए हैं. सबसे पहले महादलित आयोग गठित कर दलित समुदाय का एक नया वर्गीकरण किया गया, जिसमें अनुसूचित जातियों में से मोची, पासवान, धोबी एवं पासी बिरादरी के अलावा अन्य जातियों को महादलित घोषित कर दिया गया. ऐसा करना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि में बाधक साबित हो सकता था, लिहाजा महादलित आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहले धोबी एवं पासी को भी दलित से महादलित का चोला ओढ़ा दिया गया. इसके बाद भी मन में कुछ फांस रह गई थी तो पुन: मोची समुदाय को भी दलित से महादलित के तौर पर रूपांतरित कर दिया गया. बिहार में सिर्फ़ पासवान जाति ही आधिकारिक तौर पर दलित कहलाने की हक़दार रह गई. कुर्सी जनित राजनीति का विद्रूप चेहरा तब उजागर हुआ, जब पासवान समुदाय को भी संतुष्ट करने की नीयत से भविष्य में उन्हें भी महादलित का दर्जा प्रदान करने का मुलम्मा दिया गया. सिर पर मैला ढोने को विवश मेहतर समुदाय के लोगों के लिए इक्कीसवीं सदी का भारत और उसके विकास की अंधी दौड़ कोई मायने नहीं रखती है. बिहार में मुसहर जाति भी इसी वंचित तबके का प्रतिनिधित्व करती है. इसकी आबादी तकरीबन तीस लाख है. इनमें प्राय: 99 फीसदी के लगभग भूमिहीन हैं. इनके पास घर बनाने की भी ज़मीन नहीं है. सर्व शिक्षा अभियान के इस युग में भी इस समुदाय के सिर्फ़ नौ प्रतिशत बच्चे ही स्कूल जाते हैं. मल्टी मीडिया के इस हाईटेक युग में भी मुसहर बिरादरी की साक्षरता दर मात्र सात फ़ीसदी है. राज्य सरकार के योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश के अनुसार, मुसहर समुदाय के महादलितों में 96 प्रतिशत लोगों का स्थायी पता ही नहीं है. आवासीय भूखंड न होने के कारण वे ऐसी स्थिति से दो-चार हैं. जब तक उन्हें ज़मीन उपलब्ध कराकर बसाया नहीं जाएगा, तब तक वे समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाएंगे.

मुसहर-भुइंया विकास परिषद के सह संयोजक गजेंद्र मांझी का मानना है कि महादलित घोषित होने से मुसहरों को कोई खास लाभ तो नहीं हुआ, हानि ही हुई है. पहले दलित होने के कारण सवर्ण समुदाय के लोग प्रताड़ित करते थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा महादलित का दर्जा प्रदान करने के बाद ज़िंदगी और खराब हो गई है. इसके बाद तो दलित भी इन्हें सार्वजनिक तौर चिढ़ाने एवं अपमानित करने में नहीं हिचकते. जहां कहीं भी पासवान मुखिया हैं, आमतौर पर वे इस समाज के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं. इन्हें कहा जाता है कि अब ये दलित नहीं रहे, अत: दलितों को संविधान प्रदत्त सुविधाओं के हकदार भी नहीं रहे. इसके बावजूद सरकार गठन के बाद भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की पहली समीक्षा बैठक में महादलितों को तीन डिसमिल ज़मीन देने की महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका. हालांकि इस योजना पर पूरी तरह अमल करने में विलंब के कई कारण बताए जाते हैं. मसलन, विभाग पूरी तरह अवगत नहीं है कि कितने महादलितों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध करानी है! रमई राम इसकी तस्दीक करते हुए कहते हैं कि महादलितों को तीन डिसमिल ज़मीन ख़रीद कर देने का प्रावधान है, लेकिन कई ज़िलों में ज़मीन की कीमतें आसमान छू रही हैं. इसलिए जिला समाहर्ताओं से प्रस्ताव मांगे गए हैं. प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महादलित समुदाय के लाभार्थियों की बहुप्रतीक्षित आस पूरी हो पाएगी. महादलित आयोग के सदस्य बबन राउत कहते हैं कि महादलित समुदाय के लोगों को भूमि प्रदान करने में अब विलंब नहीं होना चाहिए. युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष शिवचंद्र राम तो महादलितों के कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ही सवालिया निशान लगाते हैं. उनकी मानें तो उन्हें रेडियो, टीवी आदि कुछ भी नहीं दिया गया है. सिर्फ़ जुबानी जमा-ख़र्च से ही काम चलाया जा रहा है. शिवचंद्र राम कहते हैं कि राज्य सरकार ने अगर महादलितों को ज़मीन दी है तो वह बताए कि सरकार की नाक के नीचे राजधानी पटना एवं इसके निकटवर्ती फुलवारी के महादलितों को ज़मीन मयस्सर क्यों नहीं हुई है. लेकिन बबन राउत इससे इत्तेफाक नहीं रखते. इनकी मानें तो महादलितों को मुख्यधारा से जोड़ने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार काफ़ी सफल रही है. इनके जीवन स्तर में आए बदलाव से यह महसूस किया जा सकता है. महादलितों के लिए शौचालय, महादलित टोले से पहुंच पथ, दस हज़ार विकास मित्रों की मानदेय पर बहाली, रेडियो आदि के वितरण से समाज का यह हिस्सा भी अब ख़ुद को उपेक्षित महसूस नहीं कर रहा है.

बहरहाल, राजनीतिक नफ़ा-नुकसान से दूर अगर महादलितों की पीड़ा का एहसास सरकार को है तो यह उम्मीद की जा सकती है कि सुस्ती का दौर ख़त्म होगा और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े महादलितों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा.

feedback@chauthiduniya.com

महादलित का विकास नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक स्टंट मात्र है. वह सिर्फ़ वोट के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं.

- अशोक चौधरी

नीतीश कुमार ने केवल वोट के लिए दलितों को तोड़ा और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया. दलितों की भलाई से उनका कोई लेना देना नहीं है.

-रामचंद्र पासवान

नीतीश कुमार महादलितों से इतना ही प्रेम करते हैं तो अनुसूचित जातियों की सरकारी नौकरी में आरक्षित पदों के दो लाख के बैकलॉग को क्यों नहीं भरते हैं.

- शिवचंद्र राम, युवा राजद

महादलितों के जीवन में आशा किरण संचार करने के अगुवा हैं नीतीश कुमार. महादलितों को उनका हक़ मिल रहा है.

- बब्बन राउत, सदस्य, महादलित आयोग

सब कुछ ठीक चल रहा है और यह सरकार महादलितों के लिए इतना काम करेगी कि दुनिया में एक मिसाल कायम होगी.

- रमई राम, सुधार एवं राजस्व मंत्री

आलीशान बंगले के निर्माण में उनकी गाढ़ी कमाई का योगदान है. वहीं हुलास पांडेय कहते हैं कि यह बंगला लूट की कमाई का प्रतीक है.

केसरिया स्थित विश्व का सबसे उंचा बौद्ध स्तूप. यहां महोत्सव भी होता है और मंत्री इसके विकास के लिए धन का पिटारा भी खोलते हैं लेकिन पता नहीं, कब यह स्थान बौद्ध सर्किट से जुड़ेगा.

एक नज़र इधर भी

साल भर में ही टूट गई सड़क

एक तरफ़ सरकार चाहती है कि राज्य का हर गांव पक्की सड़कों के माध्यम से ज़िला मुख्यालय से जुड़ जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही कुछ अधिकारी लूट खसोट में लिप्त दिख रहे हैं. मामला रोहतास ज़िले में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सासाराम द्वारा मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाए गए सेमरा मध्य विद्यालय से पिपरी होते हुए कठडिहरी पथ में हुए अनियमितता की है. उक्त पथ का निर्माण 1 करोड़ 45 लाख 26 हजार 2 सौ रूपए की लागत से हुआ. पथ बनने के एक वर्ष बाद से ही टूटने लगा. ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारियों से की गई, लेकिन पथ की मरम्मत तो दूर प्राक्कलन के अनुसार पांच वर्षों तक रख रखाव के लिए अतिरिक्त राशि रहती है, उसका भी उपयोग नहीं किया जा रहा है. लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक पथ में लंबी-लंबी दरारें पड़ी हैं. जिससे पैदल भी चलने वालों को भी काफी कठिनाई हो रही है.

सेल की खदानों को मिला स्वर्ण पदक

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हैदराबाद में आयोजित क्वालिटी कांसेप्ट सर्किल के2010 केअंतरराष्ट्रीय मिशन केतहत पुरस्कृत किया गया. सेल के सेनेटेरिल्स डिविजन की क्वालिटी सर्किल टीमों को दो स्वर्ण पदक, दो रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ है. मालूम हो कि सेल केरिसर्च एंड डेवलपमेंट डिविजन के 5 क्वालिटी सर्किल दलों ने नई तकनीक विकसित कर खदान कार्यों को सुगम बनाते हुए समय और संसाधन की काफी बचत की है. इसके पूर्व भी आरएंडडी की टीमों को कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. सेल की किरीबुरु खदान की समाधान और बोलानी की कोणार्क टीम को स्वर्ण पदक, गोवा की प्रगति तथा बोलानी की टीम को रजत पदक और किरीबुरु की एक और टीम उन्नति को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है. सेल की इस उपलब्धि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

जेएसपीएल को फोर्ब्स एशिया पुरस्कार

निजी क्षेत्र की ख्यातिप्राप्त कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को लगातार दूसरी बार फोर्ब्स एशिया द्वारा शानदार 50 कंपनियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में आयोजित समारोह में एशिया के कॉरपोरेट जगत की नामचीन हस्तियों की मौजूदगी में फोर्ब्स एशिया द्वारा कंपनी केमुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा सुशील मारू को यह सम्मान दिया गया. सम्मान प्राप्त करने के बाद मारू ने कहा कि यह पुरस्कार प्राप्त करना कंपनी ही नहीं पूरे देश के लिये गौरव की बात है. हमारी कंपनी के लिये यह पुरस्कार प्राप्त करना विश्वस्तरीय कंपनियों के समूह में शामिल होने का प्रमाण पत्र है. उन्होंने कहा कि जेएसपीएल के संस्थापक स्व. ओपी जिंदल की दूरदर्शिता और कंपनी केकार्यकारी उपाध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक नवीन जिंदल के कुशल नेतृत्व ने जेएसपीएल को एक विश्वस्तरीय कंपनी के रूप में पहचान दिलायी है. उन्होंने इस पुरस्कार को कंपनी की पूरी टीम केपरिश्रम का परिणाम बताया.

- चौथी दुनिया ब्यूरो

पंचायत समिति की बैठक में हंगामा

कैमूर में पंचायत समिति की बैठक में शिक्षक नियोजन का मुद्दा छाया रहा . इस संबंध में पूर्व के निर्णय पर अमल न होने के कारण भारी हंगामा हुआ और दर्जन भर मुखिया ने बैठक का बहिष्कार किया. बैठक में विभागीय पदाधिकारियों पर सदन की अवमानना का आरोप लगाया और कहा कि पदाधिकारी सदन के निर्णय को दरकिनार कर अपनी मनमानी करते हैं. बताया जाता है कि पंचायत समिति की बैठक में चार माह पहले यह निर्णय लिया गया था कि जो शिक्षक प्रतिनियोजित हैं, उनका प्रतिनियोजक तत्काल रद्द किया जाण व उन्हें इनके स्कूल भेजा जाए. पर आजतक ऐसा नहीं किया गया . इस मसले को लेकर मुखिया लोगों ने भारी आक्रोश जताया.

- सोनम सिन्हा

न्याय और अधिकार से वंचित विकलांग विनोद

यह तस्वीर है विकलांग विनोद कुमार साह की. ये पिछले दो दशक से समस्तीपुर ज़िले में अनुसेवक के पद पर नियुक्ति की आस लगाए हैं. नीतीश कुमार के प्रथम कार्यकाल में समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय एवं अस्पतालों में 90 उम्मीदवार अनुसेवकों की नियुक्ति हो गई, लेकिन उन्हें मलाल है कि विकलांगों के प्रति सहानुभूति रखने वाली सरकार में भी वह न्याय और अधिकार से वंचित रह गये. समस्तीपुर नगर परिशद वार्ड नं.-12 काशीपुर के निवासी विनोद कहते हैं कि 12 मार्च 2010 को उसने दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई थी और प्रमंडलीय आयुक्त के सकारात्मक रवैये व आदेश के बावजूद भी तत्कालीन जिलाधिकारी असंगबा चूबा आओ ने अनुसेवकों के स्थायी नियुक्ति के मामले में विकलांग अनुसेवक उम्मीदवार की अनदेखी कर दी.

- अजय कुमार सिन्हा

स्टेशन पर असामाजिक तत्वों का बोलबाला

पूर्व मध्यरेल के समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड में अवस्थित रूसेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव की वजह से इसे महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है, लेकिन रेल प्रशासन के उपेक्षापूर्ण रवैए के कारण यात्रियों के जान-माल पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है. कारण कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यहां रेल पुलिस की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, जिससे शाम ढलने के बाद स्टेशन परिसर में असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाता है. रात के समय में यदि स्टेशन परिसर में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं या युवतियां मजबूरीवश रुकती हैं तो उन्हें इन असामाजिक तत्वों की मनमानी झेलनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी स्टेशनकर्मियों को नहीं है, लेकिन वे भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था की अनुपलब्धता के चलते मूकदर्शक बने रहना ही बेहतर समझते हैं. बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यहां जीआरपी के मात्र एक जवान की ही व्यवस्था है, जिसे स्वयं ही अपनी ही सुरक्षा की चिंता सताती रहती है.

- संजीव कुमार सिंह

खाने के नाम पर ज़हर

नीरज कुमार सिंह

सरकार जनता के कल्याण के लिए चाहे कितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चला ले लेकिन हकीक़त यही है कि ये सारी योजनाएं सही मायने में धरातल पर उतरती नज़र नहीं आ रही हैं. आलम यह है कि पूरे सीमांचल में बच्चों के लिए चलने वाली मध्याह्न भोजन योजना में प्रशासनिक स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक लूट-खसोट मची हुई है और बच्चों को जो खाना परोसा जा रहा है वह मेनू तो क्या गुणवत्ता से भी परे है. मालूम हो कि सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और निरक्षरता दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना चला रखी है. ताकि बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़कर पलायन न कर जाएं. साथ ही उन बच्चों को भी विद्यालय लाया जा सके, जो भोजन के अभाव में विद्यालय आने से कतराते हैं और गरीबी के कारण अपने माता-पिता के साथ या कहीं अन्य निरक्षर रहकर काम में लग जाते हैं. ऐसा नहीं है कि मध्यर्या न भोजन योजना चलने से जनता को लाभ नहीं मिला. इस योजना के चलने से विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में काफी वृद्धि हुई. जो बच्चे भोजन के अभाव में विद्यालय नहीं आ सकते थे, वे विद्यालय की तरफ़ रुख़ करने लगे. इन बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी, लेकिन इस योजना का दूसरा पहलू यह निकला कि प्रशासनिक स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक लूटखसोट चालू हो गई. आज सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार ज़िले में बच्चों को जो भोजन विद्यालय में परोसा जा रहा है, उसमें गुणवत्ता कहीं नज़र नहीं आ रही है और बच्चे या तो बीच में ही भोजन छोड़कर पलायन कर जाते हैं या जानवरों को खिला देते हैं.

सरकारी प्रावधान के अनुसार महीने में कम से कम 25 दिन बच्चों को मध्यर्या न भोजन मिलना चाहिए. यह सप्ताह में लागू भोजन मेनू के अनुसार चलेगा लेकिन हक़ीक़त है कि बच्चों को मेनू के विपरीत सब्ज़ी, भात, खिचड़ी एवं पानी वाली दाल के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है. सीमांचल के शहरी क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय के विद्यालय को छोड़कर अगर दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों पर नज़र डाली जाए तो कुछ विद्यालय ऐसे भी ज़रूर मिल जाएंगे, जहां मध्यर्या न भोजन महीनों से बंद पड़े अवश्य मिल जाएंगे. इन विद्यालयों के प्रधान की दलील यह है कि राशि के अभाव में मध्यर्या न भोजन बंद है. कुछ ऐसे भी विद्यालय है, जहां के प्रधान महीने में औसतन 10-12 दिन मध्यर्या न भोजन चलाकर पूरे महीने का मध्यर्या न भोजन दिखाकर पैसे व चावल का घालमोल कर लेते हैं. एक विद्यालय के प्रधान ने अपना नाम गुप्त रखने पर जानकारी दी की मध्यर्या न भोजन योजना मद के ड्रॉफ्ट लेने पर ज़िला से प्रंखड कार्यालय में चढ़ावा देना पड़ता है, जिसमें साधन सेवी बिचौलिये की भूमिका निभाता है. सरकार ने विद्यालय स्तर पर मध्यर्या न भोजन योजना की हालत देखकर एनजीओ के माध्यम से मध्यर्या न भोजन योजना चलाने का निर्णय लिया. इसके तहत पूर्णिया में दिल्ली की राष्ट्रीय निर्बल उत्थान संस्थान को मध्यर्या न भोजन चलाने का भार सौंपा. इससे पहले जिले के 320 विद्यालयों में इस संस्था के माध्यम से मध्यर्या न भोजन की गुणवत्ता एवं बासी-ताज़ा भोजन को लेकर दूर-दराज के ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में एक नया बबाल खड़ा हुआ. अत: भोजन को फेंकने, लौटाने की घटना को लेकर इस संस्था द्वारा दूर-दराज के इलाकों के विद्यालयों में संचालित भोजन पर रोक लगा दी गई. इसके बाद जिले के शहरी एवं 9 अर्द्धशहरी क्षेत्रों की मात्र 104 विद्यालयों में इस संस्था को भोजन चलाने का निर्देश दिया गया. जब चौथी दुनिया ने आम नागरिकों के बुलाने पर गुलाबबाग के हरिचंद्र नगर स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में इस संस्था द्वारा संचालित भोजन को देखा तो वहां उपस्थित बच्चे बोल पड़े कि अंकल प्लीज इस भोजन को देखिये, क्या यह इंसानों के खाने लायक है. इस भोजन को खाने से हम बीमार नहीं हो जाएंगे. जब निर्बल उत्थान संस्थान से इस संबंध में जानकारी ली गई तो संस्था के व्यवस्थापक लालचंद जैन ने जानकारी दी की संस्था दिल्ली की है और उसके अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल हैं. लालचंद जैन ने बताया कि सरकारी मेनू में सोमवार को सब्जी-चावल, मंगलवार को आलू-राजमा चावल, बुधवार को चावल सोयाबड़ी, गुरुवार को चावल-दाल सब्जी, शुक्रवार को चावल छोला व शनिवार को खिचड़ी-चोखा खिलाने का प्रावधान है. वैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी किचन का हर समय निरीक्षण करते रहते हैं. जब मंगलवार को चावल, आलू गया तो इस संबंध में कुछ बोल नहीं सके. जब किचन घर में ही संस्थान से संबंधित लोगों के लिए अलग किचन व बच्चों के मध्यर्या न भोजन के लिए अलग किचन के बारे में पूछा गया और यह सवाल किया गया कि जब बच्चे यह भोजन कर सकते हैं तो आपलोगों के लिए अलग भोजन की व्यवस्था क्यों है. इस पर वह कुछ भी बोलने से कतराने लगे. वैसे भी पूर्णिया व किशनगंज में शिक्षा विभाग योजना में शिक्षा विभाग के पद पर बैठे कुछ अधिकारियों पर मध्यर्या न भोजन योजना में घपलेबाजी के आरोपों के बाद भी वे अपने पद पर डटे हैं. लोगों का कहना है कि अगर मध्यर्या न भोजन सुधर जाए तो विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति और साक्षरता बढ़ेगी.

feedback@chauthiduniya.com

नज़र लागी राजा तोरे बंगले पर

सासाराम के सीवी टेक कंसट्रक्शन निदेशक डीएम सिंह से विधान पार्षद हुलास पांडेय व उनके साथियों द्वारा कथित तौर पर मांगी गई रंगदारी की घटना भले ही नई हो, लेकिन इन दोनों महानुभावों का दोस्ताना वर्षों पुराना है. भले ही दोनों इससे इंकार कर दें, लेकिन लोग तो यही कहते हैं.

यह दोस्ताना 10 वर्षों से चल रहा था, जब पुसौली में पावरग्रिड का निर्माण शुरू हुआ. फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का निर्माण शुरू हुआ तो व्यवसायिक संबंध भी मजबूत हुए. संबंधों के मंथन से निकली राशि का जीता जागता उदाहरण सासाराम का वह आलीशान बंगला है, जिस पर अब हुलास पांडेय ही नहीं, कई लोगों की नज़रे गड़ी हैं. इसके निर्माण कार्य के साथ-साथ जीटी रोड के पुनर्निर्माण एवं पावरग्रिड का काम भी समाप्त हुआ. अब बारी आई पैसों की हिस्सेदारी की. डीएन सिंह की मानें तो उनके आलीशान बंगले के निर्माण में उनकी गाढ़ी कमाई का योगदान है. वहीं हुलास पांडेय कहते हैं कि यह बंगला लूट की कमाई का प्रतीक है. लेकिन आम लोगों के गले यह बात नहीं उतर रही कि सचमुच में इन दोनों परिवारों के संबंधों में खटास आ गई है. अहम बात यह है कि एक दशक पूर्व सासाराम में कंसट्रक्शन कंपनी लेकर आए डीएन सिंह ने जिस तरह से अपना व्यवसाय फैलाया, उसे देखकर लोगों ने उसी समय कहना शुरू कर दिया था कि इस व्यवसाय के पीछे ज़रूर कोई बड़ा हाथ है. अब जब उन्होंने हुलास पांडेय पर रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज कराई है और पांडेय ने अपनी बकाया राशि मांगने की बात कही है, तो ऐसे में मतलब साफ हो रहा है कि पूर्व में आरोपी एवं अभियोजन, दोनों पक्षों के बीच कोई व्यवसायिक संबंध ज़रूर रहे होंगे, तभी इतनी बड़ी राशि के अंतर सामने आ रहे हैं. यही नहीं, पांडेय ने अपनी पत्नी के नाम से चल रही एक कंसट्रक्शन कंपनी के लिए डीएन सिंह द्वारा चेक दिए जाने की बात भी कही है. फ़िलहाल पूरी कहानी को देखकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं डीएन सिंह के आलीशान संगमरमरी बंगले पर हुलास पांडेय ही नहीं कुछ और देनदारों की भी नज़र है. वैसे शहर में एक अन्य नई कंसट्रक्शन कंपनी को लेकर पहुंचे एक महानुभाव ने संगमरमर का ना सही, शीशे का घर जरूर बनवाया है. इस पर भी ऐसा मामला बन सकता है, क्योंकि, वहां भी कुछ दबंगों के उठने-बैठने एवं व्यवसाय में सहभागिता की बात सुनने को मिल रही हैं.

सासाराम

कुल मिलाकर तो यकी की सकते हैं कि नज़र लागी राजा तोरे बंगले पे.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

छपरा
पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी

बिजेंद्र कुमार

पिछले महीने समाप्त हुए विधान सभा चुनाव की चर्चाएं अभी पूरी तरह थमी भी नहीं हैं कि अप्रैल-मई में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गंवई की राजनीति परवान चढ़ने लगी है. पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं. संभावित उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क साधने में जुट गए हैं. इस क्रम में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार की कमियों को उजागर कर मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास करता दिख रहा है. नये साल में उम्मीदवारों की तरफ़ से शुभकामना संदेश दिये जाने को लेकर प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है. वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव को लेकर ज़िला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है. पिछले दिनों सारण प्रमंडल की आयुक्त अंशुली आर्या ने पंचायत चुनाव को लेकर प्रमंडलीय समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. ज़िले के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह तय हुआ है कि प्रत्येक बूथ पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की जाएगी ताकि विधान सभा की तरह पंचायत चुनाव भी शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से हो सकें. पंचायत चुनाव दस चरणों में कराए जाने की मांग आयोग से की गई है. इसके अलावा बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. बैठक में सारण क्षेत्र के डीआईजी सुनील कुमार सिन्हा, सीवान डीएम लोकेश कुमार सिंह, गोपालगंज डीएम बाला डी मुरुजन, सारण के पुलिस अधीक्षक ए.के. सत्यार्थी, सीवान के पुलिस अधीक्षक कप्तान अमृत राज व गोपालंज के पुलिस प्रमुख के अनुपम सहित कई वरीय अधिकारी शामिल हुए. आगामी पंचायत चुनाव में ज़िले में लगभग 10 हज़ार मतपेटियों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा अनुमान है. ऐसी स्थिति में पर्याप्त मतपेटियों की व्यवस्था करने में प्रशासन तैयार है. पंचायतीराज अधिनियम के तहत दो पंचायत चुनावों के उपरांत ही आरक्षण रोस्टर में बदलाव का प्रावधान किया गया है. इसके कारण त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी पद पूर्ववत रहेंगे. यह अलग बात है कि चालू वर्ष के प्रारंभ में परसा नगर पंचायत के गठन के बाद ज़िले में चार मुखिया, चार सरपंच, चार पंचायत समिति सदस्य, 56 पंच व 56 वार्ड सदस्य के पद समाप्त हो जाएंगे. आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज़िले में 47 ज़िला परिषद सदस्य, 326, मुखिया, 326 सरपंच व 465 पंचायत समिति सदस्यों के अलावा 4628 पंचायत सदस्य व इतने ही पंचों का चुनाव होना है. जिसमें पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 50 प्रतिशत महिलाओं के अलावा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है. पंचायत चुनाव में नए युवा वोटरों को शरीक होने के लिए विशेष मौका दिया है. वैसे युवा, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2011 को 18 पूरी हो रही है, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से अपना नाम जोड़ने का आवेदन दे सकते हैं.

चार पंचायतों में नहीं पड़ेंगे वोट

ज़िले में आगामी वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में परसा प्रखंड की चार पंचायतों के 124 पदों के लिए वोट नहीं होगा. पंचायती राज विभाग ने उक्त प्रखंड की चार पंचायतों के 124 पंचायत प्रतिनिधियों के पदों को विलोपित कर दिया है. जबकि इसी के साथ नगर पंचायत का मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते एकमा नगर पंचायत का नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थगित रखा गया है, जिसके आधार पर वहां पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है.

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार ज़िले में पहले 330 पंचायत गठित हुए थे, जहां पूर्व में चुनाव कराए जाते रहे हैं. फ़िलहाल परसा को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो जाने पर इसकी चार पंचायतें उसमें समाहित हो गई हैं. इस वजह से पंचायती राज विभाग ने परसा प्रखंड के शंकरडीह, दरियापुर प्रखंड के पोझी खजौली, बिसाही व सैदपुर को विलोपित कर दिया है. अधिसूचना के मुताबिक़ परसा बाज़ार नगर पंचायत गठित हो जाने के बाद ज़िले में अगले वर्ष 326 पंचायतों की विलोपित किया गया है. इसके अधीन 124 पदों को समाप्त कर दिया गया है. जिसमें मुखिया पद के 4, सरपंच 4, बीडीसी-4, वार्ड सदस्य-56 तथा पंचायत का 56 पद शामिल है. पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी चल रही है. मतदाता सूची के निपटारे का कार्य ज़ोरों पर है. चुनाव आयोग के निर्देश पर 8 जनवरी 2011 तक मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने का फरमान है, जबकि विधान सभा चुनाव में फ़र्ज़ी मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने की आम शिकायत मिल रही है. जिसे हटाने के लिए संभावित प्रत्याशियों की आंखों की नींद ग़ायब है तथा इस कार्य को लेकर वे दिन-रात प्रखंड कार्यालयों का चक्कर काटने को विवश हो रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

जूनियर दादा भी दंगल में

राजनीति के दंगल में स्व दिग्विजय सिंह के छोटे भाई कुमार त्रिपुरारी सिंह ने सादगी से मगर संभावनाओं से भरी इंट्री देकर सबको चौंका दिया है. जदयू में विधिवत शामिल होकर उन्होंने ऐलान किया कि दादा के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना है. बांका सहित पूरे राज्य की जनता को दादा से जो उम्मीदें थी, उसे नीतीश कुमार के आशीर्वाद से पूरा करने की कोशिश करूंगा. दादा की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए उठाए गए इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

दादा की धर्मपत्नी पुतुल सिंह तो इस काम को बख़ूबी अंजाम दे ही रही हैं, पर उसे और विस्तार देने के लिए कुमार त्रिपुरारी सिंह, जिन्हें लोग प्यार से केटी पुकारते हैं, पूरी तैयारी व दमखम के साथ जुट गए हैं. गोल्फ खेलने के शौकीन व डिजाइनर शर्ट व जीं के दीवाने केटी ने जैसे ही कुर्ता व वंडी पहनी, चर्चा ज़ोर पकड़ने लगी कि नीतीश कुमार की एक युवा राजपूत नेता की तलाश पूरी हो गई. मिलन समारोह में नीतीश कुमार के ख़ासमख़ास सांसद रामचंद्र सिंह व जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह की मौजूदगी जदयू में केटी के शामिल होने की अहमियत को साबित कर रही थी. केटी सक्रिय राजनीति से भले अभी तक दूर थे पर परदे के पीछे दिग्विजय बाबू के तमाम राजनीतिक अभियानों में उनकी अहम भूमिका होती थी. दादा के जाने के बाद उभरी शून्यता को दूर करने के लिए पहले पुतुल सिंह ने बांका से उपचुनाव लड़ने का फ़ैसला किया और अब त्रिपुरारी सिंह दंगल में कूद पड़े हैं. राजनीतिक सूत्रों की बातों पर भरोसा करें तो जदयू को एक साफ़ सुथरे युवा चेहरे की तलाश थी और केटी को पार्टी में लाकर युवाओं को जोड़ने का एक बड़ा अभियान जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. इस अभियान को जदयू के सदस्यता अभियान से भी जोड़ा जा सकता है. बांका तथा आसपास के ज़िलों में त्रिपुरारी सिंह को ज़्यादा सक्रिय किया जाएगा ताकि पार्टी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले.

वशिष्ठ बाबू ने तो साफ़ भी कर दिया कि पार्टी त्रिपुरारी सिंह का बेहतर से बेहतर उपयोग करेगी. जदयू महासचिव छोटू सिंह भी मानते हैं कि त्रिपुरारी सिंह जैसे लोगों के पार्टी में आने से युवाओं में अच्छा संदेश गया है. युवाओं के लिए नीतीश कुमार ने जो सपना देखा है, उसे हम लोग मिलकर हर हाल में पूरा करेंगे .

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

झूठे वादों की मार से बेहाल

चंपारण के ऐतिहासिक स्थल

मनोज कुमार राव

वर्ष 2010 बीत गया और चंपारण के मुद्दे जस के तस रहे. विकास यात्राएं हुईं, नई सरकार का गठन भी हुआ, लेकिन सत्याग्रही भूमि पर मुद्दों का समाधान नहीं हुआ. चंपारण को खास पहचान देने वाले स्थलों का जीर्णोद्धाधार तक नहीं हुआ है.

सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी शहर के बीचों बीच स्थित मोतीझील की. अब तक शायद ही कोई ऐसा ज़िलाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक होगा, जिसने इस झील के जीर्णोद्धार से संबंधित भाषणबाजी न की हो. मामला तीन करोड़ से बढ़कर सौ करोड़ तक पहुंच गया. धरनों और आम सभाओं का आयोजन हुआ, लेकिन सब बेकार साबित हुआ. बहरहाल, मोतीझील का अतिक्रमण जिस तेजी से हो रहा है, वह दिन दूर नहीं जब यह मुद्दा अपने आप ही दम तोड़ देगा. केसरिया स्थित विश्व का सबसे उंचा बौद्ध स्तूप. यहां महोत्सव भी होता है और मंत्री इसके विकास के लिए धन का पिटारा भी खोलते हैं लेकिन पता नहीं, कब यह स्थान बौद्ध सर्किट से जुड़ेगा और कब यहां की सिरकटी मूर्तियां अपने वजूद में वापस लौटेंगी. नीतीश कुमार हों अथवा लालू प्रसाद, सब ने लुभावने वादे किये, लेकिन आज भी मामला जस का तस ही है.

विश्व प्रसिद लेखक जार्ज आरवेल की जन्म स्थली मोतिहारी जो पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है. आज यह अतिक्रमण की शिकार है. यहां के सीप बटन विदेशों में भी चर्चित हैं, लेकिन कभी स्थानीय राजनीति तो कभी ज़िला व राज्य स्तरीय भाषणबाजी के कारण यह उद्योग खोखला हो गया है. संघर्ष समितियां इसके वजूद को जिंदा रखे हैं, लेकिन कब तक रख सकेंगी, कहना मुश्किल है.

अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ मंदिर पूरे राज्य के शिवभक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. इसकी भी हालत खस्ता है. सोमेश्वरनाथ के नाम से यहां कई संस्थाएं कार्यरत हैं, लेकिन किसी भी भवन की भौतिक स्थिति व कार्यरत संस्थाओं की दशा-दिशा ठीक नहीं है. ज़िले के अधिकारी हों अथवा चंपारण आने वाले नेता, सभी इस मंदिर में सिर झुकाते हैं लेकिन इसकी फिक्र किसी को नहीं है. ऐसा ही कुछ हालत सत्याग्रही भूमि की है. पूरे देश में चंपारण की इस सत्याग्रही भूमि के चर्चे हैं, लेकिन यहां बापू की प्रतिमाओं को व इनसे जुड़ी यादों को किस प्रकार सहेजा गया है, इससे यहां की जनता वाकिफ है. पश्चिमी चंपारण का भीतिहरवा आश्रम. यहां से बापू ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी. विशिष्ट लोग आते हैं, फूल चढ़ाकर सभाएं करते हैं और सब्जबाग दिखाकर फुर्र हो जाते हैं.

इसी तरह इस ज़िले की कई ऐतिहासिक धरोहरे हैं जो सिर्फ बयानबाजों के लिए एक मुद्दा बनकर रह गई हैं. नीतीश सरकार की विकास यात्रा इन स्थलों से भी गुजरती है और वादों का अंबार लगा देती है, लेकिन ये वादे कब पूरे होंगे, कब अधिकारियों की घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. बहरहाल, नए वर्ष में चंपारणवासी एक बार फिर से विकास की बाट जोह रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

यहां के ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख के लिए कई संस्थाएं कार्यरत हैं, लेकिन कोई भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही हैं.

एक नज़र इधर भी

सर्वदलीय आंदोलन के प्रतीक थे भाईजी

समस्तीपुर के प्रखर समाजवादी चिंतक एवं पत्रकार स्व. रामजपित राय की दशम स्मृति दिवस पर ज़िले के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधि महाविद्यालय में एकत्रित होकर स्व. राय उर्फ भाईजी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि बीते दस वर्षों में अनेकानेक सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधि लोगों के सामने आए लेकिन स्व. रामजपित राय की मृत्यु से जो रिक्तता जिले में आई, उसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी. विधान पार्षद रोमा भारती ने स्मृति दिवस समारोह में उपस्थित ज़िले के सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि स्व. पिता रामजपित राय के अरमानों के अनुरूप जिले को विकासोन्मुखी स्वरूप देने के लिए उनका तन-मन-धन का सहयोग रहेगा. स्मृति दिवस समारोह में पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी ने कहा कि भाईजी जिले की समस्याओं पर सर्वदलीय आंदोलन के प्रतीक थे. समस्तीपुर के युवा विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहिन ने कहा कि जिले की समस्याओं पर रामजपित बाबू दलगत भावना से उठकर जनांदोलन किया करते थे और उनके नहीं रहने पर जिले में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है.

- चौथी दुनिया ब्यूरो

रिश्वतखोरी का मामला जनता दरबार पहुंचा

इंदिरा आवास में घूसखोरी के आरोप में डुमरिया पंचायत के जितेंद्र बैठा द्वारा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन दिया गया है. इसमें कहा गया है कि विकास मित्र मुकेश कुमार राय के द्वारा 5000 रुपए की मांग की गई है. मुख्यमंत्री जनता दरबार के निर्देश के आलोक में जिलापदाधिकारी के निर्देशानुसार अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार पांडे एवं प्रभारी बीडीओ रइसुद्दीन खां के द्वारा डुमरिया पंचायत जाकर पूछताछ की जाए. इस मामले में पांडे ने बताया गया है कि दिसंबर 2008 से आज तक किसी प्रकार की सलाह नहीं भेजी गई है. वहीं प्रखंड कार्यालय के लगभग सभी पंचायतों में इंदिरा आवास संबंधी घोर अनियमितताएं उजागर हुई हैं. किसी भी पंचायत द्वारा 2008 के बाद आजतक इंदिरा आवास की प्रतिक्षा सूची नहीं दी गई. अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है. उधर विकास मित्र ने पूरे मामले में अपने आप को निर्दोष बताया है.

नहीं खुले धान क्रय केंद्र

संग्रामपुर प्रखंड में सरकारी मूल्य पर धान खरीद का दावा खोखला साबित हो रहा है. रबी की खेती समाप्ति पर है जबकि संग्रामपुर के किसान क्रय केन्द्र खुलने का इंतजार कर रहे हैं. सरकार पैक्स के माध्यम से भी धान की खरीददारी का दावा करती है, लेकिन इस पंचायत में अभी तक एक भी सरकारी एजेंसी द्वारा क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है. प्रगतिशील किसान विनोद सिंह व चंद्र प्रसाद ने बताया कि घरों व खलिहानों में धान रखे हुए हैं, जिनको चूहे खा रहे हैं लेकिन इस बारे में स्थानीय प्रशासन भी मौन है. इस व्यवस्था के कारण स्थानीय व्यापारियों की चांदी कट रही है, क्योंकि मनमाने दाम पर वे किसानों से धान ख़रीद रहे हैं.

- अभय कुमार पांडे

लड़कियों को देंगे बेहतर भविष्य : रंजना

सहयोग शांति की रंजना सिंह ने कहा है कि हमलोग लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हमारी संस्था की कोशिश यही रहती है कि जमुई की लड़कियों को इस तरह तैयार करें ताकि वे जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकें. संस्था में आने वाली लड़कियों के लिए नए साल में बेहतर भविष्य की कामना करते हुए रंजना सिंह ने कहा कि साल 2011 में सहयोग शांति की पूरी कोशिश होगी कि उन्हें हर वह हुनर दिया जाए जिससे उन्हें जिंदगी के सफर में मदद मिले. रंजना सिंह ने संस्था की प्रमुख इशा सिंह और सक्रिय सदस्य मीरा सिंह के योगदान को काफी अहम बताया.

- प्रियंका

मनोज सिंह ठोकेंगे ताल

महनार में पंचायत चुनाव की आहट होते ही सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के जिला परिशद क्षेत्र संख्या 36 से पार्शद पद के लिए युवा लोजपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार सिंह ने ताल ठोंक दी है. पूर्व विधायक रामा सिंह के प्रतिनिधि रहे मनोज कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें अपने कर्म पर पूरा भरोसा है तथा क्षेत्र में उन्होंने जनता की जो सेवा की है, उसका फायदा उन्हें मिलेगा. सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र के जो जिला पार्षद हैं, उन्हें जनता दो-दो बार देख चुकी है. अब जनता यहां बदलाव चाहती है.

- अंजुम परवेज

गुलाबबाग बाजार समिति व्यावसायिक संघ
की ओर से नववर्ष की हार्दिक बधाई

अध्यक्ष
व्यवसायी

हार्दिक शुभकामनाएं
सुनील कुमार
पूर्व मुखिया, बनौली प्रखंड

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

समाज में फैली इस तरह की बुराइयों को समाप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना इनके परिवार के लोगों को नागवार गुजरा.

तपस्या से मिटेगा भ्रष्टाचार!

राजनीतिज्ञों की कारगुज़ारियों से आहत और समाज में आए दिन हो रही लूटपाट, हत्या, डकैती जैसे अपराधों से आजिज़ आकर एक हठी बाबा राजनेताओं के गाल पर करारा तमाचा जड़ते हुए अपनी कठोर तपस्या में लीन है.

राजेश सिन्हा

आज के इस स्वार्थी युग में जहां लोग चंद रुपयों के लिए अपनों का भी कत्ल करने से नहीं चूकते हैं, वहीं एक ऐसा भी शख्स है जो देश से द्वेष, स्वार्थ और भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए कई महीनों से अन्न सहित सभी सुख–सुविधा त्यागकर ईश्वर की अराधना में तल्लीन है. गंगा नदी के बीच निर्जन टापू पर आराधना करता यह साधु न किसी से बात करने को राजी है और न ही किसी का उपहार स्वीकार रहा है. अपनी पहचान किसी को भी न बताने वाले इस हठी बाबा को लेकर लोगों में उनकी इस आराधना का उद्देश्य जानने की इच्छा प्रबल होती जा रही है. इस शख्सियत की ख्याति भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. गंगा नदी का पानी पीकर ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहने वाले हठी बाबा की खबर पाकर जब चौथी दुनिया ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सबसे पहली समस्या यह थी कि हठी बाबा के पास आख़िर पहुंचा कैसे जाए. एक नाविक ने हठी बाबा तक पहुंचाने का वादा यह कहकर किया कि आज तक वह लोग भी बाबा के संदर्भ में जानकारी हासिल नहीं कर सके हैं. इसलिए इस बहाने शायद उनकी भी बाबा से मुलाकात हो जाए. जब वहां पहुंचे तो देखा कि बालू की रेत से शिवलिंग बनाकर आराधना में तल्लीन बाबा सर्वप्रथम कुछ भी बताने को राजी नहीं हुए. काफी विनती करने के बाद वह सभी सवालों का जवाब बोलकर नहीं अपितु लिखकर देने को राजी हुए.

बातचीत के दौरान पता चला कि 22 साल पूर्व जब वह उच्चविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान ही वह समाज में फैले भ्रष्टाचार और समाजविरोधी घटनाओं से इतना आहत हुए कि कठोर तपस्या करने का फैसला कर लिया. समाज में फैली इन बुराइयों को खत्म करने के लिए कठोर तपस्या करना उनके परिवार को नागवार गुजरा. कम उम्र में कठोर तपस्या करते देखकर उनके घरवालों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया. उन्होंने घरवालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब घरवाले उनकी भावना को नहीं समझ पाए तब वह बिहार के पूर्णिया ज़िला अंतर्गत बड़हरा कोठी स्थित घरबार छोड़कर वृदांवन चले गए और विकृत हो चुके समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए ईश्वर की तपस्या में लीन हो गए. हालांकि, वह इस आराधना का मूल उद्देश्य जनता को समझा पाने में फिलवक्त खुद असमर्थ बताते हैं. बाबा के लिखे अनुसार उनके गुरू की मौत के बाद वह जगह बदल–बदलकर कठोर आराधना में लग गए. रामानंद संत आश्रम ऋशिकेश, उत्तराचंल, हनुमान टेकरी, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, हरिहरउदासीन आश्रम, कमला मार्केट नई दिल्ली सहित दस राज्यों का भ्रमण करने के बाद उन्होंने यह फैसला किया कि गंगा नदी के तट पर अराधना की जाए. इसी सोच के तहत वह गंगा नदी तट पर रहकर घोर तपस्या में लीन हो गए. नदी पार करने के दौरान उनके आस–पास इतनी भीड़ लगने लगी कि वह परेशानी महसूस करने लगे. बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से वह इस टापू पर चले आए. जब तक तपस्या पूरी नहीं होगी तब तक वह लोगों से बात करने से भी परहेज करेंगे. उनकी यह कब तक पूरी होगी जैसे सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि जब तक समाज से इस तरह की विकृतियां दूर नहीं होगी, तब तक उन्होंने तपस्या करते रहने की कसम खाई है.

हिंदुस्तान की राजनीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि वर्तमान परिवेश की राजनीति को अगर स्वार्थ की राजनीति कहा जाए तो गलत नहीं होगा. अपना नाम तक बताने से परहेज करने वाले हठी बाबा ने कहा कि वह अखबार या निजी चैनल से इसलिए दूर भागते हैं, क्योंकि मीडिया भ्रष्ट और स्वार्थी नेताओं को न केवल तवज्जो देता है बल्कि समाज की मूल समस्याओं को पटल पर लाना जरूरी नहीं समझता. बाबा के मुताबिक़ वास्तविक राजीनति गांधी के जमाने में होती थी. एक ही कंबल पर बैठकर सभी नेता देशहित की बात सोचते थे. आज असेंबली के रखरखाव तथा नेताओं की सुख–सुविधा के नाम पर करोड़ो रुपये बहाए जाते हैं और गरीब लोग भूख से मरते हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की राजनीति कितनी भ्रष्ट हो चुकी है. उन्होंने आम जन मानस को यह संदेश दिया कि अपना सभी काम करते हुए अपने ईष्ट का खूब पूजन करें. क्योंकि रसातल में जा रहे समाज को ईश्वर ही बचा सकते हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसा कोई भी काम आम अवाम को नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे या व्यक्तिगत, सामाजिक या देशहित का नुकसान हो. हिंदुत्व और आराधना पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि हमारे देश में हिंदुओं का सनातन धर्म पहले से प्रसिद्ध रहा है. भारतवर्ष में अनेकानेक देवी देवता हैं. श्रीराम और श्रीशिव का महापूजन पहले से इसलिए होते आया है, क्योंकि दोनों देवता प्रमुख हैं. दानव रावण का

भी वध श्रीराम ने ही किया था. भ्रष्टाचार रूपी रावण अर्थात बहरूपिए नेताओं का वध भी श्रीराम की अराधना से ही संभव है. उधर आस–पास गांव के विजय यादव तथा सुमित कुमार ने बताया कि लगभग चार माह से अन्न सहित अन्य सुख सुविधाओं का त्यागकर ईश्वर की अराधना करने वाले बाबा को देखने के लिए लोग लालायित होने लगे हैं, लेकिन बाबा किसी से भी मिलने से इंकार कर देते हैं. छड्डापट्टी निवासी विलास यादव कहते हैं कि आज तक उन लोगों ने ऋषिमुनियों द्वारा इस तरह की कठोर तपस्या करते सुना था, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है.

नीलेश कुमार के मुताबिक कई माह पूर्व जब बाबा को इस तरह कठोर तपस्या करते देखा तो लगा कि शायद बाबा ईश्वर की आराधना करते–करते जान गंवाने की ठान चुके हैं. लेकिन अन्न त्यागने के बाद भी बाबा के शारीरिक ढांचे में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आना, इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं ईश्वर भी उनके साथ है. अंगद यादव ने सुलगता हुआ सवाल किया कि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके समाज में क्या इस तरह की तपस्या से बदलाव संभव है! बहरहाल, इस हठी बाबा की कठोर तपस्या से भ्रष्टचारमुक्त समाज का निर्माण संभव हो सकेगा! हत्या, लूट और अन्य तरह के अपराध पर काबू पाया जा सकेगा! क्या भ्रष्ट हो चुकी राजनीति पटरी पर आ सकेगी, यह तो फिलवक्त कह पाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, लेकिन इस सन्यासी ने इस तरह की कठोर तपस्या की शुरुआत कर देश के उन स्वार्थी और भ्रष्ट नेताओं के गाल पर करारा तमाचा तो जड़ ही दिया है जो अपने स्वार्थ के लिए न केवल देश को खोखला करने में लगे हैं, बल्कि सरकारी धन को लूटने पर अमादा हैं. देश की जनता कराह रही है. इस हठी बाबा की तपस्या की जानकारी मिलने के बाद भी अगर ऐसे नेताओं का ज़मीर नहीं जागेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे इन नेताओं ने देश को रसातल तक पहुंचाने की कसम खा ली है, जबकि दूसरी ओर हठी बाबा विकृत समाज के चेहरे को सौम्य बनाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हैं. देखते हैं कि उनका यह प्रयास कितना सफल होगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

दिल्ली, 10 जनवरी-16 जनवरी 2011
www.chauthiduniya.com

पंचायत चुनाव

बसपा जीती लोकतंत्र हारा

उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए स्थानीय चुनावों में लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उस समय उड़ाई गईं, जब पूरे देश में ग्रामसभा वर्ष चल रहा था. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 को ग्रामसभा वर्ष घोषित किया गया था. लेकिन ग्रामसभा वर्ष घोषित करने वाली केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में लोकतांत्रिक मूल्यों की खुलेआम अवहेलना पर कोई ध्यान नहीं दिया.

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

प्रभात रंजन दीन

- **हाईकोर्ट का निर्देश, पंचायत चुनाव आतंक रहित हों.**
- **बसपा ने हाईकोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई.**
- **पंचायत से ब्लॉकों तक 70-80 फ़ीसदी सीटों पर बसपा का क़ब्ज़ा.**
- **पंचायत सदस्यों का वोट 25 से 50 लाख रुपये तक में बिका.**

ज़िला पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के जो चुनाव हुए, उनमें यह साबित हुआ कि सत्ताधारी पार्टी अगर चाहे तो किसी भी हद तक जाकर और किसी भी स्तर तक उतर कर ग्रासरूट तक अपना नेटवर्क स्थापित कर सकती है. बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में यही किया. साम-दाम-दंड-भेद का इस्तेमाल कर प्रदेश भर में बसपा ने पहले ज़िला पंचायत अध्यक्षों और फिर ब्लॉक प्रमुखों का जो जाल बिछाया, वह बहुजन समाज पार्टी के लिए एक उपलब्धि है, भले ही इसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हों. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सत्ताधारी पार्टी के अलोकतांत्रिक रवैये को देखते-भांपते हुए ही चुनाव के पहले यह सख्त निर्देश जारी किया था कि ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव आतंक रहित हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव आतंक सहित हुए और हाईकोर्ट के आदेशों की हमेशा की तरह बसपा ने ऐसी-तैसी करके रख दी. चुनाव में हत्या से लेकर अन्य सभी किस्म के अपराध हुए और अधिकतर अपराधों का दोष बसपा के खाते में ही रहा.

ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में हुए अपहरण और आतंक के आधिकारिक आंकड़े देखें तो बसपा का सत्ताई आतंक जाहिर होता है. समाज से सीधे प्राप्त हुईं सूचनाएं तो भीषण निरंकुश सत्ताई उत्पात उजागर करती हैं. लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ने दूसरे दलों को अपने आधारभूत लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने से भी रोका. जिस जगह भी दूसरी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख ताकतवर होता दिखा, वहां पुलिस ने बसपाई कॉडर की तरह काम और तांडव किया. बुलंदशहर में डिबाई के बसपा विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित ने जहांगीराबाद ब्लॉक के 14 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अगवा कर लिया. दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के कुंडा में समाजवादी पार्टी के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ़ राजा भैया को बसपा उम्मीदवार को डराने-धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. राजा भैया अपने पुराने ख्याति नाम की वजह से पकड़े गए. कई जगह तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मारे भी गए और सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए. वाराणसी के निकट अतरौलिया में बसपा की मुख़ालफ़त करने वाले राम अवध की हत्या हुई. हालत यह रही कि विधानसभा चुनावों के दरम्यान भी हिंसा मुक्त रहने वाले उत्तर प्रदेश में पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में ख़ूब हिंसा हुई और एक महिला समेत चार लोग अलग से मारे गए. दर्जनों जख्मी हुए. सरकारी गाड़ियां फूंकी गईं. मुजफ्फर नगर के जहानपुर इलाक़े में एक व्यक्ति मारा गया तो फिरोज़ाबाद के सेंगरी गांव में गुड्डी देवी नामक महिला मारी गई. जौनपुर के खेतपुर गांव में मजिस्ट्रेट की जीप फूंक डाली गई. विडंबना यह रही कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ता जिन मामलों में गिरफ्तार किए गए, वही अपराध करने वाले बसपाई अपनी पार्टी को मजबूत करने वाले कार्यकर्ता माने गए. रघुराज प्रताप सिंह के साथ कौशांबी के सांसद शैलेंद्र कुमार, बिहार (प्रतापगढ़) के विधायक विनोद कुमार सरोज और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह जिस मामले में गिरफ्तार किए गए, उसी मामले में बसपा के जिन नेताओं को अभियुक्त बनाया गया था, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों की लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाशीलता की असलियत का भी सार्वजनिकीकरण किया. समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी भी दल ने बसपाई आतंक के ख़िलाफ़ लोकतांत्रिक प्रतिरोध जताने का कोई लोकधर्म निभाने की भी ज़रूरत नहीं समझी. समाजवादी पार्टी ने भी राजा भैया की गिरफ्तारी के विरोध में राज्यव्यापी एक दिवसीय प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित कर अपना लोकतांत्रिक धर्म निभा लिया. ज़िला पंचायत सदस्यों से लेकर ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव तक की पूरी प्रक्रिया पर ग़ौर करें तो आप यह पाएंगे कि सत्ताधारी बसपा से लेकर बड़ी विपक्षी पार्टियां तक सब एक ही जुगत में थीं कि कैसे सीटों पर क़ब्ज़ा मिले. यह पूरा चुनाव दरअसल अवसरवादी चुनाव साबित हुआ. सारे दल एक ही प्रयास में थे. सत्ताधारी दल से लेकर प्रमुख विपक्षी दल तक ज़िला पंचायतों से लेकर ब्लॉक प्रमुखों तक अपने लोगों को बैठाने का प्रयास कर रहे थे. सभी दलों ने सारे रास्ते अख्तियार किए, लेकिन बसपा सबमें अव्वल रही, क्योंकि सत्ता उसके पास थी और लोकतांत्रिक भय से उसका कभी का वास्ता नहीं. ज़िला पंचायत अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुखों तक का चुनाव सरकारी आतंक के बीच ही संपन्न हुआ. पूरी सत्ता, पूरा प्रशासन और समस्त बसपाई कॉडर मिलकर पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर क़ब्ज़ा जमाने में लगा रहा. इसके लिए डराने, धमकाने, पिटवाने, गिरफ्तार और अपहरण कराने से लेकर हत्या और वोट ख़रीदने तक के तौर-तरीक़े अख्तियार किए गए. पंचायत से लेकर ब्लॉकों तक 70 से 80 फ़ीसदी सीटों पर बसपा ने क़ब्ज़ा कर लिया. लोकतंत्र ख़त्म कर बाहुतंत्र और धनतंत्र का इस्तेमाल करके आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा फिर से अपनी तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने का प्रयास कर रही है.

ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में हुए अपहरण और आतंक के आधिकारिक आंकड़े देखें तो बसपा का सत्ताई आतंक जाहिर होता है. समाज से सीधे प्राप्त हुईं सूचनाएं तो भीषण निरंकुश सत्ताई उत्पात उजागर करती हैं. लेकिन दूसरी तरफ़ सत्ताधारी दल ने दूसरे दलों को अपने आधारभूत लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने से भी रोका. जिस जगह भी दूसरी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख ताकतवर होता दिखा, वहां पुलिस ने बसपाई कैडर की तरह काम और तांडव किया.

ज़िला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की सीटों पर क़ब्ज़े की रणनीति बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सोच-समझ कर तैयार की थी. मुख्यमंत्री मायावती और उनके ख़ास नौकरशाहों ने रणनीति तैयार करने से लेकर उसे ज़मीनी स्तर तक लागू कराने की रूपरेखा तैयार की और उसी तरह पूरे प्रशासन तंत्र को चौकस किया गया. विशेषज्ञ बताते हैं कि ज़िला पंचायतों और ब्लॉक प्रमुखों की अधिकांश सीटों पर क़ब्ज़ा कर पंचायतों और ब्लॉकों तक जाने वाले विकास के सरकारी धन का इस्तेमाल बसपा अपनी पार्टी के कैडर-बिल्डिंग में लगाएगी. यह रणनीति आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई और इसमें अन्य विपक्षी दल पूरी तरह नाक़ाम हो गए. कुछ छोटे दलों ने बसपाई आतंक का विरोध भी किया और ऐसे कुछ दलों के प्रत्याशी सरकारी आतंक या धन के प्रलोभन के आगे झुके भी नहीं, लेकिन ऐसे छोटे दलों द्वारा विरोध की आवाज़ नक्कारखाने में तूती की आवाज़ ही साबित हुई. एक-एक ज़िला पंचायत सदस्य का वोट 25 से 50 लाख रुपये तक में ख़रीदा गया. ख़रीद-बिक्री का खेल खुलेआम हुआ और यह साबित हुआ कि हाईकोर्ट या चुनाव आयोग सब दिखावटी औपचारिकता मात्र हैं. चुनाव आयोग में इतनी भी हिम्मत नहीं कि वह राजनीतिक दलों से आधिकारिक तौर पर यह जवाब-तलब कर सके कि पंचायत और ब्लॉकों के चुनाव जब दलीय नहीं लड़े गए, तो फिर ज़िला पंचायत अध्यक्षों या ब्लॉक प्रमुखों पर राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी के क्या मायने हैं. अब पंचायत चुनावों में भी बिहार ही नजीर पेश करने वाला है, जहां पंचायत चुनावों को दलीय स्तर पर कराने का क़ानूनी प्रावधान करने की विधाई कोशिशें शुरू हो रही हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ़ से यह पहल हो रही है और बिहार में लागू होने के बाद यह उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी उदाहरण के बतौर पेश होगी और फिर उसे लागू करने के प्रयास होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

नदियों के किनारे बसे तमाम गांवों की सैकड़ों बीघा कृषि योग्य भूमि नदी में कटकर रेत के ढ़ेर में तब्दील हो चुकी है.

गंगा की दुर्दशा पर साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष जयराम ब्रह्मचारी ने प्रशासन एवं सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को अविरल गंगा जल उपलब्ध कराने की मांग की.

हरीश रावत के बयान पर बिफरे निशंक

राजकुमार शर्मा

मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार रोल बैक करने के कारण उनकी जनता जनार्दन में भी ख़ासी किरकिरी हो रही है. इस गिरती साख को संवारने में अपने को असफ़ल पा रहे मुख्यमंत्री अब कई अवसरों पर अपना आपा खो रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अपना गढ़ भी नहीं बचा सकी सपा

कालेश्वर सिंह

हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में सपा को अपने ही गढ़ में अपनों से ही शिकस्त मिली है. जहां पूर्व चुनावों में पार्टी ने तीन फ़ीसदी से अधिक सीटों पर ज़िला पंचायत अध्यक्ष का परचम लहराया था. वहीं अब पार्टी थोड़ी सी सीटों पर काबिज़ होकर रह गई है. इसका असर सबसे ज़्यादा सपा के गढ़ में ही देखने को मिला है. सपा ने इसकी वजह सरकारी तंत्र द्वारा धन-बल से पंचायत चुनाव के सदस्यों की ख़रीद-फरोख्त कर अधिक से अधिक ज़िला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों के पदों पर क़ब्ज़े का बसपा सरकार पर आरोप लगाया है. चुनाव नतीजों से स्पष्ट होता है कि कहीं न कही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है. जिससे चुनावों के नतीजों से बसपा के कृत्यों का विरोधी पार्टी सपा, भाजपा, काग्रेंस, रालोद ने जमकर आलोचना भी की है. सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में फिरोज़ाबाद व कन्नौज दोनों सीटों से चुनाव जीता था, जिसमें फिरोज़ाबाद से इस्तीफ़ा देकर कन्नौज पुरानी सीट बरकरार रखी थी. फिरोजाबाद की जनता ने इसका जबाब उनकी पत्नी डिंपल यादव की हार से चुकता किया.

एक समय था जब आगरा मंडल में सपा का दबदबा था. वर्ष 2004 के लोकसभा के आम चुनाव में एटा जलेसर, आगरा फिरोज़ाबाद मैनपुरी से सपा सांसद चुने गये थे. वर्ष 2009 केलोकसभा के चुनाव में नये परिसीमन के आधार पर चुनाव संपन्न हुआ. जिसमें एटा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, आगरा व फतेहपुर सीकरी में से सिर्फ़ 3 ही सीट सपा के खाते में आई. जिसमें एटा की सीट पर समर्थित प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह विजयी हुए थे. सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह चुनाव कन्नौज और फिरोज़ाबाद सीटों पर लड़ा था. इन दोनों सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी. बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने फिरोज़ाबाद सीट से इस्तीफ़ा दे दिया, खाली हुई सीट पर दुबारा चुनाव हुआ जिसमें सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव ने अपनी पुत्र वधू डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा. इधर सपा के दोनों बाग़ी प्रत्याशी राजबब्बर काग्रेंस और प्रो एसपी सिंह बघेल को बसपा से टिकट मिल गई. त्रिकोणीय मुक़ाबले में गेंद काग्रेंस के राजबब्बर के पाले में चली गई. पिछले चुनाव में सपा ने लगभग 80 हज़ार मतों से इस सीट पर क़ब्ज़ा किया था. इसी को आधार मानकर सपा अपनी जीत सुनिश्चित मान रही थी. लेकिन जनता ने ताज कांग्रेस प्रत्याशी राजबब्बर के सिर लगाया. उस वक्त सपा मुखिया ने इस हार को पार्टी की आपसी कलह बताया था. उसके बाद पार्टी ने हार पर मंथन भी शुरू किया जिसका नतीजा फिर वहीं रहा जो पिछले लोकसभा केचुनाव में रहा. इसके बाद हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में इसका ख़ामियाजा पार्टी को फिर भुगतना पड़ा. पूरे जनपद में 28 ज़िला पंचायत सदस्यों में से 12 सपा समर्थित सदस्य थे, जिनमें से चुनाव के दौरान सिर्फ़ सपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक रमेश चंचल को सिर्फ़ 8 मत ही मिले. जबकि बसपा प्रत्याशी प्रमोद कुमार को 20 मत मिले. इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिकोहाबाद केपूर्व विधायक हरिओम यादव को पार्टी विरोधी क्रियाकलापों का दोषी मानते हुए बाहर का रास्ता दिखाया. पूर्व विधायक के साथ शिकोहाबाद चेयरमैन रघुवर दयाल गुप्ता व एक दर्जन से अधिक सभासदों ने सपा से इस्तीफ़ा

...पार्टी में गुटबंदी के चलते घमासान मचा हुआ है. वहां के स्थानीय ज़िलाध्यक्ष अजीम भाई एवं अन्य नेताओं का मानना है कि गद्दारों के निकलने से ... आएगी. सपा नेता डा दिलीप यादव का कहना है कि ज़िला पंचायत ... अपनों की ग़लती से भी हार हुई है साथ ही पुलिस प्रशासन के दबाव से ... बसपा को वोट किया है. फिरोज़ाबाद और कन्नौज दोनों जगहों से ... अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी. उन दोनों सीटों पर वर्तमान समय ... पंचायत अध्यक्ष का क़ब्ज़ा हुआ है. जिससे प्रदेश अध्यक्ष की हैरानी बढ़ ...

कन्नौज में कुल 23 ज़िला पंचायत सदस्यों की संख्या थी, जिसमें सब ... सदस्य सपा के थे, तथा दूसरे नंबर पर बसपा व तीसरे स्थान पर भाजपा ... कर आए थे. फिर भी सपा ज़िला पंचायत अध्यक्ष न बना सकी. ज़िला ...

feedback@chauthiduniya.com

भागीरथी में कम होता जल प्रवाह

देवभूमि हरिद्वार में गंगा का अभी से बुरा हाल हो गया है. गंगा की अविछिन्न आपूर्ति धारा में गंगाजल का प्रवाह न होने से धर्म नगरी में श्रद्धालुओं द्वारा बनाए गये दर्जन भर से अधिक घाट अभी से जलविहीन हो गये है. जिससे हरिद्वार के श्मशान घाट पर भी जल का प्रवाह नही हो रहा है, इससे नाराज़ हरिद्वार के संतों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए गंगा के भागीरथ बिंदू पर धरना दिया. धरना देने वाले दर्जन भर से अधिक कद्दावर संतों ने सरकार एवं प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पंद्रह दिन के भीतर गंगा तट की सफ़ाई करा कर घाटों पर जल नहीं पहुंचाया गया तो संत समाज गंगा की अविरलता के लिए कार सेवा कर मलबा हटा कर घाटों की रौनक लौटाएंगे.

गंगा की दुर्दशा पर साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष जयराम संस्थाओं के संस्थाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने प्रशासन एवं सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को अविरल गंगा जल उपलब्ध कराने की मांग की, इस अवसर पर धरना स्थल पर गंगा की दुर्दशा के लिए रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज ने ज़िला प्रशासन को जम कर कोसा और कहा कि हरिद्वार में प्रतिष्ठीत घाटों पर गंगा जल की उपलब्धता न होने के कारण जन आस्था के चर्चित घाट दुर्दशा पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर गए है, जिसके लिए ज़िला प्रशासन की भूमिका निंदनीय है. धरना कार्यक्रम के संयोजक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने निशंक सरकार के शहरी विकासमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मंत्री की ग़लत नीतियों के चलते अफसर शाही हरिद्वार में गंगा के सफ़ाई के नाम पर छल कर रहे है. इस अवसर पर चर्चित संत हठयोगी बाबा ने गंगा की अविरलता एंव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना हर योगदान देने की बात कही. हरिद्वार स्थित समभाव आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी प्रेमानंद महाराज ने गंगा की हरिद्वार में इस कदर हो रही दुर्दशा पर गहरी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि भागीरथ बिंदु से जल का प्रवाह न रहने से हरिद्वार में गंगा का स्वरूप ही नही दिखाई दे रहा है. गगां की बेकदरी और दुर्दशा पर परमार्थ आश्रम के अध्यक्ष पूर्व गृहराज्य मंत्री चिन्मयानंद ने गहरी चिंता व्यक्त कर गंगा की अविरलता के प्रति अपनी प्रतिवद्धता को दुहराया. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अखाड़ा परिषद, भारत साधु समाज, और संत समिति के लोगों ने धरना दिया.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

कानपुर से शुरू हुआ ग्राम-स्वराज लाने का काम

अरविंद त्रिपाठी

नवंबर का बीता महीना लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कई घटनाओं का साक्षी बना. म्यांमार में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संघर्ष करने वाली आंग सांग सू नाम की महिला को स्थानीय सैनिक सरकार की नज़रबंदी से मुक्ति मिली. बिहार में नितीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही देश के राजनैतिक रूप से प्रौढ़ होने ...

ग्राम-पंचायतों में भी हावी रिश्तेदारी

समाज की झांकी प्रधानों में भी झलकी

काबेंट नेशनल पार्क

धनवानों की थाप पर नाच रहे हैं वनाधिकारी

विश्वप्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा पर बने होटल रिसार्ट में वन एवं वन्य क़ानून की तमाम पाबंदियों को तार-तार कर जंगल में मंगल मनाने वाले धनवानों का जमावड़ा लगा हुआ है. धनवानों के धन की थाप पर वनाधिकारी नाच रहे हैं, और यह सब कुछ इस नेशनल पार्क में क्रिसमस के दिन से न्यू ईयर तक होगा. टाइगर रिजर्व की सीमा से मात्र आठ किलोमीटर की दूरी में वन विभाग के अतिथि गृह को इस अवसर पर मेहमानवाज़ी के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है. नियम क़ानून को धत्ता बता कर जंगल में मंगल मनाने वालों की लक्जरी वाहनों के साथ की मौजूदगी ख़ुद ब ख़ुद सारा पोल खोल रही है कि इस इलाक़े में तैनात वनाधिकारी, पर्यावरण से जुड़े अधिकारी सभी इस जश्न के लिए आंख बंद किए बैठे हैं.

प्रतिबंधित वन क्षेत्र जो कोटद्वार से बाइस किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग का अतिथि गृह है, इससे लगा जंगल वन्य जीवों के लिए विख्यात है, यहां जाने के लिए दूर्गम मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, पच्चीस दिसंबर से ही जंगल में धूम-धड़ाम की कार्यवाही शुरू हो गई और इसका दौर एक जनवरी तक चलेगा. वन विभाग के अतिथि गृह में इस जश्न के आयोजकों व इनके कर्मियों के अलावा किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नही है. इसके चारों ओर काले कनातों से सब कबर्ड करके रखा गया है. इसके अंदर शानदार व्हाइट हट्स मेहमानों के लिए तैयार किए गए है, आयोजकों ने इस परिसर में अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात कर रखी है. तीन अतिथि गृह के तीन सुईट तीन जनवरी तक के लिए तीन अलग-अलग लोगों के नाम बुक किए गए हैं. इन वन क्षेत्र में रात के अंधेरे में कौन सा जश्न कौन लोग मनाएंगे यह तो अभी नहीं कहा जा सकता. जंगल में बढ़ रहे मानवीय दख़ल का परिणाम यह है कि जब धन के मद में चूर मानव जंगली जानवरों की माद में धमाल मचाने पहुंच रहा है, वन्य जीव भी इस धमाल से तंग आकर मानव बस्तियों का रूख कर रहा है. भारत सरकार ने इस वर्ष को टाइगर संरक्षण वर्ष घोषित कर रखा है. उत्तराखंड सरकार की इस तरफ़ से लापरवाही और वनाधिकारियों के मिली भगत से जश्न मनाने के नाम पर जंगल में जंगली जीवों के

अमंगल का खेल खेला जा रहा है. प्रशासन ने दावा किया है कि पहली बार कार्बेट से लगे होटल-रिसार्ट की निगरानी की जा रही है, मानवीय शोर से वन्य जीवों को बचाने के लिए शोर को मापने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यंत्र लगाया है. असलियत यह है कि सब कुछ निगरानी काग़ज़ी खानापूर्ति के तौर पर की जा रही है.

वन विभाग के इस अतिथि गृह में किसने महफिल सजाने की छूट दी है, इस सवाल पर वनाधिकारी बगले झांकते नज़र आते है. वन के शांत वादियों में शराब-शबाब की होने वाली दावत इस क्षेत्र के जन जन के मुंह सुनी जा सकती है. इस खेल में सफ़ेद पोश लोगों की संलिप्तता के कारण पुरे मामले को चर्चा में होने के बावजूद इसे रोक कर वन्यजीवों को इनकी चैन, नींद वापस करने का सामर्थ्य किसी में नही दिख रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बाढ़ ने किया किसानों को बेघर

सरकार दावा करती है कि वह किसानों की हमदर्द है और उसके हितों की रक्षा करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत देखकर सरकार की यह दावा ग़लत ही साबित होती है. ख़ासकर मिर्ज़ापुर ज़िले के किसानों की हालत दिनोंदिन बद से बदतर होती जा रही है. यहां के किसानों की हालत भुखों मरने की है. यहां के युवा किसान इस तरह हिम्मत हार चुके है कि अपना खानदानी पेशा छोड़ कर अब रोजगार कि तलाश में शहरों की ख़ाक छान रहें हैं. शहरों की तरफ पलायन कर रहे इन युवा किसानों के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, जिससे वो अपने पुस्तैनी धंधे को बचा सके.

यहां प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ ने यहां के किसानों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है. कलान मिर्ज़ापुर क्षेत्र चार नदियों गंगा, रामगंगा, बहगुल एवं सोतचार नाम की चार नदियों से घिरा है. इस क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ फ़सल प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ नष्ट कर देती है. खेती पर पूरी तरह से निर्भर यहां के किसानों के लिए जीविकोपार्जन की समस्या बड़े पैमाने पर उभरती है. खरीफ़ फ़सल की बर्बादी से जुझ रहे किसान रबी कि बुवाई का ख़र्चा भला किस तरह उठाए. यहां दोआब क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ यहां की कृषि के लिए विकट समस्या है. बाढ़ फ़सलों को नष्ट तो करती ही है साथ ही उपजाऊ भूमि के उपर रेत की मोटी परत बिछा देती है. जिससे बड़े-बड़े किसान भूमिहीन होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं. नदियों के किनारे बसे तमाम गांवों की सैकड़ों बीघा कृषि योग्य भूमि नदी में कटकर रेत के ढ़ेर में तब्दील हो चुकी है. यहां आने वाली बाढ़ कभी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर ले आती है जिससे पैदावार अच्छी हो जाती है, तो कभी अपने साथ रेत लेकर आती है जिससे किसान कोई भी फ़सल नहीं उगा पाते. तब यहां के किसान जीवन यापन के लिए छोटे मोटे उद्योग धंधे से लेकर मजदूरी की तरफ़ भी रूख करते है. पर उसमें भी समस्या यह है काम मिलता नहीं और अगर मिल जाता है तो पूरा पूरा समय उन्हें देना पड़ता है जिससे वो कृषि कार्य को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते, ऐसे में वो कृषि से बिलकुल ही कट जाते है.

यहां के किसान बाढ़ से सुरक्षा के लिए प्रशासन के सामने कई बार गुहार लगा चुके हैं, धरना दे चुकेहै. पर आज तक किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी. सोचने वाली बात यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है. पर हमारी सरकार चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इस तरफ़ से उदासीन बनी बैठी है.

प्रियंका प्रियम तिवारी
priyankapriyamtiwari@chauthiduniya.com